देश में ऑनलाइन लूडो के बढ़ते खतरे पर कैसे लगेगी लगाम 4

भारतीय सिनेमा में पुरुषों का दबदबा बहुत ज्यादा : सामंथा 7

योगी के जनता दर्शन में पहुंचे अन्य राज्यों के भी फरियादी 8

तिथि-बैशाख, शुक्ल, दशमीं

सोना - 1,00,085

शेयर मार्केट- 80,641

चांदी- 96,900

निफ्टी- 24,379

अधिकतम -36 °c
न्यूनतम -27 °c

लखनऊ से प्रकाशित एवं उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से एक साथ प्रचारित

चर्चित राजनीति

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

-: सर्वाधिक लोकप्रिय समाचार पत्र :-

www.charchitrajnit.com वर्ष - 21 अंक-163 आर.एन.आई. नं.- UPHIN/2004/14385 लखनऊ, बुधवार 7 मई, 2025 पृष्ठ-8 मूल्य : दो रुपये

योगी कैबिनेट ने 11 प्रस्तावों को दी मंजूरी

यूपी के हर जिले में बनेगी स्मार्ट पार्किंग, तबादला नीति स्वीकृत

चर्चित राजनीति। ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्ताव पर कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। इसमें स्मार्ट पार्किंग को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ।

उत्तर प्रदेश के हर जिले में स्मार्ट पार्किंग बनेगी। इसके अलावा यूपी स्टेज कैरेज बस टर्मिनल, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और आल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना और विनियमन) नीति 2025 को मंजूरी दे दी। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में निजी बस अड्डे खोले जा सकेंगे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में लगातार बढ़ते सड़क सम्पर्क और मूलभूत ढांचे के विकास के साथ-साथ बसों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उनकी पार्किंग के लिये होने वाली समस्या और आवश्यकता को देखते हुए आज एक विशेष नीति को मंजूरी दी गई है। इसमें विशेष रूप से निजी भागीदारी के माध्यम से यह व्यवस्था की जा रही है कि दो एकड़ जमीन पर निजी बस स्टैंड की व्यवस्था की जाए।

उन्होंने बताया कि नई नीति के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जो स्टेज कैरेज बस टर्मिनलों, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पार्कों और आल इंडिया टूरिस्ट बस पार्कों की स्थापना के लिये आवेदन आमंत्रित करेगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि नियामक प्राधिकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक या आयुक्त क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी, नगर आयुक्त या विकास प्राधिकरण के सचिव, नगर पालिकाध्नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी, संबंधित उप मंडल मजिस्ट्रेट, पुलिस के क्षेत्राधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता और अध्यक्ष द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत बस टर्मिनल या पार्क स्थापित करने की पात्रता के लिए आवेदक के पास कम से कम दो एकड़ जमीन, कम से कम 50 लाख रुपये की शुद्ध संपत्ति और पिछले वित्तीय वर्ष में दो करोड़ रुपये का कारोबार होना चाहिए। वित्त मंत्री ने बताया कि नीति में आवेदक द्वारा स्थापित किए जा सकने वाले टर्मिनलों की संख्या को राज्य भर में 10 से अधिक नहीं, एक जिले में दो से अधिक नहीं और एक ही मार्ग पर एक से अधिक नहीं रखा जा सकता है। निजी संस्थाओं को 10 वर्ष की अवधि के लिए परिचालन अधिकार दिए जाएंगे और संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण की संभावना होगी।

- सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक

एक ही जिले में 3 साल से जमे अधिकारी, कर्मचारी हटेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अधिकारियों व कर्मचारियों की वर्ष 2025-26 की स्थानांतरण नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस नीति के तहत एक ही जिले में तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात समूह क व ख के अधिकारियों व कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। एक ही मंडल में सात वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने वालों को भी दूसरे मंडल भेजा जाएगा। तबादले 15 मई से 15 जून तक किए जाएंगे। लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव पास किए गए। बैठक के बाद स्थानांतरण नीति की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि समूह क एवं (शेष पृष्ठ 7 पर)

अदाणी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदेगी यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2034 तक राज्य की बिजली संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये अदाणी पावर लिमिटेड से 1,500 मेगावाट बिजली खरीदेगी। राज्य मंत्रिमण्डल ने मंगलवार को इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने मंगलवार को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से 2 गुणा 800 मेगावाट (1,600 मेगावाट) ताप बिजली परियोजना से 1,500 मेगावाट बिजली खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में हुई निविदा प्रक्रिया में अदाणी पावर लिमिटेड को सफल निविदाकर्ता घोषित (शेष पृष्ठ 7 पर)

उन्होंने बताया कि ऐसे बस अड्डों का स्वामित्व किसी अन्य कानूनी संस्था को हस्तांतरित किया जा सकता है, लेकिन वह पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से एक (शेष पृष्ठ 7 पर)

ग्लोबल सेवा का हब बनेगा उत्तर प्रदेश

चर्चित राजनीति। ब्यूरो

लखनऊ। योगी सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ष्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी नीतिष् को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नीति का मकसद यूपी को भारत का अगला वैश्विक सेवा केंद्र बनाना है।

प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचाना है। नई नीति के तहत यूपी में आईटी, बैंकिंग, हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग और अगली पीढ़ी की तकनीकों में काम करने वाली वैश्विक कंपनियों को बड़े पैमाने पर निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। इससे न केवल रोजगार के लाखों अवसर खुलेंगे, बल्कि प्रदेश के टियर-2 शहरों में भी आर्थिक गतिविधियों में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई।नीति के संबंध में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश में साइंस, लॉ, इंजीनियरिंग समेत बहुत सारे सेक्टर्स का टैलेंट काफी बड़ी मात्रा में मौजूद है। कम पैसे में बेहतर क्वालिटी का काम लेने के लिए कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपने ऑफ शोर डेवलपमेंट सेंटर्स यहीं पर स्थापित कर रही हैं। इसे ही ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर कहते हैं। इसमें पहले नंबर पर सॉफ्टवेयर और आईटी आता है, जिसमें मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक प्रॉसेस ऑटोमेशन, एआई संचालित (शेष पृष्ठ 7 पर)

भारत के हक का पानी भारत के ही काम आएगा

चर्चित राजनीति। एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी चैनल की India@2047 समिट में वक्फ कानून से लेकर पाकिस्तान को पानी दिए जाने तक हर विषय पर अपनी बात रखी। प्रधानमन्त्री मोदी ने कहा कि बदलते हुए भारत का सपना है 2047 तक विकसित भारत। पीएम मोदी ने समिट में भारत-ब्रिटेन ट्रेड डील के बारे में भी जानकारी दी। समिट की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह समिट विविधता से भरी हुई है। युवाओं और महिलाओं की उपस्थिति इस समिट की USP बन गई है। ये बदलते भारत का प्रतिबिंब है जो हर क्षेत्र में भारत का आवाज बुलंद कर रहा है।

पीएम मोदी ने समिट के जरिए ही देश को जानकारी दी कि भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दो ओपन मार्केट के बीच दोनों देशों के विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। भारत में ईको एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा और नई अपॉर्च्युनिटी के रास्ते खुलेंगे।

रिफॉर्म को लेकर पीएम मोदी ने कही बड़ी बात : प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में बहुत दशकों तक विपरित धारा बही और इसका नुकसान हुआ। पहले कोई भी बहुत बड़ा फैसला लेने से पहले सोचा जाता था कि वोट मिलेगा कि नहीं, दुनिया क्या सोचेगी। इसके कारण बड़े रिफॉर्म टलते जाते थे। देश तभी आगे बढ़ता

है जब देश प्रथम की भावना से काम किया जाए और आज हम इसका परिणाम देख रहे हैं। इस सरकार ने राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण ऐसे निर्णय लिए हैं जो लटके भटके थे। मोदी ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा, हमारे पीएम ने माना था एक रुपये में 15 पैसा जनता तक पहुंचता था। अगर 1 रुपये निकले तो 100 के 100 पैसे लाभार्थियों को मिले। इसके लिए DBT शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस देश में 10 करोड़ ऐसे लाभार्थी थे, जिनका जन्म ही नहीं हुआ था। हमारी सरकार ने 10 करोड़ नामों को हटाया और पूरा का पूरा पैसा DBT के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन अनेक दशकों तक नहीं हुआ, हमारी सरकार ने आते ही इसे लागू किया। महिला आरक्षण, तीन तलाक और वक्फ कानून जैसे कई फैसले हैं, जिनके जरिए हमारी सरकार ने बड़े रिफॉर्म किए। मुस्लिम महिलाओं के हित में हमारी सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया। वक्फ (शेष पृष्ठ 7 पर)

संक्षिप्त समाचार

उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा का सुनहरा भविष्य

लखनऊ, चसं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्य के रूप में तेजी से उभर रहा है। कंप्रेस्ड बायोगैस के क्षेत्र में जहां यूपी पहले से ही स्थापित प्लांट्स की संख्या में नंबर एक है, वहीं निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स के आंकड़ों में भी राज्य पूरे देश में सबसे आगे निकल गया है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 129 सीबीजी प्रोजेक्ट्स का निर्माण चल रहा है, जिन पर लगभग 5,992 करोड़ का निवेश हो रहा है। यह भारत में किसी भी राज्य में निर्माणाधीन सीबीजी प्लांट्स की सबसे बड़ी संख्या है। उत्तर प्रदेश में 25 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित हैं। पूरे देश में सर्वाधिक सीबीजी प्लांट उत्तर प्रदेश में ही हैं। प्रदेश में पूरे देश के 19 प्रतिशत सीबीजी प्लांट्स स्थापित हैं जो पूरे देश में सर्वाधिक हैं। इन प्लांट की क्षमता 213 टन पर डे टीपीडी है। इसके बाद गुजरात 16 प्रतिशत, महाराष्ट्र 9 प्रतिशत का नंबर आता है। नंबर्स की बात करें तो गुजरात में 21 प्लांट्स, महाराष्ट्र में 12, पंजाब में 10 और मध्य प्रदेश में 6 प्लांट स्थापित हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश, सीबीजी क्षेत्र में निवेश और विकास का सबसे सक्रिय केंद्र बन चुका है।

आईओसी की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज

नई दिल्ली, एजेंसी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई एक्शन लिए हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान हड़बड़ाहट में आ गया है। इस बीच इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान का सहयोग करने की बात की है। वहीं, भारत ने मंगलवार को इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) की आलोचना की और पहलगाम हमले पर उसके बयान को बेतुका बताया। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा कि ओआईसी ने पाकिस्तान के इशारे पर बयान जारी किया है। जानकारी दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान के इशारे पर जारी (शेष पृष्ठ 7 पर)

मॉक ड्रिल को लेकर उच्च स्तरीय बैठक

चर्चित राजनीति। एजेंसी

- कई अधिकारी रहे मौजूद

नयी दिल्ली। 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल पर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। गृह सचिव 244 सिविल डिफेंस जिलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। दरअसल, 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर यह एक महत्वपूर्ण बैठक है, जो गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित की गई है।

बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति से यह स्पष्ट है कि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ा यह एक राष्ट्रीय स्तर का समन्वय प्रयास है। इस बैठक का उद्देश्य 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारी और समन्वय को सुनिश्चित करना है। इसी के चलते एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस डीजी, डीजी फायर और एयर डिफेंस के अधिकारियों के साथ ही राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा, सीमावर्ती और संवेदनशील जिलों पर फोकस करना है। 244 सिविल डिफेंस जिलों और सीमावर्ती क्षेत्र के प्रतिनिधि इस मीटिंग के लिए खास तौर पर शामिल हुए हैं। साथ ही इस ड्रिल में रॉकेट, मिसाइल और हवाई हमले जैसे आपातकालीन परिदृश्यों की तैयारी पर भी फोकस किया जाएगा। इसके अलावा, सायरन और ब्लैकआउट की व्यवस्था को कैसे करना है, इस पर भी बैठक में चर्चा संभव है। यह बैठक देश की सुरक्षा और आपदा से निपटने की क्षमताओं को परखने और सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने देश के कई राज्यों को 7 मई को व्यापक नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, मॉक ड्रिल के तहत महत्वपूर्ण गतिविधियां की जाएंगी। इस दौरान एयर रेड वार्निंग सायरनों का संचालन होगा। यह बड़े खतरे और दुश्मन की गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी करने से जुड़ा कदम है। नागरिकों और छात्रों को संभावित हमलों की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक नागरिक सुरक्षा तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्रैश ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत दुश्मन की हवाई निगरानी या हमले से शहरों और ढांचों को छिपाने के लिए आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा।

आज बजेंगे जंगी सायरन : पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच पड़ोसी देश से युद्ध की आशंका को देखते हुए पूरा देश माक ड्रिल के लिए कमर कस चुका है। मॉक ड्रिल देश के सिविल डिफेंस जिलों में की जाएगी। सिविल डिफेंस जिले भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें सशस्त्र बल केंद्र या महत्वपूर्ण आर्थिक या सार्वजनिक अवसंरचना, जैसे तेल रिफाइनरी या परमाणु संयंत्र हो। गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को मॉक ड्रिल के संबंध में दिए गए निर्देशों में 54 वर्षों में पहला क्रैश ब्लैकआउट उपायों के प्रविधान का भी उल्लेख किया गया है। दुश्मन के विमानों द्वारा हवाई हमलों के दौरान ब्लैकआउट उपायों को लागू किया जाता है। इस तरह की ड्रिल आखिरी बार 1971 में की गई थी जब पाकिस्तान के साथ पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों मोर्चों पर युद्ध हुआ था। 2003 के एक दस्तावेज, भारत में नागरिक सुरक्षा के सिद्धांत में बताया गया है कि हवाई हमलों के दौरान क्या करें और क्या न करें। इसमें यह भी बताया गया है कि ब्लैकआउट को किस प्रकार लागू किया जाना चाहिए। दुश्मन के विमानों की हरकत का पता लगाने का काम वायुसेना का है। जैसे ही वायुसेना को दुश्मन के किसी विमान का पता चलता है, सूचना क्षेत्रीय नागरिक सुरक्षा नियंत्रण केंद्रों को भेज दी जाती है-इसके बाद (शेष पृष्ठ 7 पर)

मॉक ड्रिल में देशवासी बढ़ चढ़कर लें हिस्सा

नयी दिल्ली, एजेंसी। देश भर में 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। पहलगाम टेरर अटैक के बाद तनावपूर्ण स्थिति में जंग जैसे हालात बने हुए हैं। इस ड्रिल को तैयारियां की जा रही हैं। इसी बीच बीजेपी ने देशवासियों ने इस मॉक ड्रिल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है।

भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर कार्यकर्ताओं, नेताओं, समर्थकों और नागरिकों से इस ड्रिल में हिस्सा बनने की अपील की है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी सुरक्षा अभ्यास के दौरान आगे आएं और नए और जटिल खतरों के खिलाफ तैयारियों की जांच के लिए स्वयंसेवक बनें। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मॉक ड्रिल के दौरान स्वेच्छा से काम करने और अपनी भागीदारी के माध्यम से बदलाव लाने की अपील की। गृह मंत्रालय ने पोस्ट शेयर कर कहा कि 'सभी नागरिकों, बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील है कि वो आगे आएं और स्वेच्छा से काम करें। आपकी भागीदारी से बहुत फर्क पड़ेगा।' यह अपील गृह मंत्रालय (एमएचए) के निर्देश के मद्देनजर की गई है, जिसमें सभी राज्यों को नागरिक सुरक्षा प्रणालियों के परीक्षण और सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से मॉक ड्रिल आयोजित करने (शेष पृष्ठ 7 पर)

मुख्यमंत्री योगी से मिला पत्रकारों का दल, रखी मांगें

चर्चित राजनीति। संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के सचिव भारत सिंह के नेतृत्व में कल सोमवार को पत्रकारों का एक दल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मिला। पत्रकारों से जुड़े कई विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा हुई।

पत्रकारों के आवास व निःशुल्क चिकित्सा जैसे कुछ विषयों पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया गया। मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के सचिव भारत सिंह ने पत्रकारों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के हितों से जुड़ी समसस्याओं के निराकारण का आश्वासन दिया। प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू करने, पत्रकारों को अनुदान पर प्लाट और फ्लैट उपलब्ध कराने और एसजीपीजीआई में पत्रकारों के इलाज के लिए 25 लाख रूपये की धनराशि को बढ़ाकर 50 लाख कराने की मांग रखी गयी।इसके अलावा समाचार पत्रों की विज्ञापन दरें और विज्ञापन मान्यता समिति का भी गठन के लिए बात रखी गयी। बातचीत में पत्रकारों के प्रतिनिधि मण्डल ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणी के समाचार पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी किए जाते रहे हैं उनकी सूचीबद्धता एक निश्चित न्यूनतम दर पर की जाती है। अतः सूचीबद्धता हेतु समाचार पत्र की प्रसार संख्या, नियमितता तथा लोकप्रियता के आधार पर विज्ञापन दरें बढ़ाई जाएं। इसी क्रम में हम यह भी माँग करते हैं की प्रेस मान्यता समिति की भाँति विज्ञापन मान्यता समिति का भी गठन किया जाए। यह परम्परा पूर्व में रही है। फोटो जर्नलिस्ट के लिए विधायक निवास दारुलशफा ए ब्लॉक- 66 में आवन्टित कार्यालय किराया जमा (शेष पृष्ठ 7 पर)

भारत ने जारी किया 'नोटम'

नई दिल्ली, एजेंसी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस बीच भारत सरकार की ओर से देश के सभी राज्यों में बुधवार को मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। देश भर के चिह्नित करीब 300 जिलों में 7 मई को बड़े पैमाने पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के आयोजन का निर्देश दिया गया है। साल 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद पहला ऐसा अभ्यास होगा। देश के अलग-अलग हिस्सों में कल होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इस बीच खबर है कि पाक सीमा पर अभ्यास के लिए भारत की ओर से NOTAM जारी किया गया है। बता दें कि भारत कल हवाई अभ्यास करेगा। इसको देखते हुए हवाई अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया गया है। इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया है। ये हवाई युद्धाभ्यास पाकिस्तान की सीमा के दक्षिणी हिस्से के पास किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना कल 7 मई से भारत पाकिस्तान सीमा पर रेगिस्तानी क्षेत्र और आस-पास के इलाकों में अभ्यास करेगी जिसमें राफेल, मिराज 2000 और सुखोई-30 सहित सभी अग्रणी विमान भाग लेंगे जानकारी हो कि NOTAM एक प्रकार का नोटिस है। इसके माध्यम से उड़ान संचालन से संबंधित कर्मियों (शेष पृष्ठ 7 पर)

बीबीचक (तेजकिशन खेड़ा) में 5 लाख से होगा अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यीकरण, डॉ. राजेश्वर सिंह ने किया ऐलान

बाबा साहेब के सपनों का भारत, भाजपा की नीति और नीयत में प्रतिबिंबित

चर्चित राजनीति। संवाददाता

लखनऊ। सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र के तेज किशन खेड़ा, मजरा बीबी चक में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भंडारे में पहुंचे डॉ. राजेश्वर सिंह ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। डॉ. सिंह ने अपने संबोधन में बाबासाहेब को युगप्रवर्तक विचारक, संविधान निर्माता और सामाजिक समरसता के सबसे बड़े प्रेरक के रूप में नमन किया।

इस अवसर पर सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि सरोजनीनगर में बाबा साहेब की प्रतिमाओं के सौन्दर्यीकरण कार्य निरंतर कराये जा रहे हैं। इसी क्रम में नटकुर, मेमोरा, गहरू, पिपरसंड, ऐन, माती, किशनपुर कौड़ियां, दारोगाखेड़ा, सदरौना, फतेहगंज, हुल्लीखेड़ा सहित 15 स्थालों पर अम्बेडकर प्रतिमाओं पर टिन शेड लगाए गए। विधायक ने बताया कि इस प्रतिमाओं के अनावरण के समय अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर 100 से अधिक आभावग्रस्त परिवारों के माधावियों को साइकिल प्रदान कर सम्मानित भी किया गया।

अपने उद्बोधन में डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं, वह एक विचार हैं। और उस विचार को सहेजने, संवारने और आगे बढ़ाने का कार्य अगर किसी सरकार ने किया है, तो वह है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार। डॉ. सिंह ने सभा में डॉ. अंबेडकर को समर्पित भाजपा सरकार के 10 ऐतिहासिक निर्णयों और कार्यों को विस्तार से रखा। प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर बाबासाहेब की जीवनयात्रा के पांच प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ घोषित किया गया। महू (मप्र) जन्मभूमि, लंदन उच्च शिक्षा, नागपुर दीक्षाभूमि, मुंबई चैत्यभूमि (महापरिनिर्वाण स्थल), दिल्ली 26 अलीपुर रोड अंतिम निवास। पहली बार 26 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर संविधान दिवस घोषित कर बाबासाहेब के योगदान को संस्थागत सम्मान दिया गया। बाबासाहेब की जयंती (14 अप्रैल) को राष्ट्रीय अवकाश और 'राष्ट्रीय समरसता दिवस' का दर्जा, जिस तिथि को दशकों तक उपेक्षित रखा गया, उसे भाजपा सरकार ने सामाजिक समरसता के प्रतीक दिवस के रूप में स्थापित किया। डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली (2017), यह केंद्र न केवल शोध और संवाद का मंच है, बल्कि सामाजिक न्याय और नीति निर्माण का वैचारिक ध्रुव भी है। कांग्रेस द्वारा उपेक्षित अलीपुर रोड स्थित उनके निवास को एक भव्य डिजिटल संग्रहालय में परिवर्तित किया गया। जहां बाबासाहेब ने 5 लाख अनुयायियों संग बौद्ध दीक्षा ली, उसे वैश्विक मान्यता मिली। भीम ऐप' की शुरुआत-डिजिटल आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक। भारत रत्न सम्मान (1990),भाजपा समर्थित सरकार ने डॉ. अंबेडकर को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, जिसे कांग्रेस सरकारें दशकों तक टालती रहीं। भाजपा के निरंतर प्रयासों से संसद में संविधान निर्माता का चित्र लगाया गया। कन्नौज मेडिकल कॉलेज सहित अनेक संस्थानों का नाम बाबासाहेब पर रखा गया। 'सामाजिक न्याय सप्ताह', 'संविधान गौरव अभियान' जैसे कार्यक्रमों से उनके विचारों को गाँव-गाँव तक पहुँचाया गया।

डॉ. राजेश्वर सिंह ने इस जनसभा के माध्यम से समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा ÷आज अखिलेश यादव अपनी फोटो बाबा साहेब के साथ जोड़कर उनका अपमान कर रहे हैं, वे य भूल गए कि बाबा साहब ने अपने प्रयासों से करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किया है। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने ग्रामीणों के अनुरोध पर इंटर कॉलेज की स्थापना के लिए पत्राचार करने, पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख की राशि प्रदान करने, हनुमान मंदिर के सौन्दर्यीकरण के लिए 51 हजार रूपये प्रदान करने, स्कूलों में झूले (शेष पृष्ठ 7 पर)

अखिलेश बोले-मायावती का फैसला बदलकर गलती की

चर्चित राजनीति। संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से राजा भैया को निशाने पर लिया। कहा बहुजन समाज पार्टी ने जो फैसला किया था, वह मुझे बदलना नहीं चाहिए था। अखिलेश का इशारा मायावती सरकार के दौरान लगाए गए पोटा एक्ट की तरफ था। जिसे मुलायम सरकार ने बाद में हटा लिया था। अखिलेश यादव मंगलवार को सपा के लखनऊ ऑफिस में मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर भी तीखा हमला बोला।

झांसी में किसानों की जमीन औने-पौने दामों में छीने जाने से लेकर जेपीएनआईसी बेचने तक, हर मुद्दे पर अखिलेश ने सरकार की नीयत और नीति पर सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा जब सब कुछ बिक रहा है तो अब बसें भी बिकेंगी। भाजपा एसेट्स बनाना नहीं जानती, वो बस बेचने में लगी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जिस दिन चाहेंगे, साक्षी महाराज समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। अखिलेश ने राजा भैया को भी निशाने पर लिया। कहा बहुजन समाज पार्टी के निर्णय को मुझे बदलना नहीं चाहिए था। अखिलेश यादव लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में मीडिया से

- राजा भैया का नाम लिए बिना सपा सुप्रीमो ने कहा-पोटा नहीं हटाना चाहिए था

मुखातिब थे। राजा भैया ने अखिलेश के खास और प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष गुलशन यादव के खिलाफ एफआईआर लिखाई थी। इसके बाद 4 मई को सरकार ने गुलशन की 7 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की थी। इसको लेकर अखिलेश काफी नाराज हैं। अखिलेश यादव ने आज दो टूक कहा कि राजा भैया के उन्हें चुनाव हारने से कोई नहीं बचा सकता। दरअसल, प्रतापगढ़ में सपा नेता गुलशन यादव पर हो रही कार्रवाई को लेकर अखिलेश से सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा यह हम सब जानते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? आर्थिक रूप से भी जितना तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा रहा है। टाइम लाइन देखिए मुकदमे कब दर्ज हुए हैं? पुलिस कप्तान जो थे, उनसे बात की तो लगा कि उनके ऊपर दबाव है। एफआईआर कौन लोग करवा रहे हैं? वो घबराए हुए लोग हैं। जिन्हें चुनाव हारना निश्चित है। वो लोग चुनाव हारेंगे। उन्हें कोई भी गणित चुनाव नहीं जिता सकता। मैं आपको वो बातें याद दिला दूं, जिसे याद नहीं दिलानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए था। अखिलेश यादव का इशारा राजा भइया पर लगे पोटा कानून की ओर था।

साल 2002 में प्रदेश में भाजपा और बसपा की गठबंधन की सरकार थी। राजा भइया पर आरोप लगा कि वह भाजपा-बसपा वाली गठबंधन सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे, सरकार गिराना चाहते हैं। 2 नवंबर, 2002 को मायावती सरकार ने राजा भैया को पोटा के तहत गिरफ्तार करवाया। राजा भैया को करीब 11 महीने तक जेल में रहे। इस दौरान उनकी भदरी रियासत की हवेली में पुलिस ने छापेमारी की और उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई भी की। 2003 में मायावती सरकार ने प्रतापगढ़ में राजा भैया की भदरी रियासत के पास स्थित बेंती तालाब को सरकारी कब्जे में ले लिया। इसे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार घोषित कर दिया। बाद में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। मुलायम सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही राजा भइया की रिहाई के आदेश जारी कर दिए। साथ ही, बसपा सरकार द्वारा लगाया गया पोटा भी हटा दिया। अखिलेश ने चाचा शिवपाल को लेकर कहा कि उनके संबंध सबसे अच्छे हैं। कुछ लोग सदन की कार्रवाई नहीं समझते लेकिन बयानबाजी जरूर करते हैं। खनन में भ्रष्टाचार के सवाल पर अखिलेश ने मुस्कराकर कहा योगी जी ने शायद पहली बार सच बोला। जाने वाले की तारीफ होनी चाहिए। अब तो आप सबको पता है, कौन जा रहा है। साक्षी महाराज की टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने कहा जिस दिन हम चाहेंगे, साक्षी महाराज समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हम जिस दिन अपील करेंगे, वो पीडीए की लड़ाई के लिए हमारी पार्टी में आ जाएंगे। उन्हीं के दबाव में ही सरकार जातीय जनगणना करा रही है। पहलगाम में शहीद हुए लोगों को 'शहीद' का दर्जा दिया जाना चाहिए। सरकार उनके परिवार वालों को 10-10 करोड़ का मुआवजा दे। भाजपा के एक विधायक के सुरक्षा मांगने पर अखिलेश ने कहा हमारे नेता पत्र लिख देंगे, उनके लिए भी सुरक्षा मांगी जाएगी। उन्होंने कहा आजकल डर लगता है कि किस जवाब को आप लोग कैसे पेश कर देंगे? आप मेरी किसी से लड़ाई करवा दोगे। जब होम मिनिस्ट्री गाइडलाइन जारी कर चुकी है, तो गैर-जरूरी बयान नहीं देने चाहिए।

उन्होंने कहा जेपीएनआईसी से हमारा इमोशनल अटैचमेंट है। जब उसका शिलान्यास हुआ था, कई समाजवादी नेता मौजूद थे। अगर भाजपा उसे बेचना चाहती है, तो हम खरीदेंगे। कार्यकर्ताओं से चंदा मांगूंगा। अखिलेश ने कहा अगर बुंदेलखंड में फैक्ट्री होती, तो हमें रशिया से मिसाइल नहीं मंगानी पड़ती। ये लोग तो झांसी में सुतली बम भी नहीं बना पाए। जमीन ली, मुआवजा नहीं दिया, अब कह रहे हैं विकास हुआ है। 18 अप्रैल को झांसी में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अफसरों से बातचीत की। 52 गांव पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन न अभिलेख में नाम है, न पुनर्वास पूरा हुआ। अब दोबारा जमीन ली जा रही है। 33 गांवों में सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। किसानों को 9 लाख प्रति हेक्टेयर दिया जा रहा है, जो बाजार रेट के मुकाबले बेहद कम है। तहसीलदार किसानों पर जमीन रजिस्ट्री के लिए दबाव बना रहे हैं।

पीएम श्री केवी शिवगढ़ में मैजिक स्लेट वितरण समारोह सम्पन्न

चर्चित राजनीति। संवाददाता

शिवगढ़, रायबरेली। क्षेत्र के पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय शिवगढ़ में मंगलवार को एलसीडी राइटिंग टैबलेट (रिचार्जेबल मैजिक स्लेट) वितरण समारोह सम्पन्न हुआ।

गौरतलब हो कि क्षेत्र के पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय शिवगढ़ में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम श्री योजना अन्तर्गत मैजिक स्लेट वितरण समारोह आयोजित किया गया। जिसमें कक्षा-1, कक्षा 2 के 155 छात्र-छात्राओं को रिचार्जेबल मैजिक स्लेट का वितरण किया गया। जिसका शुभारम्भ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री बरखण्डी विद्यापीठ इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजकुमार गुप्ता व पीएम श्री केन्द्रीय

- कक्षा-1, कक्षा-2 के छात्र-छात्राओं को बांटे गए मैजिक स्लेट

विद्यालय शिवगढ़ के प्राचार्य मनोज कुमार द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन से किया गया। मैजिक स्लेट वितरण समारोह में श्री गुप्ता ने मैजिक स्लेट वितरण करने के दौरान छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि मैजिक स्लेट से डिजिटल लिट्रेसी को बढ़ावा मिलेगा, यह छात्र-छात्राओं की लेखन अभ्यास अभिरुचि बढ़ाने के साथ ही साथ शिक्षण अभिरुचि बढ़ाने में मददगार साबित होगी। वहीं विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार ने छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों को मैजिक स्लेट्स की उपयोगिता की जानकारी देते हुए बताया

कि मैजिक स्लेट एक पुनः प्रयोज्य लेखन बोर्ड है जिस पर लिखकर आसानी से मिटाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल बार-बार किया जा सकता है। थेरेपी में, यह बच्चों के लिए लेखन, ड्राइंग और ट्रेसिंग का अभ्यास करने के लिए एक इंटरैक्टिव माध्यम के रूप में कार्य करती है, जिससे बच्चों के संज्ञानात्मक, संचार कौशल में वृद्धि होगी है। इस मौके पर महेश शुक्ला, कक्षाध्यापक सर्वेश कुमार गिरि, शुभम भारती, आकाश, मयंक, पंकज पंत, जय नारायण यादव, सतानन्द यादव, प्रशांत कुमार, दीपक तथा अभिभावक एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

थाईलैंड में पासपोर्ट बैन हुआ तो लगाया जुगाड़

लखनऊ, चसं। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति पकड़ा गया है। वह थाईलैंड जा रहा था। थाईलैंड में उसका पासपोर्ट बैन है। बैन होने के बाद उसने जुगाड़ लगाकर नया पासपोर्ट बनवा लिया। यहां एयर एशिया के विमान में एंट्री से पहले इमिग्रेशन काउंटर पर उसका फर्जी पासपोर्ट पकड़ा गया। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सोमवार रात वह बैंकॉक जाने वाला था। इमिग्रेशन काउंटर पर पासपोर्ट की जांच में पता चला कि यात्री पहले विजिट वीजा पर थाईलैंड गया था। वहां निर्धारित समय से अधिक रहने पर थाई पुलिस ने पकड़ा था। उसका पासपोर्ट बैन कर भारत वापस भेज दिया गया था। सरोजनी नगर प्रभारी निरीक्षक राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि पकड़े गए यात्री के पहले वाले पासपोर्ट में नाम कमलेश यादव था और पिता का नाम रामानंद था। अब उसने फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया है। इसमें यात्री ने अपना नाम कमलेश कुमार और पिता का नाम रामानंद यादव कर दिया है। पुलिस ने बताया यात्री के दोनों पासपोर्ट में जन्मतिथि भी अलग-अलग पाई गई है। बैन हो चुके पासपोर्ट में जन्मतिथि 02-07- 1986 है, जबकि दूसरे पासपोर्ट में इसकी जन्मतिथि 10-05-1975 है। इसने पासपोर्ट बैन होने पर भारत आकर अपने नाम में बदलाव कर फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया।

डिप्टी सीएम ने संस्कृत पाठशाला कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं को किया सम्मानित

लखनऊ, चसं। सदर बाजार स्थित संस्कृत पाठशाला कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित मेधावी विद्यार्थियों के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा हर बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी एवं कुशल नेतृत्व में देश व प्रदेश में संचालित शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के जरिए बच्चे देश-दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा मधु पटेल व सभी छात्राओं को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में कम्प्यूटर लैब व अन्य शैक्षिक सुविधाओं की स्थापना हेतु अपनी विधायक निधि का प्रयोग करेंगे। उन्होंने छात्राओं एवं विद्यालय प्रबंधन को आश्वस्त किया कि शैक्षिक सुविधाओं की स्थापना के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी। गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। प्रबंधक राजीव अग्रवाल ने बताया कि विद्यालय में 60 फीसदी छात्राएं प्रथम श्रेणी एवं 20 प्रतिशत छात्राओं ने 70 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कार्यक्रम में संस्कृत पाठशाला समिति के अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक अंकुर अग्रवाल, प्रधानाचार्या, कन्या इंटर कॉलेज उमा खन्ना, प्रधानाचार्या, डिग्री कॉलेज डॉ रश्मि श्रीवास्तव, प्रधानाचार्या, एसपी पब्लिक इंटर कॉलेज दर्शना राय, प्रधानाचार्य, एसपी जूनियर हाईस्कूल कृष्ण कुमार गुप्ता, कैंटोनमेंट बोर्ड के नामित सदस्य प्रमोद शर्मा, प्रताप सिंह वाल्मीकि, आलोक सिंघल एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

महापौर सुषमा खर्कवाल के मानसून से पूर्व तैयारियों के निर्देश

लखनऊ, चसं। नगर निगम लखनऊ की विकास योजनाओं और आगामी मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर मंगलवार को एक अहम बैठक का आयोजन कैंप कार्यालय में किया गया। बैठक की अध्यक्षता माननीय महापौर सुषमा खर्कवाल ने की। बैठक में नगर आयुक्त गौरव कुमार, समस्त अपर नगर आयुक्त, सीएफएओ, जीएम जलकर, चीफ इंजीनियर (सिविल), चीफइंजीनियर (आरआर) सहित नगर निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान महापौर ने विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों से उनके विभागीय कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से आगामी मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए ड्रेनेज सिस्टम, जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान और उनकी समय पर सफाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। महापौर ने कहा कि मानसून से पहले सभी नालों और जल निकासी व्यवस्था की पूरी तरह से सफाई की जाए, जिससे कि शहर में जल भराव की समस्या उत्पन्न न हो। श्रीमती खर्कवाल ने कहा कि शहरवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हर विभाग को समन्वय बनाकर कार्य करना होगा।

जोन तीन में हटाए गए दर्जनों ठेले और झोपड़ियां

लखनऊ, चसं। नगर निगम लखनऊ के जोन-3 में आज अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व जोनल अधिकारी ने किया। कुल 296 टीमों के साथ यह अभियान मडियांव थाने से होकर प्रमुख मार्गों पर चलाया गया। नगर निगम की टीम ने सड़क पर अवैध रूप से लगे ठेले, गुमटियां, झोपड़ियां और अन्य अतिक्रमण हटाए। अभियान के दौरान जोनल अधिकारी श्री अमरजीत सिंह यादव के साथ टैक्स सुप्रिटेंडेंट सभाजीत सिंह, राजस्व निरीक्षक श्रीमती स्वप्निल सिंह, उदय त्रिपाठी और थाना मड़ियांव की पुलिस फोर्स भी मौजूद रहे। अभियान मड़ियाव थाने से केशव नगर मोड़ तक व केशव नगर मोड़ से मड़ियाव थाने तक दोनों पट्टियों पर किए गए अस्थाई अतिक्रमण के विरूद्ध अभियान चलाया गया।

इस अभियान में 75 फल व सब्जी के ठेले, 16 गुमटियां, लगभग 12 बांस की झोपड़ियां, टीनशेड, लोहे की गुमटी, लकड़ी की गुमटी, 2 लोहे के काउंटर, 2 अन्य ठेले और लगभग 9 बोर्ड हटाए गए। यह सारा सामान नगर निगम की टीम ने जब्त कर लिया। अभियान के अंतर्गत प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त किया गया जिससे राहगीरों को आने-जाने में आसानी हो।इस अभियान के संचालन के दौरान कई जगहों पर नगर निगम की गाड़ियों और जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माण हटाया गया। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में इन स्थानों पर दोबारा अतिक्रमण न होने पाए। इसके लिए स्थानीय पुलिस को भी निर्देशित किया गया है।जोनल अधिकारी ने बताया कि यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा ताकि शहर में स्वच्छता और सुगम यातायात सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जनता को जागरूक किया जा रहा है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण न करें और नगर निगम के साथ सहयोग करें।जोन-5 क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ एक प्रभावी अभियान चलाया गया। अभियान का संचालन चंदर नगर स्टेट बैंक से जय प्रकाश नगर चौक, स्टेला रोड होते हुए आलमनगर चौराहे तक किया गया। इस मार्ग पर अस्थाई रूप से किए गए अतिक्रमण जैसे ठेला, टेबल, खुमचा, गुमटी, काउंटर आदि को हटाया गया।

बिजली खरीद करार मंहगी बिजली करने की तैयारी

चर्चित राजनीति। संवाददाता

लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के आह्वान पर आज लगातार पांचवे दिन शक्तिभवन मुख्यालय पर बिजली कर्मचारियों का क्रमिक अनशन जारी रहा। आज ताप विद्युत परियोजनाओं के बिजली कर्मी अनशन में सम्मिलित हुए। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के पहले मिर्जापुर में अडानी से बहुत मंहगी दरों पर बिजली खरीद करार निजीकरण के बाद आम उपभोक्ताओं को मंहगी बिजली देने की तैयारी है। संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु अवैध ढंग से झूठा शपथ पत्र देने वाले नियुक्त किये गया ट्रांजैक्शन कन्सलटेंट ग्रान्ट थॉर्टन अडानी पॉवर का भी कंसलटेंट है जिससे मंहगी बिजली खरीद का करार होने वाला है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि निजीकरण के बाद निजी घरानों को मदद करने हेतु आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली मंहगी करने की तैयारी है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सोनभद्र जनपद में उत्पादन निगम की अनपरा 'ए' परियोजना से 2.816 रूपये प्रति यूनिट, अनपरा 'बी' परियोजना से 2.502 रूपये प्रति यूनिट तथा अनपरा 'डी' परियोजना से 3.574 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है।

अडानी पॉवर के साथ 25 वर्षों की अवधि के लिए किये जाने वाले बिजली क्रय करार के अनुसार 5.383 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी जो सरकारी क्षेत्र के उत्पादन निगम से मिलने वाली बिजली की तुलना में कहीं अधिक मंहगी है। उन्होंने कहा कि ग्रान्ट थॉर्टन अडानी पॉवर का भी सलाहकार है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की दृष्टि से ही अडानी पावर के साथ मंहगी बिजली खरीदने का करार किया गया है। स्पष्ट है कि निजीकरण के बाद पूर्वांचल की गरीब जनता के लिए बिजली की दरें बढ़ने वाली है। संघर्ष समिति ने उपभोक्ताओं को आगाह किया कि निजीकरण प्रदेश को लालटेन युग में ले जायेगा। क्रमिक अनशन के पांचवे दिन आज ओबरा, पिपरी, अनपरा, हरदुआगंज, पारीछा, जवाहरपुर और पनकी विद्युत परियोजनाओं के तथा लखनऊ नगर के 200 से अधिक बिजली कर्मचारी और अभियन्ता क्रमिक अनशन में सम्मिलित हुए। क्रमिक अनशन कल भी जारी रहेगा। कल क्रमिक अनशन में बरेली, देवीपाटन, अयोध्या, रायबरेली, सीतापुर और लखनऊ क्षेत्र तथा लखनऊ नगर के बिजली कर्मी सम्मिलित होंगे। कल पंजाब और हरियाणा के बिजली कर्मचारी और अभियन्ता उप्र के बिजली कर्मियों के समर्थन में क्रमिक अनशन में सम्मिलित होंगे।आज प्रदेश के अन्य जनपदों और परियोजनाओं पर निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन जारी रहा। शक्ति भवन पर क्रमिक अनशन के पांचवे दिन आज मुख्यतया मो0 वसीम, विशम्भर सिंह, योगेन्द्र कुमार लाखा, सत्या उपाध्याय, सुबोध कुमार, शैलेन्द्र सिंह, जितेन्द्र यादव, गौरव वर्मा, गणेश दत्त, अरविन्द कुमार यादव, विवेक सक्सेना, प्रदीप कनौजिया, रूपेन्द्र शर्मा, निर्भय सिंह, पवन कुमार, अंकित कुमार इत्यादि सम्मिलित हुए।

कैबिनेट का बिजली खरीद प्रस्ताव, उपभोक्ताओं के लिए घाटे का सौदा : उत्तर प्रदेश में निजीकरण का मसौदा तैयार करने वाला असंवैधानिक रूप से नियुक्त ग्रंथ फ्रंटल इसके ज्यादातर एक्सपर्ट या तो अडानी के साथ कार्य कर रहे हैं या तो कर चुके हैं। इसका खुलासा उपभोक्ता परिषद पहले ही कर चुका है। अब आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में वेडिंग रूट के 800 मेगावाट के दो इकाइयों 1600 मेगावाट तापीय पावर परियोजना से कुल 1500 मेगावाट बिजली रुपया 5.38 प्रति यूनिट में खरीदने के लिए न्यूनतम विड को प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किया। सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला आया है कि प्रदेश सरकार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि या बिल्डिंग रूट का प्रोजेक्ट जिस नियम के तहत है उसमें 25 सालों तक जो फिक्स कॉस्ट रुपया 3.727 पर यूनिट है। उसमें गिरावट होने की संभावना बहुत कम है। वह बराबर रहेगी । जो उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बहुत घाटे का सौदा है या कहना बिल्कुल सही है कि अदानी जो पूर्वांचल के निजीकरण के पश्चात नई बिजली कंपनी को खरीदना चाहते हैं वहां के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरें आने वाले समय में बढ़ना तय है। अब कोई यह बताए कि अदानी पावर के पास कौन सी ऐसी दूरबीन है की टेंडर उनका अक्टूबर में खुला और उन्होंने टरबाइन मशीन का आर्डर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल को जून 2024 में ही दे दिया । इसका मतलब नियमानुसार मामले की सीबीआई से जांच करने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय अथवा सीबीआई से जांच होना जरूरी है और उपभोक्ता परिषद प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता है कि कुछ उच्च अधिकारी जल्दबाजी में इसे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट से पास करा लिया। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष में कहा चाहे महाराष्ट्र की बात हो या मध्य प्रदेश की सभी जगह बिडिंग रूट के टेंडर में अदानी ही न्यूनतम निविदा डाता घोषित हो रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

बैंक अधिकारियों ने ग्रामीणों को दी योजनाओं और ऋण सुविधाओं की जानकारी

हरचंदपुर/रायबरेली, चसं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की देदानी शाखा ने एक विशेष चौपाल का आयोजन किया। इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं से अवगत कराना था। बैंक की अधिकारी अर्चना पांडेय ने बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बैंक से जुड़कर ग्रामीण अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। कार्यक्रम में यूनिक आहूजा ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने ग्रामीणों को बैंक की ऋण योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

नेत्र शिविर में 72 रोगियों का किया गया नेत्र परीक्षण

बछरावां/रायबरेली, चसं। क्षेत्र के थुलेंडी गांव में डॉक्टर एम. के. कुरैशी के आवास पर इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय कैसरबाग लखनऊ द्वारा आयोजित निशुल्क मोतियाबिंद नेत्र प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया । इस शिविर में 72 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया। नेत्र परीक्षण में 27 मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया जिनको लैंस प्रत्यारोपण की सलाह दी गई। सभी 27 मरीजों को चिन्हित करके उन्हें लैंस प्रत्यारोपण के लिए इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय कैसरबाग लखनऊ ले जाया गया। इस मौके पर डॉक्टर एम.के. कुरैशी, डॉक्टर योगेंद्र वर्मा, सलीम, शालिनी सिंह, संध्या सैनी, आकांक्षा, रागिनी सिंह, बृजेंद्र प्रताप, तंजीम कुरैशी, जतिन कुशवाहा चाहत, देवानंद एवं दूर दराज के गांव से आए मरीज एवं ग्रामवासी भी मौजूद रहे।

शिक्षा के उजियारे से दूर होगा जरायम का अंधेरा

रायबरेली, चसं। जरायम की दुनिया में फंसे बंदियों का जीवन अब शिक्षा की रोशनी से नई राह पर आगे बढ़ेगा। रायबरेली जिला कारागार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) का केंद्र खोल दिया गया है, जिससे अब बंदी हाईस्कूल और इंटर की पढ़ाई के साथ-साथ बोर्ड परीक्षाएं भी दे सकेंगे। बंदी शिक्षा के जरिए न केवल अपनी सोच बदल सकेंगे, बल्कि जेल से बाहर निकलकर समाज में सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकेंगे। प्रदेश के चुनिंदा जिलों में बंदियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है। रायबरेली जिला कारागार में हत्या, लूट, दुष्कर्म और चोरी जैसे मामलों में बंद ऐसे कई अभियुक्त हैं, जिन्होंने कक्षा 9 या 11 तक की पढ़ाई की है, लेकिन जेल में रहने के कारण पढ़ाई अधूरी रह गई। एनआईओएस सेंटर खुलने से अब उनका सपना साकार हो सकेगा। वर्तमान में जेल में करीब 800 बंदी निरुद्ध हैं। एनआईओएस सेंटर खुलने के बाद 41 बंदियों ने पढ़ाई के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें 12 बंदी इंटर और 29 बंदी हाईस्कूल की पढ़ाई करेंगे। रायबरेली के अलावा अमेठी जिले के बंदी भी इस जेल में हैं, क्योंकि अमेठी में फिलहाल जिला कारागार की सुविधा नहीं है। अधिकारियों का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा बंदी इस योजना से जुड़ें।

कॉपी-किताब मिलते ही शुरू होगी पढ़ाई : जेलर हिमांशु रौतेला के मुताबिक एनआईओएस द्वारा बंदियों को कॉपी, किताब व अन्य पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सामग्री मिलते ही पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी। शिक्षा विभाग से दो शिक्षकों की मांग की गई है। तब तक हाईस्कूल और इंटर पास बंदी ही अन्य बंदियों को पढ़ाएंगे।

सुधार की दिशा में सार्थक कदम : जेल अधीक्षक प्रभात सिंह ने बताया कि एनआईओएस एक मान्यता प्राप्त बोर्ड है, जो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करता है। इसका सेंटर जेल में शुरू हो गया है। शिक्षा के जरिए बंदियों की सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा और वे जेल से रिहा होने के बाद समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।

एक साल में 74 पेंशनर अपात्र, 4614 की मौत

रायबरेली, चसं। जिले में वृद्धावस्था पेंशनरों के वार्षिक सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में है। कुल 1,18,379 पेंशनरों में से अब तक 95 प्रतिशत का सत्यापन पूरा हो चुका है। सत्यापन के दौरान 74 पेंशनर अपात्र पाए गए हैं, जबकि 4614 पेंशनरों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। अपात्र पाए गए पेंशनरों में अधिकांश वे हैं जिनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी मिल गई है, या जिनकी उम्र निर्धारित मानक (60 वर्ष) से कम है। सत्यापन पूरा होने के बाद जून माह में पात्र पेंशनरों के खातों में अगली पेंशन किस्त भेजी जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी सृष्टि अवस्थी ने सभी खंड विकास अधिकारियों (एडीओ) को सात दिन के भीतर सत्यापन कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं, ताकि समय से पेंशन वितरित की जा सके।

रेलवे साइडिंग की सड़क बदहाल, वाहनों के पलटने का खतरा

रायबरेली, चसं। शहर के रेलवे स्टेशन के निकट स्थित रेलवे साइडिंग की सड़क बदहाल हो चुकी है। ऐसे में कभी भी ट्रक पलटने से बड़ा हादसा हो सकता है। साइडिंग के पास तेज धूप और बारिश से बचने के लिए पर्याप्त शेड की व्यवस्था नहीं है। पानी के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। इन समस्याओं के लिए कई बार उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका है। स्टेशन के निकट स्थित यह रेलवे साइडिंग रूपामऊ साइडिंग के नाम से जानी जाती है। करीब 900 मीटर लंबी साइडिंग की रेल लाइन है, जिस पर मालगाड़ी की 58 बोगियां खड़ी हो सकती हैं। रेल लाइन के किनारे लगभग 700 मीटर का प्लेटफार्म बना है। मजबूती के लिए रेलवे ट्रैक के स्लीपर बिछाए गए हैं। पूर्वी छोर की तरफ करीब 50 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त है। मिट्टी धंसने की वजह से स्लीपर टूट गए हैं और गड्ढे बन गए हैं। इसके अलावा भी कई जगह गड्ढे हैं। इसी प्लेटफार्म पर ट्रक खड़े होते हैं, ताकि मालगाड़ी से सामान ट्रकों में रखा जा सके। आसपास बसे मोहल्लों के लोगों के आवागमन का रास्ता भी इसी प्लेटफार्म से होकर गुजरता है। इससे हादसे का अंदेशा बना रहता है। इतनी लंबी साइडिंग में सिर्फ नाम के लिए करीब 40 फुट का शेड लगा है, जहां मवेशियों का डेरा रहता है। शेड के पास ही इकलौता हैंडपंप लगा है। हैंडपंप के पानी का उपयोग हाथ-मुंह धोने में ज्यादा किया जाता है। प्रकाश की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। साइडिंग पर औसतन रोजाना रोज एक मालगाड़ी आती है। दर्जनों ट्रक आते-जाते रहते हैं। ट्रक चालकों, क्लीनरों, अनलोडिंग व लोडिंग करने वाले मजदूरों को ज्यादा परेशानी होती है। धूप से बचने के लिए मजदूर ट्रक के नीचे बैठने को मजबूर होते हैं। वाणिज्य निरीक्षक डीडी शुक्ला का कहना है कि रूपामऊ साइडिंग पर काफी समस्याएं हैं। सड़क सही कराने, शेड लगवाने, पानी के इंतजाम के लिए मंडल स्तरीय अधिकारियों को पत्र भेजा है।

भरे जाएंगे गड्ढे, क्रॉसिंग पर लगेगा सबमर्सिबल : रूपामऊ साइडिंग पर सड़क के गड्ढे भरवाने के साथ ही पेयजल की समस्या दूर करने के लिए सबमर्सिबल लगवाया जाएगा। रेलवे के वरिष्ठ खंड अभियंता (कार्य) विजय श्रीवास्तव का कहना है कि प्लेटफार्म वाले हिस्से में कई जगह गड्ढे होने की जानकारी है। ट्रकों के पटलने का खतरा रहता है। इसीलिए इस हफ्ते काम शुरू कराया जाएगा। साइडिंग वाली क्रॉसिंग पर पेयजल की समस्या का हल निकालने के लिए सबमर्सिबल लगाने की योजना भी बनाई गई है। इस पर जल्दी ही काम शुरू कराएंगे। शेड लगवाने का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है। अगर उच्चाधिकारियों का आदेश मिला तो शेड भी लगवाएंगे।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री ने मऊ में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर जताया शोक

लखनऊ, चसं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने दिवगंतों के परिजनों को अनुमन्य राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के भी निर्देश दिए हैं।

नवचयनित 494 सहायक अध्यापक एवं 49 प्रवक्ताओं का होगा नियुक्ति पत्र वितरण

लखनऊ, चसं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए लोक सेवा आयोग के विज्ञापन-2018 के माध्यम से 494 सहायक अध्यापक संवर्ग, जिसमें 258 महिला एवं 236 पुरुष है। विज्ञापन-2020 के माध्यम से 49 प्रवक्ता संवर्ग, जिसमें 15 महिला 34 पुरुष हैं। इस प्रकार कुल 543 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को 08 मई, 2025 गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा पूर्वाह्न 10:00 बजे, लखनऊ लोकभवन स्थित सभागार में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना प्रस्तावित है।

आजाद समाज पार्टी का शर्मा चाय पर प्रदर्शन दुकानदार ने हाथ जोड़कर माफी मांगी

लखनऊ, चसं। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को आजाद समाज पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। हजरतगंज स्थित शर्मा चाय वाले की दुकान पर पहुंच कर नारेबाजी किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पार्टी के प्रदेश सचिव अनिकेत धानुक ने कहा कि शर्मा चाय के दुकानदार संविधान विरोधी है। एक वायरल वीडियो में यह स्पष्ट हुआ कि यह संविधान को नहीं मानते। शर्मा चाय की दुकान पर बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। इसके बाद शर्मा चाय के दुकानदार ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि संविधान सर्वश्रेष्ठ है। प्रदर्शनकारियों के सामने उन्होंने कहा कि संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं और हम लोग संविधान मानते हैं। विगत कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें शर्मा चाय के दुकानदार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मनुस्मृति ऊपर है। संविधान उसके बाद है। उन्होंने कहा था कि हम पहले मनुस्मृति को मानते हैं। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर चौतरफा विरोध शुरू हो गया था। सोशल मीडिया पर शर्मा चाय का बायकाट करने की मुहिम भी चलाई गई थी। इसी वायरल वीडियो को संज्ञान लेते हुए आजाद समाज पार्टी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अनिकेत धानुक ने कहा कि संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। संविधान किसी एक धर्म और जाति का नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए सर्वोपरि है। जो लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, दरअसल वह लोग भारत का विरोध कर रहे हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं किया जाएगा, जो संविधान और देश विरोधी हैं। यह देश संविधान से चलता है और चलेगा। हर व्यक्ति को संविधान को मानना पड़ेगा।

पीडीए-बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर, होर्डिंग लगाकर कसा तंज

लखनऊ, चसं। लखनऊ में सियासी दलों के बीच में पोस्टर वॉर जारी है। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले के बाद भाजपा मुख्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई गई है। भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने होर्डिंग में लिखवाया है-जातीय जनगणना की उठाई आवाज अब बताओ कौन जात? जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में लगातार पोस्टर वॉर हो रहा है। भाजपा मुख्यालय के बाहर होर्डिंग ने इसे तूल दे दिया है। होर्डिंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर है। होर्डिंग के माध्यम से सीधे तौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जाति पूछी गई है। अमित त्रिपाठी ने कहा जातीय जनगणना जब होगी तो सबको अपनी जाति बतानी पड़ेगी। राहुल के दादा अपने नाम के आगे फिरोज खान लिखते थे। अब राहुल गांधी किस जाती से है देश को बताएं। उन्होंने कहा इसी प्रकार मुलायम सिंह यादव अपने नाम के साथ सिंह लिखते थे। अखिलेश यादव बताएं कि वो सिंह है या यादव। यह दोनों ही नेता जो जोर-जोर से जातीय जनगणना की बात करते थे। अब अपनी जाति नहीं बता रहे हैं। इसलिए हम लोग पोस्टर लगवा कर इनकी जाति पूछ रहे हैं। लोकसभा सदन के दौरान जब अखिलेश यादव से जाति पूछी गई थी तब वह भड़क गए थे। मगर अब पूरे देश को जाती बतानी पड़ेगी।

डीपीएस एल्डिको में अलंकरण समारोह

लखनऊ, चसं। राजधानी लखनऊ के पीजीआई इलाके स्थित एल्डिको उद्यान कॉलोनी के दिल्ली पब्लिक स्कूल में मंगलवार को अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर जयदीप यादव उपस्थित रहे। समारोह में विद्यालय की प्रधानाचार्या मनीषा अंथवाल ने चयनित छात्रों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। इस दौरान छात्रों ने विद्यालय के विभिन्न विभागों से जुड़े दायित्वों की शपथ ली। कार्यक्रम में अकादमिक समन्वयक नेहा रस्तोगी और प्रधानाध्यापिका वंदना खरे भी मौजूद रहीं। प्रधानाचार्या ने चयनित छात्र प्रतिनिधियों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी छात्र अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर निर्वहन करेंगे और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे।

संविदा कर्मचारियों की छंटनी से संघ नाराज

लखनऊ, चसं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में संविदा कर्मचारियों की छंटनी का विरोध किया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा,संविदा कर्मचारी संघ का आरोप है कि प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल पूर्व एमडी के आदेशों को नहीं मान रही हैं। वह आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। दरअसल, वर्ष 2017 में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 20 और शहरी क्षेत्रों में 36 कर्मचारियों की तैनाती का आदेश जारी हुआ था। एमडी रिया केजरीवाल ने इसे घटाकर 12.5 और 18.5 कर दिया है।

ग्रामीण महिलाओं के आजीविका संवर्धन कार्यों में लायी जाय तेजी : उपमुख्यमंत्री

स्वयं सहायता समूहों को प्रभावी बनाकर, दीदियों को बनाया जाये आत्मनिर्भर व स्वावलंबी

चर्चित राजनीति। विशेष संवाददाता

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण महिलाओं के आजीविका संवर्धन कार्यों में और तेजी लायी जाय।स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय व प्रभावी बनाकर समूहों से जुड़ी दीदियों को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने की ठोस कार्यवाही की जाय।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि समूहों द्वारा निर्मित सामग्री की ब्रांडिंग करने व उनके विपणन की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाय। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में गति लाने के लिए जरूरी है कि योजनाओ व कार्यक्रमो की नियमित रूप से गहन समीक्षा की जाय। योजनाओं की ग्राउंड रियलिटी पता करने व उन्हें धरातल पर प्रभावी तरीके से उतारने के लिए जरूरी है कि फील्ड भ्रमण किया जाय और सम्बन्धित अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही फिक्स की जाय। उन्होंने समूहों की सक्रियता पर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश दिए हैं।राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार में 884845 लाख स्वयं सहायता समूह एवं 61484 हजार ग्राम संगठन का गठन किया गया है जिसमे काफी संख्या में समूहों तथा ग्राम संगठनों का सखी ऐप पर प्रोफाइल का अंकन नहीं हो पाया है। जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

समूह सखियों को सक्रिय किए जाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक दीपा रंजन ने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं,जो समूह सखी किन्ही कारणवश निष्क्रिय हो गयी है, उनके स्थान पर अन्य सक्षम महिला को नियमानुसार समूह सखी का चयन कराते हुए निर्धारित प्रारूप पर मिशन मुख्यालय को अवगत कराया जाय। समस्त उपायुक्त स्वतः रोजगार को भी निर्देशित किया गया है कि वह इस कार्य को पूरी गम्भीरता व संवेदनशीलता के साथ कराना सुनिश्चित करें।

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के तहत 12 अरब 55 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति की प्रदान : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि हेतु वर्ष 2025-26 में विधान सभा के 403 मा0 सदस्यों हेतु रू0 100750.00 लाख (रू0 दस अरब सात करोड पचास लाख मात्र, जी0एस0टी0 सहित) की धनराशि तथा विधान परिषद के 100 में से 99 (01 स्थान रिक्त हैं) मा0 सदस्यों हेतु रू0 24750.00 लाख (रू0 दो अरब सैतालीस करोड़ पच्चास लाख मात्र जी एस टी सहित)की धनराशि अर्थात विधान मण्डल के कुल 502(403+99) मा0 सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम किश्त के रूप में रू0 250.00 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की दर से कुल रू0 125500.00 लाख जी0एस0टी0 सहित (रू0 बारह अरब पचपन करोड़ मात्र, जी0एस0टी0 सहित) की धनराशि अवमुक्त किया जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं कि स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था, प्राविधानों तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार ही किया जाय। ज्ञातव्य है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अन्तरित की जाने वाली धनराशि 50 प्रतिशत की दर से 02 किश्तों में निर्गत की जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

योगी सरकार नवंबर में करेगी दुधवा महोत्सव

लखनऊ, चसं। योगी सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा महोत्सव कराने का निर्णय लिया है। दुधवा महोत्सव नवंबर में होगा। यह प्रदेश का पहला आवासीय सांस्कृतिक एवं वन्यजीव महोत्सव है। तीन दिवसीय महोत्सव-25 न सिर्फ प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और जैविक समृद्धि का उत्सव होगा बल्कि पर्यटकों को जंगल की गोद में प्रकृति से जुड़ने और थारू संस्कृति को करीब से जानने का मौका भी देगा। देश की जानी मानी हस्तियों द्वारा परफॉर्मेंस भी दी जाएगी।प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरुप प्रदेश को बहुआयामी पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए नवंबर में महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें 2,000 से अधिक पर्यटक शामिल होंगे। महोत्सव का केंद्र सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक दृश्य, ग्रामीण पर्यटन, थारू जनजाति की विरासत, उनका खानपान, हस्तशिल्प, औषधीय ज्ञान और जीवनशैली होगा।

सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार सृजक बनाना और पारम्परिक उद्योगों को प्रोत्साहित करना है

- मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने 'उद्यमिता विकास की ओर उत्तर प्रदेश' कार्यक्रम का किया शुभारम्भ
- कौशल विकास मंत्री ने 'हुनर मित्र' पत्रिका के प्रवेशांक का किया विमोचन

चर्चित राजनीति। संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने मंगलवार को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ के मार्स ऑडिटोरियम में आयोजित उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा उद्यमिता विकास की ओर उत्तर प्रदेश विषयक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास से जुड़े समस्त स्टेकहोल्डर, जिसमें सेक्टर स्किल काउंसिल, उद्योग, उद्यमी, सरकार तथा एकेडमिक्स सम्मिलित है, को एक मंच पर लाकर कौशल विकास मिशन कार्यक्रमों को सही दिशा में लागू करने की राजनीति का निर्धारण करना था।

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मंत्री अग्रवाल ने सबसे पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और इस जघन्य कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सरकार हर मोर्चे पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कौशल विकास, रोजगार सृजन और युवाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में युवाओं के कौशल विकास, रोजगारपरकता और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की पूर्ति में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की अहम भूमिका होगी। इसके लिए सरकार उद्योग जगत से नवाचार, कौशल विकास में निवेश और सहभागिता बढ़ाने का आह्वान कर रहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार खोजने वाला (जॉब सीकर) के बजाय रोजगार सृजक (जॉब क्रिएटर) बनाना है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे प्राप्त हो रहे प्रशिक्षण को गंभीरता से लेकर अपने कौशल को निखारें। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि पारंपरिक स्वदेशी उद्योगों को भी प्रोत्साहित करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश के युवाओं को प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। कार्यक्रम के दौरान कौशल विकास मंत्री ने हुनर मित्र पत्रिका के प्रवेशांक का विमोचन किया और मिशन द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने प्रशिक्षण में निपुणता लाकर प्रदेश व देश की आर्थिक प्रगति में सहभागी बनें। इस अवसर पर प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि औद्योगिक प्रतिष्ठान, नियोजक और अन्य हितधारक रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु मिशन के साथ भागीदारी करें ताकि उद्योगों की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित युवा उपलब्ध कराए जा सकें। अपने समापन भाषण में प्रमुख सचिव द्वारा उद्यमशीलता के महत्व को रेखांकित करते हुए कौशल विकास को उद्यमिता उन्मुख बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने उद्यमिता के संबंध में निहित जोखिम के मिथकपूर्ण भय पर विजय पाने हेतु युवाओं को प्रेरित किया। उनके द्वारा इसी प्रकार के कार्यक्रम लगातार कराए जाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि कार्यक्रम में रिलायबल फर्स्ट एडकॉन प्राइवेट लिमिटेड, क्वेस कॉर्प, गकोंडेस एक्सपोर्ट्स, और सरन्या हेल्थ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड सहित 22 औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ आपसी सहमति पत्र और आशय पत्र हस्ताक्षरित किए गए हैं। इससे 26,811 युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सेवायोजित प्रशिक्षणार्थियों नीता पासवान, ओमप्रकाश, आंचल (सुल्तानपुर) और जया (मिर्जापुर) ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भरता और रोजगार के बेहतर अवसर मिले हैं। कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर केंद्रित विचार-विमर्श भी आयोजित हुआ, जिसका संयोजन संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार ने किया। विचार-विमर्श में लखनऊ विश्वविद्यालय, सेक्टर कौशल परिषद, परियोजना क्रियान्वयन अभिकरण व औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रोफेसर खेमंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रशिक्षण परिणाम आधारित होना चाहिए। मोटर वाहन क्षेत्र के विशेषज्ञ विक्रम सिंह ने विद्यालय-कॉलेज स्तर पर कौशल आधारित कार्यक्रमों की आवश्यकता बताई। कृष्ण कुमार ने ग्रामीण युवाओं में संवाद क्षमता व आत्मविश्वास की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए व्यक्तित्व विकास व संवाद कौशल पर विशेष ध्यान देने की बात कही। विशेषज्ञों द्वारा स्कूल स्तर से ही विद्यार्थियों को उद्यमिता के बारे में जागरूक करने तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में इंडस्ट्री के प्रतिभाग पर विशेष जोर दिया गया। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एस्पिरेशनल बनाने तथा प्रशिक्षकों की इंटर्नशिप करने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव भी विशेषज्ञों से प्राप्त हुए। कार्यक्रम में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बाराबंकी, गोरखपुर तथा बुलंदशहर के प्रधानाचार्य को उनकी उत्तम निष्पादन हेतु सम्मानित भी किया गया साथ ही पांच उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रशिक्षण प्रदाताओं व प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को भी सम्मानित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के मुख्य परिचालन अधिकारी आशीष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

लोक निर्माण राज्य मंत्री ने उप्र राजकीय निर्माण निगम के कार्यों की समीक्षा बैठक की

लखनऊ, चसं। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने निर्माण निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा अवशेष कार्यों को तीव्र गति से कराते हुए निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाये। निगम का टर्नओवर बढाये जाने हेतु कार्य अर्जन पर विशेष ध्यान दिया जाये ताकि निगम की पुरानी ख्याती पुनः वापस आ सके। लोक निर्माण राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने यह निर्देश आज यहाँ उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के मुख्यालय स्थित सभागार में निगम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दिए। इस अवसर उन्होंने निर्माण निगम द्वारा निगम द्वारा कराए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति जानकारी ली और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु विभिन्न स्तर पर चेकिंग के निर्देश दिए। लोक निर्माण राज्य मंत्री ने निर्देश दिया कि निगम द्वारा कराए जा रहे कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी स्तर पर कोई अनियमितता पाए जाने पर संबंधित की जवाबदेही तय करते हुए कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने निर्माण निगम की निर्माणाधीन परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई इस संबंध में उन्होंने निर्देश दिया कि निगम कार्यों में पारदर्शिता व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यो को पूर्ण कराया जाए। लोक निर्माण राज्य मंत्री ने निर्देश दिया कि निगम द्वारा जिन परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है, उन परियोजनाओं को जल्द से जल्द संबंधित विभागों को हैण्डओवर किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं की प्रगति 75 प्रतिशत से ऊपर है उनको शीघ्र पूर्ण कर सम्बन्धित विभाग को हस्तगत करते हुए जनोपयोगी बनाया जाये। जिन कार्यों की प्रगति 50 फीसदी से कम है उनकी प्रगति बढ़ाते हुए नियमित समीक्षा की जाये। बैठक में अवगत कराया गया कि निगम में कुल 15 अंचल कार्यरत है जिनके अन्तर्गत 67 इकाईयां विभिन्न जनपदों में कार्य कर रही है। निगम द्वारा विभिन्न 96 विभागों की रू0 19288 करोड़ लागत की 1029 परियोजनाएं निर्माणाधीन है जिसमें प्रदेश के अन्दर 56 विभागों की रू0 13447 करोड़ लागत की 828 परियोजनाएं तथा प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में 46 विभागों की रू0 5841 करोड़ लागत की 201 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न 34 विभागों की रू0 4613 करोड़ लागत की 411 परियोजनाएं पूर्ण करायी गयी है। बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अजय चौहान, लोनिवि के प्रमुख अभियंता (परिकल्प एवं नियोजन) श्रीराज, प्रमुख अभियंता ग्रामीण सड़क ए के द्विवेदी, एमडी राजकीय निर्माण निगम विजय कन्नौजिया के साथ निर्माण निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

प्रशिक्षण का हिस्सा होंगे आम लोग और छात्र

लखनऊ, चसं। नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा इस अभ्यास में आम नागरिकों, खासकर छात्रों को सिविल डिफेंस के बुनियादी कौशल सिखाए जाएंगे। इनमें प्राथमिक चिकित्सा, आग बुझाना, संचार के साधनों का उपयोग, शेल्टर में जाना और दूसरों की मदद करना शामिल है।नागरिक सुरक्षा विभाग के डीजी अभय प्रसाद ने बताया कि राज्य के 15 जिलों में सिविल डिफेंस विभाग के कार्यालय हैं, जो कुल 26 जिलों को कवर करते हैं।इनमें प्रमुख तौर पर लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे शहर शामिल हैं। मॉक ड्रिल के दौरान परखा जाएगा कि घायल लोगों को अस्पताल तक ले जाने, प्राथमिक उपचार देने और आपात सेवा से जोड़ने की व्यवस्था कितनी कारगर है।विभाग का मकसद युद्ध जैसी स्थिति में आम जनता को मानसिक रूप से तैयार करना है। ड्रिल सिर्फ सरकारी तैयारियों की जांच भर नहीं, बल्कि आम नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी का भी परीक्षण है।

सात बजते ही यूपी में बजेंगे सायरन, छा जाएगा अंधेरा

लखनऊ, चसं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में युद्ध से बचाव के लिए एक बार फिर मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू हो गई है। कल 7 मई को पूरे प्रदेश में यह अभ्यास किया जाएगा, जिसमें आम नागरिकों को हवाई हमले, ड्रोन अटैक और मिसाइल हमले जैसी स्थितियों से बचाव की जानकारी दी जाएगी। ड्रिल करीब 54 वर्षों बाद हो रही है। 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान इस तरह की मॉक ड्रिल कराई गई थी। अब दोबारा केंद्र सरकार ने राज्य को निर्देशित किया है कि संभावित युद्ध या आपात स्थिति के समय नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। इस मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट यानी पूर्ण अंधकार की रणनीति भी लागू की जाएगी। इसका मतलब, हमले के समय सभी घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों की लाइटें बंद कर दी जाएंगी

उत्तर रेलवे

ई–निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य विद्युत अभियन्ता, कर्मशाला, उत्तर रेलवे, सवारी एवं माल डिब्बा कारखाना, आलमबाग, लखनऊ निर्धारित प्रपत्र पर निम्नलिखित कार्यों हेतु मोहरबन्द निविदायें आमंत्रित करते है।

1	निविदा सूचना संख्याः–	विद्युत / डब्ल्यू० / आलमबाग / 201 / 2025–26			
क	कार्य का विवरणः कैरेज एण्ड वैगन वर्कशाप, आलमबाग, लखनऊ में आउट आफ वारंटी 25 किलोवॉट ई0आर0आर0यू0 के नवीनीकरण का कार्य।				
ख	अनुमानित लागत	रू० 49,92,934 / –	ग	धरोहर राशि	रू० 99,900 / –
घ	निविदा प्रपत्र मूल्य	शून्य	ड.	कार्य समापन अवधि	12 माह
अन्य सूचना					
2	निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि एवम समय	30.05.2025 को अपरान्ह 15:00 बजे तक।			
3	निविदा खुलने की तिथि व समय	30.05.2025 को अपरान्ह 15:00 बजे के बाद।			

● निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है तथा निर्धारित तिथि के अनुसार भरा जा सकता है। ● मैनुअल आफ़र पर विचार नहीं किया जायेगा। ● निविदाकर्ता निविदा फार्म की धरोहर राशि का भुगतान केवल www.ireps.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान प्रणाली द्वारा ही किया जायेगा। डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / डिपॉजिट रसीद / एफ०डी०आर० या अन्य किसी रूप में निविदा धरोहर धनराशि का भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। ● प्रस्तावों के खुलने के बाद अतिरिक्त दस्तावेज़ की प्रस्तुति एवं उससे संबन्धित निविदा उपरान्त किसी प्रकार के पत्राचार स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निविदादाता के निविदा उपरान्त पत्रों को भी शून्य एवं प्रभावहीन माना जायेगा। **निविदा संख्याः– विद्युत / डब्ल्यू० / आलमबाग / 201 / 2025–26 दिनांक–06.05.2025** 1341/2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

एकेटीयू के इनोवेशन हब द्वारा यूथ इनोवेशन फेयर-2025 कार्यक्रम का हुआ आयोजन

चर्चित राजनीति। संवाददाता

लखनऊ। इनोवेशन हब डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में यूथ इनोवेशन फेयर-2025 का आयोजन किया गया। जिसमें छात्रों ने अपने नवाचारों और स्टार्टअप विचारों को प्रस्तुत किया।

डीन इनोवेशन एवं सोशल इंटरप्रेन्योरशिप प्रो. बी. एन. मिश्रा के नेतृत्व तथा एसोसिएट डीन डॉ. अनुज कुमार शर्मा की उपस्थिति में युवाओं के नवाचार मेला 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे मुख्य अतिथि के रूप में वित्त अधिकारी केशव सिंह उपस्थित रहे एवं विशेष अतिथि श्री पवन कुमार यादव, समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जे. पी. पांडेय के मार्गदर्शन में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत डा अनुज कुमार शर्मा ने किया एवं संचालन अनुराग त्रिपाठी, असिस्टेंट इनक्यूबेशन मैनेजर ने किया। महीप सिंह, हेड इनोवेशन् हब ने छात्रों को आइडियाज से स्टार्टअप तक की यात्रा में आने वाली समस्याओं एवं उसके समाधान के तरीके बताए। कार्यक्रम विश्वविद्यालय में कार्यरत स्टार्टअप फ्यूचर गुरुकुल के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन फ्यूचर गुरुकुल के फाउंडर एवं को फाउंडर अविनाश मिश्र एवं अभिषेक मिश्र ने किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में नवाचार की भावना को जागृत करना और उन्हें अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें स्टार्टअप पिचिग, मॉडेल का प्रस्तुतिकरन, रोबोटिक्स काम्पिटिशन जैसे रोबोरेस, लाइन फालोअर रेस, रोबोमेज, रोबो सॉकर, डिबेट, और ड्रोन उड़ान प्रतियोगिताएँ शामिल थीं। कार्यक्रम में 16 विभिन्न स्कूल्स के कुल लगभग 400 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया जिसमे 20 स्टार्टअप्स भी शामिल थे जिन्होंने स्कूल के विद्यार्थियों की मेन्टरिंग की एवं इनोवेशन् से स्टार्टअप में जाने के तरीके बताए। कार्यक्रम के अंत में, विजेताओं को पुरस्कार एवं सर्टिफिकेट का वितरण सुश्री वंदना शर्मा की उपस्थिति में डा अनुज कुमार शर्मा द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त, ए के टी यू के कलाम पेटेंट सेंटर के माध्यम से इनोवेटिव प्रोडक्टस को निःशुल्क पेटेंट की सुविधा का विकल्प दिया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को सफल बनाने के लिये प्री-ट्रायल बैठक सम्पन्न

लखनऊ, चसं। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ प्री-ट्रायल बैठक का आयोजन पुराना उच्च न्यायालय स्थित मीडिएशन सेंटर, लखनऊ में किया गया। बैठक का उद्देश्य आगामी 10 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण की प्रभावी रणनीति तैयार करना रहा। यह बैठक विशेष न्यायाधीश सीबीआई सेंट्रल / नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ श्रीमती बबीता रानी के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। इस अवसर पर अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ मीनाक्षी सोनकर के साथ मुख्य विकास अधिकारी श्री अजय जैन, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) हनुमान प्रसाद मौर्य, अपर नगर आयुक्त श्री पंकज श्रीवास्तव, उप मुख्य चिकित्साधिकारी के.डी. मिश्रा सहित कुल 30 विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिला प्रोबेशन विभाग, ऊर्जा विभाग (नेडा), श्रम, पंचायती राज, ग्रामीण विकास प्राधिकरण, दिव्यांगजन कल्याण, महिला कल्याण, खाद्य, राजस्व, सिंचाई, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक कल्याण, नगर निगम, आयुष, जल निगम, उद्यान, बचत, लोक निर्माण, विद्युत, समाज कल्याण, सेवा योजना, युवा कल्याण, बेसिक शिक्षा, लखनऊ विकास प्राधिकरण, क्रीड़ा और सूचना विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक के दौरान विभिन्न विभागों में लंबित वादों की समीक्षा की गई एवं आगामी लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करने पर बल दिया गया। साथ ही, राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। नोडल अधिकारी ने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विवादों के आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से त्वरित निस्तारण हेतु एक वैकल्पिक मंच उपलब्ध कराना है। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। लोक अदालत की प्रक्रिया सरल, सुलभ और पक्षकारों के आपसी सहमति पर आधारित होती है।

अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। याद रखें- अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है : सुभाषचंद्र बोस

संपादकीय

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की तेज हुई मांग

राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और कांग्रेस में अनगिनत मुद्दों पर मतभेद हैं लेकिन जब भी बात पश्चिम बंगाल की आती है तो दोनों पार्टियों के स्थानीय नेता एक ही सुर में बोलते हुए नजर आते हैं। पश्चिम बंगाल में नेता चाहे कांग्रेस पार्टी के हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के, दोनों ही एक ही सुर में राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते रहते हैं। पश्चिम बंगाल में दोनों ही दलों के स्थानीय नेताओं का यही आरोप रहता है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और ममता बनर्जी सही तरीके से सरकार चला नहीं पा रही है। बीजेपी की केंद्र में सरकार होने के बावजूद राज्य भाजपा के नेता लगातार पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते रहते हैं। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रदेश के नेता पिछले कुछ वर्षों के दौरान, कई बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुके हैं। हालांकि कई वजहों से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए गठबंधन की सरकार ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से बचती रही है। दरअसल, बीजेपी को सबसे बड़ा डर यह सताता रहता है कि अगर उनकी केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त कर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की फिर से जीत सुनिश्चित हो जाएगी। यही वजह है कि राज्य की सरकार पर हिंसा करवाने, बीजेपी नेताओं पर हमला करवाने, विरोधी नेताओं पर हमला करवाने, हिंदुओं पर हमला करवाने और कट्टरपंथी ताकतों को ब?ावा देने जैसे गंभीर आरोप लगाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में राष्टपति शासन नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की एक रिपोर्ट ने केंद्र सरकार की दुविधा को बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, राज्यपाल ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद इलाके में हुई हिंसा की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कट्टरपंथ और उग्रवाद की दोहरी समस्या राज्य के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। रिपोर्ट में बांग्लादेश के साथ लगते पश्चिम बंगाल के दो जिलों- मुर्शिदाबाद और मालदा में हालात भयावह तौर पर खराब होने का जिक्र किया गया है। अपनी रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी सवाल उठाते हुए हिंसा की पूरी जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन, बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में केंद्रीय बलों की चौकियां स्थापित करने जैसे कई अहम सुझाव दिए हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन की तरफ इशारा करते हुए यह कह कर सनसनी फैला दी है कि,हालात बिगड़ने पर संविधान के अनुच्छेद- 356 के तहत प्रावधान भी विकल्प बने रहेंगे। अनुच्छेद-356 यानी राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल ने सीधे तौर पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश तो नहीं की है लेकिन यह जरूर लिख दिया है कि अगर राज्य में स्थिति और ज्यादा बिगड़ती है तो केंद्र संविधान के अनुच्छेद-356 के प्रावधानों को लागू करने पर विचार कर सकती है। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2026 यानी अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी जोर-शोर से चुनाव की तैयारियों में जुटी हई है। पार्टी आलाकमान का यह दावा है कि इस बार बीजेपी राज्य में सरकार बनाने जा रही है।

देश में ऑनलाइन लूडो के बढ़ते खतरे पर कैसे लगेगी लगाम

> सितंबर 2024 में, तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी (टीएनओजीए) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा देने के लिए लगभग आधा दर्जन यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और एक निजी फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।टीएनओजीए ने इन सोशल मीडिया हस्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए और उनके जवाबों से असंतुष्ट होने पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, सैदापेट में कानूनी कार्यवाही शुरू की। यदि दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है।खबरों के अनुसार, कुछ फिल्म हस्तियां जो पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को ब?ावा देने में शामिल थीं, वे भी जांच के दायरे में हैं।

रमेश, एक मध्यमवर्गीय परिवार का साधारण युवक था। शहर के एक निजी कंपनी में मामूली वेतन पर काम करता और अपने छोटे से परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। उसकी दिनचर्या काम से घर और कभी कभार दोस्तों के साथ चाय पीने तक ही सीमित थी। लेकिन कुछ महीने पहले, उसके एक सहकर्मी ने उसे ऑनलाइन लूडो के एक ऐप के बारे में बताया। शुरुआत में रमेश ने इसे सिर्फ मनोरंजन का एक साधन समझा। काम से लौटने के बाद या खाली समय में वह दोस्तों या अनजान लोगों के साथ लूडो खेलता, और कभी-कभार छोटी-मोटी बाजी भी लगा लेता। शुरुआत में सब कुछ रोमांचक और मजेदार लग रहा था। जीत की खुशी और हार का मामूली गम, यह सब उसकी नीरस जिंदगी में एक नया रंग भर रहा था। धीरे-धीरे, रमेश इस खेल का आदी होता चला गया। अब वह काम के दौरान भी चोरी-छिपे लूडो खेलने लगा था, और घर पर परिवार को कम समय देता था। उसकी पत्नी अक्सर शिकायत करती कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा, हमेशा फोन में ही घुसा रहता है। रमेश इन बातों को अनसुना कर देता, उसे तो बस अगली बाजी जीतने की धुन सवार रहती थी। एक दिन, रमेश ने एक बड़े दांव पर अपनी महीने भर की कमाई लगा दी। उसे पूरा भरोसा था कि वह जीत जाएगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वह बुरी तरह हार गया। इस हार ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह घर कैसे चलाएगा और अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा। रातों की नींद उड़ गई, और वह हर समय उदास और चिड़चिड़ा रहने लगा।

रमेश अकेला नहीं था जो इस ऑनलाइन लूडो के जाल में फंसा था। भारत में ऑनलाइन लूडो का चलन तेजी से बढ़ रहा है, खासकर युवाओं और कम आय वर्ग के लोगों के बीच। इसकी आसान उपलब्धता और कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के लालच ने लाखों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यह सिर्फ एक खेल नहीं रह गया है, बल्कि एक तरह का नशा बन गया है जो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ऑनलाइन लूडो के कई खतरे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला खतरा है आदत लगना और लत में बदलना। यह खेल इतना आकर्षक और आसान है कि लोग आसानी से इसके आदी हो जाते हैं। लगातार खेलने की इच्छा और हर बार जीतने की उम्मीद उन्हें घंटों तक स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर देती है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। नींद की कमी, आंखों में दर्द, तनाव और चिंता जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। दूसरा बड़ा खतरा है वित्तीय नुकसान। ऑनलाइन लूडो में अक्सर पैसे की बाजी लगाई जाती है। जीतने का लालच लोगों को अपनी जमा पूंजी और यहां तक कि कर्ज लेकर भी दांव लगाने के लिए प्रेरित करता है। हारने पर उन्हें भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां लोगों ने कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या तक कर ली है। तीसरा खतरा है सामाजिक अलगाव। जो लोग ऑनलाइन लूडो के आदी हो जाते हैं, वे धीरे-धीरे अपने परिवार और दोस्तों से दूर होने लगते हैं। उन्हें वास्तविक दुनिया से कोई सरोकार नहीं रह जाता और वे अपनी आभासी दुनिया में ही खोए रहते हैं। इससे उनके सामाजिक संबंध कमजोर हो जाते हैं और वे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। चौथा खतरा है धोखाधड़ी और जालसाजी। ऑनलाइन लूडो प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां खिलाड़ियों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। कुछ ऐप गैरकानूनी तरीके से काम करते हैं और खिलाड़ियों से पैसे ऐंठ लेते हैं। इसके अलावा, कुछ खिलाड़ी हैकिंग या अन्य गलत तरीकों का इस्तेमाल करके दूसरों को हराते हैं, जिससे ईमानदार खिलाड़ियों को नुकसान होता है। अब सवाल यह उठता है कि इस ऑनलाइन लूडो के बढ़ते खतरे पर लगाम कैसे लगाई जाए? इसके लिए कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है।

सबसे पहले लोगों को ऑनलाइन लूडो के खतरों के बारे में जागरूक करना होगा। इसके लिये सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को मिलकर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताना चाहिए। मीडिया भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लोगों को यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि एक गंभीर लत बन सकता है जो उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन लूडो प्लेटफॉर्म को कानूनी दायरे में लाना जरूरी है। सरकार को ऐसे नियम और कानून बनाने चाहिए जो इन प्लेटफॉर्म की गतिविधियों को नियंत्रित करें और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करें। सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए लाइसेंसिंग और विनियमन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि धोखाधड़ी और जालसाजी को रोका जा सके। ऑनलाइन लूडो ऐप्स में ऐसे फीचर होने चाहिए जो खिलाड़ियों को अपनी खेलने की सीमा निर्धारित करने और समय-समय पर ब्रेक लेने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐप्स में एक चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए जो खिलाड़ियों को अत्यधिक खेलने या पैसे गंवाने पर सतर्क करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके लत लगने के शुरुआती लक्षणों का पता लगाया जा सकता है और खिलाड़ियों को समय पर सहायता प्रदान की जा सकती है। ऑनलाइन लूडो की लत के जो लोग शिकार हो चुके हैं, उन्हें मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना भी जरूरी है।

सरकार को नशा मुक्ति केंद्रों और हेल्पलाइन नंबरों की स्थापना करनी चाहिए जहां ऐसे लोग मदद मांग सकें। परिवार और दोस्तों को भी ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए और उन्हें इस लत से बाहर निकलने में मदद करनी चाहिए। इसके अलावा माता-पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे ऑनलाइन लूडो या किसी अन्य हानिकारक ऑनलाइन गेम के आदी न हों। बच्चों को स्क्रीन टाइम को सीमित करने और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बहरहाल, विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन लूडो और अन्य ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने वाले स्टार प्रचारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की खबरें भी सामने आती रहती हैं। **:: एजेंसी**

पाकिस्तान को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में वापस लाने की रणनीति

भारत पाकिस्तान के खिलाफअपने कूटनीतिक हमले को तेज कर रहा है,और अब वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट में इस्लामाबाद को फ्रि से सूचीबद्ध कराने के लिए प्रयास कर रहा है। ट्रम्प के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन से समर्थन की असामान्य रूप से मजबूत अभिव्यक्ति द्वारा समर्थित यह नया प्रयास, सीमा पार आतंकवाद में अपनी निरंतर मिलीभगत के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने के लिए नयी दिल्ली द्वारा एक रणनीतिक कदम में तेजी को दर्शाता है। एफएटीएफ ग्रे लिस्ट- जिसे औपचारिक रूप से बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार के रूप में जाना जाता है- में पहले 2018 से 2022 तक पाकिस्तान शामिल था, जिससे देश को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण चौनलों पर गहन जांच के अधीन किया गया था। उस चार साल की अवधि में इस्लामाबाद ने अंतरराष्ट्रीय दबाव के तहत वित्तीय सुधारों को लागू करने के लिए संघर्ष किया, और इसने विदेशी निवेश, ऋण और विकास सहायता तक पाकिस्तान की पहुंच को काफी हद तक बाधित किया। 2022 में डीलिस्टिंग इस दक्षिण एशियाई राष्ट्र के लिए एक कूटनीतिक और आर्थिक सफलता थी, जिसने पाकिस्तान की पहले से ही लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को जीवन रेखा प्रदान की और वैश्विक वित्तीय संस्थानों के साथ नये सिरे से जुड़ाव को सक्षम किया। भारत अब उस लाभ को उलटने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को एफएटीएफके निशाने पर वापस लाने का प्रयास तेज हो गया।

हालांकि इस्लामाबाद ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने एफएटीएफ के प्रमुख सदस्य देशों को नयी खुफिया जानकारी दी है, जिसमें वित्तीय बहाव का विवरण शामिल है जो कथित तौर पर हमले के अपराधियों को पाकिस्तान स्थित फंड प्रदाता संस्थानों से जोड़ता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, डोजियर में सैटेलाइट इमेजरी, इंटरसेप्ट किये गये संचार और लेन-देन रिकॉर्ड शामिल हैं जो जम्मू और कश्मीर में चरमपंथी गतिविधियों से जुड़े धन के सीमा पार प्रवाह का संकेत देते हैं। उद्देश्य स्पष्ट हैरू यह प्रदर्शित करना कि पाकिस्तान आतंकवाद वित्तपोषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहा है, और इस प्रकार एफएटीएफकी बढ़ी हुई निगरानी व्यवस्था में पाकिस्तान की वापसी को उचित ठहराया जा सकता है। नये भू-राजनीतिक गठबंधनों के कारण इस प्रयास में तेजी आने की संभावना है। दक्षिण एशिया पर हाल ही में अमेरिका की अस्पष्टता से उल्लेखनीय रूप से हटकर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पहलगाम की घटना के बाद भारत के सभी रूपों में आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने के अधिकार का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है। पेरिस में एफएटीएफ

> भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल और वैश्विक प्रभाव बढ़ने के साथ, यह आज खुद को बहुपक्षीय मंचों को प्रभावित करने के लिए सात साल पहले की तुलना में अधिक मजबूत स्थिति में पाता है। इसके अलावा, इजरायल-गाजा युद्ध, यूक्रेन संघर्ष और अफ्रीका और एशिया में फिर से उभर रही जिहादी गतिविधि से आकार लेने वाले वैश्विक सुरक्षा वातावरण ने आतंकवाद को फिर से अंतरराष्ट्रीय चिंता के केंद्र में ला दिया है, जिससे भारत के तर्कों के लिए ग्रहणशीलता का माहौल बन रहा है।

मुख्यालय में भारत की वर्तमान पैरवी कथित तौर पर फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका के समन्वय में की जा रही है- वे देश जिन्होंने पहले पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद वित्तपोषण सुधारों के आधे-अधूरे कार्यान्वयन पर निराशा व्यक्त की थी। कहा जाता है कि भारतीय राजनयिक यह मामला बना रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद वित्तपोषण गतिविधियों को सक्षम करने या अनदेखा करने की स्पष्ट पुनरावृत्ति न केवल एक क्षेत्रीय खतरा है, बल्कि एक वैश्विक खतरा भी है, विशेष रूप से अफगानिस्तान में तालिबान के पुनरुत्थान और व्यापक मध्य पूर्व में बढ़ती अस्थिरता पर चिंताओं के मद्देनजर। एफएटीएफकी अगली पूर्ण बैठक जून में होने वाली है और सूत्रों का कहना है कि भारत इस समयसीमा में ही काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाकिस्तान की अनुपालन स्थिति के मुद्दे को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा जाये। यह रणनीति पाकिस्तान के लिए विशेष रूप से कमजोर समय पर आयी है, जिसकी अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन और घटते विदेशी भंडार के बोझ तले दबी हुई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ देश की मौजूदा व्यवस्था 2025 के मध्य में समाप्त हो रही है, और नये बचाव कोष के लिए बातचीत कठिन होने की उम्मीद है। एफएटीएफ की ग्रे सूची में पाकिस्तान को फिर से शामिल करने का कोई भी कदम इन वार्ताओं को गंभीर रूप से जटिल बना देगा, जिसके परिणामस्वरूप ऋण की शर्तें सख्त हो सकती हैं या वितरण में देरी हो सकती है। इसके अलावा, अपर्याप्त धन शोधन नियंत्रण वाले क्षेत्राधिकार के रूप में टैग किये जाने से प्रतिष्ठा को होने वाला नुकसान निजी निवेशकों को हतोत्साहित करेगा और ऐसे समय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को और ठंडा कर देगा जब इस्लामाबाद पूंजी आकर्षित करने के लिए बेताब है। इसके निहितार्थ केवल वित्तीय ही नहीं हैं। इस तरह के कदम से देश में राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है, जो पहले से ही तीव्र घरेलू उथल-पुथल और चल रहे नागरिक-सैन्य तनावों से जूझ रहा है। इस्लामाबाद जोर देकर कहता है कि उसने अपनी पिछली ग्रे लिस्टिंग के दौरान एफएटीएफद्वारा अनिवार्य सभी 34 कार्रवाई मदों का पूरी तरह से पालन किया है और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिए एक मजबूत ढांचा बनाये रखना जारी रखा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत पर संकीर्ण भू-राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय प्लेटफार्मों का फायदा उठाने का भी आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि इस तरह की कार्रवाइयों से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। फिर भी, कूटनीतिक वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान की विश्वसनीयता पिछली कई तिमाहियों से अस्थिर बनी हुई है, खासकर पिछले उदाहरणों के बाद जब यह पाया गया कि यह प्रमुख सुधारों को लागू करने में अपने पैर खींच रहा है या अपनी धरती पर सक्रिय संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने में विफल रहा है। जैसे-जैसे एफएटीएफअपने मध्य-वर्ष सत्र की तैयारी कर रहा है, दांव बढ़ते जा रहे हैं। भले ही कुछ सदस्य देश एक तकनीकी निकाय के राजनीतिकरण से सावधान हों, लेकिन 2018 का उदाहरणकृजब भारत ने आतंकवाद के वित्तपोषण पर चिंताओं के बीच पाकिस्तान को ग्रे लिस्टिंग में डालने के लिए सफलतापूर्वक पैरवी की थीकृयह बताता है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और कूटनीतिक समन्वय तकनीकी अस्पष्टता पर भारी पड़ सकते हैं। **:: एजेंसी**

गरीब की दवा

कई बार समाचार सुनने-पढ़ने को मिलते हैं कि परिजनों के गंभीर व असाध्य रोगों के महंगे इलाज की वजह से लाखों लोग गरीबी की दलदल में डूब गए। कोरोना संकट के दौरान भी लोगों द्वारा घर, जमीन व जेवर बेचकर अपनों की जान बचाने की कोशिश की खबरें मीडिया में तैरती रही। लेकिन सामान्य दिनों में दवा कंपनियों की मिलीभगत व दबाव में लिखी जाने वाली महंगी दवाइयां भी गरीबों को टीस दे जाती हैं। इसके बावजूद कि बाजार में उसी साल्ट

वाली गुणवत्ता की जेनेरिक दवा सहज उपलब्ध है। कुछ समय पहले केंद्र सरकार की ओर से जेनेरिक दवाइयां लिखने की अनिवार्यता के निर्देश का अच्छा-खासा विरोध हुआ, जिसके चलते निर्णय वापस लेना पड़ा था। अब इसी चिंता को देश की शीर्ष अदालत ने अभिव्यक्त किया है। दरअसल, बीते शुक्रवार को दवा कंपनियों की मुनाफखोरी के कारोबार से बढ़ती दवाओं की कीमतों के बाबत एक मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि डॉक्टर केवल जेनेरिक दवाइयां ही लिखना प्रारंभ कर दें, तो दवा कंपनियों व चिकित्सकों के अपवित्र गठबंधन को तोड़ा जा सकता है। निस्संदेह, तरह-तरह के प्रलोभन व परोक्ष-अपरोक्ष लाभ देकर दवा कंपनियां चिकित्सकों पर महंगी दवा लिखने का दबाव बनाती हैं। जिसकी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ती है, जो महंगी दवा खरीदने की क्षमता नहीं रखते। ऐसे में वे कर्ज लेकर या अपने रिश्तेदारों से मदद लेकर किसी तरह गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों का इलाज कराते हैं। इस खर्च के दबाव के चलते परिजनों को भी तमाम कष्ट उठाने पड़ते हैं। गाहे-बगाहे सरकारों ने दवा कंपनियों की बेलगाम मुनाफखोरी रोकने को कदम उठाने की घोषणाएं तो कीं, लेकिन समस्या का सार्थक समाधान नहीं निकल पाया। चिकित्सा बिरादरी की तरफसे भी यदि इस दिशा में सहयोग मिलने लगे तो इस समस्या का समाधान किसी सीमा तक संभव हो सकता है। लेकिन विडंबना है कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक संकट यह भी है कि दवा कंपनियों द्वारा प्रचार किया जाता है कि जेनेरिक दवाइयां रोग के उपचार में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं होती।

निस्संदेह, सरकारों को इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा कि जेनेरिक दवाइयों को प्रोत्साहन देने के उसके प्रयास क्यों सिरे नहीं चढ़ते। एक वजह यह भी है कि दवा कंपनियों की लॉबी खासी ताकतवर होती है और साम-दाम-दंड-भेद की नीति का उपयोग करके अपने उत्पादों का विपणन करने में सफ्ल हो जाती है। ऐसे आक्षेपों से चिकित्सा बिरादरी भी दोषमुक्त नहीं हो सकती, जो दवा कंपनियों के लोभसंवरण से मुक्त नहीं हो पाती। सरकारों को देखना चाहिए कि दवा कंपनियों द्वारा पोषित कदाचार पर नियंत्रण के प्रयास जमीनी हकीकत क्यों नहीं बन पाते। यदि ये कदम सख्ती से उठाए जाएं तो गरीब मरीज गंभीर रोगों का उपचार करने में सक्षम हो पाएंगे। फ्रि उनके अपनों का इलाज उनकी क्षमता के अनुरूप हो सकेगा। निःस्संदेह, लंबे उपचार व असाध्य रोगों के इलाज में दवाओं की कीमत एक प्रमुख घटक होता है। यदि दवा नियंत्रित दामों में मिल सके तो उनकी बड़ी चिंता खत्म हो सकती है। निस्संदेह, दवाओं की कीमत हमारी चिकित्सा सेवाओं के लिये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकार को चाहिए कि गांव से लेकर शहरों तक जेनेरिक दवाओं के मेडिकल स्टोर बड़ी संख्या में खोले जाएं। मरीजों के तिमारदार उन तक आसानी से पहुंच सकें। इस काम में स्वयं सेवा समूहों की मदद ली जा सकती है ताकि गरीब-अनपढ़ मरीजों को जागरूक करके जेनेरिक दवाइयों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। मरीजों के परिजनों को विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि जेनेरिक दवाइयां भी उसी साल्ट से बनी होती हैं, जिससे महंगी ब्रांडेड दवाइयां बनी होती हैं।

दुनिया भर में आ सकती है चीनी माल की बाढ़

हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा के एक सप्ताह से भी कम समय में, 8 अप्रैल 2025 को 75 देशों पर अपने पारस्परिक टैरिफ को रोक दिया, लेकिन इस रोक में एकमात्र अपवाद था चीन, जिस पर ट्रम्प ने पहले 125 प्रतिशत टैरिफ लगाया, जिसे बाद में बढ़ाकर 245 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसे हम दंडात्मक टैरिफ भी कह सकते हैं, क्योंकि चीन ने राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा पारस्परिक टैरिफ का जवाब देने का विकल्प चुना है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपने पोस्ट में ट्रम्प ने कहा, 'चीन ने विश्व के बाजारों के प्रति जो सम्मान नहीं दिखाया है, उसके आधार पर, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए जाने वाले टैरिफ को तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 125 फीसदी कर रहा हूं।

उम्मीद है कि निकट भविष्य में किसी समय चीन को एहसास होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों को लूटने के दिन अब टिकाऊ या स्वीकार्य नहीं हैं।' हालांकि, अमेरिका को छोड़कर भारत समेत किसी भी देश ने चीन पर टैरिफ नहीं बढ़ाया है, लेकिन अधिकांश देश, चीन द्वारा की जाने वाली डंपिंग से चिंतित हैं, जिससे उनके घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। डंपिंग का मतलब है कम दामों पर सामान बेचना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भाषा में डंपिंग तब होती है, जब कोई देश या कंपनी अपने घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में कम कीमत पर उत्पाद का निर्यात करती है। डंपिंग को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दुरुपयोग माना जाता है। चीन ने डंपिंग की इस कला में महारत हासिल कर ली है, इसे

> उद्योगों की कई विनिर्माण इकाइयां चीनी डंपिंग के कारण बंद होने की कगार पर पहुंच गई। और सरकार के ठोस प्रयासों के बावजूद ये उद्योग चीन से अनुचित प्रतिस्पर्धा की छाया से बाहर नहीं आ पाए। हालांकि भारत सरकार का दावा है कि वह वैश्विक बाजारों में उभरती स्थितियों पर कड़ी नजर रख रही है, लेकिन उद्योग चीन द्वारा संभावित डंपिंग प्रयासों से सभी चिंतित हैं।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उद्देश्य आयात करने वाले देशों के घरेलू उद्योग को खत्म करना है और एक बार जब कोई देश चीनी सामग्रियों पर निर्भर हो जाता है, तो फिर उसका शोषण शुरू हो जाता है। सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) का मामला चीनी डंपिंग और शोषण के जीते जागते उदाहरण हैं। 2004 के बाद, पेनिसिलिन जी और फोलिक एसिड सहित कई प्रकार की एपीआई को भारतीय बाजारों में बेहद कम कीमतों पर डंप किया गया। इस खेल में न केवल भारतीय एपीआई उद्योग को खत्म कर दिया गया, बल्कि देश की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया गया। मार्च में, भारत ने घरेलू उद्योगों को चीनी डंपिंग से बचाने के लिए चार चीनी वस्तुओं- सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्यूमीनियम पन्नी और ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया था। एंटी-डंपिंग शुल्क 276 अमेरिकी डॉलर से लेकर 1732 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक है और यह पांच साल के लिए है, जबकि एल्यूमीनियम पन्नी पर छह महीने का अस्थायी शुल्क लगाया गया है। इससे पहले 2024 में ही, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) द्वारा दायर एंटी-डंपिंग जांचों में से 79 प्रतिशत चीनी उत्पादकों के खिलाफ दायर की गई थीं। यह ध्यान देने योग्य है कि डीजीटीआर भारत में व्यापार उपायों की जांच और सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है, जो अन्य उपायों के साथ-साथ डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की भी सिफारिश करता है। चीन पहले से कहीं ज्यादा डंप क्यों करेगा? कारण यह है कि अमेरिकी टैरिफ के बाद, चीन के लिए अमेरिका को इतनी आसानी से निर्यात करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए चीन निश्चित रूप से अपने उत्पादों को अन्य बाजारों में डंप करने के लिए मजबूर होगा। सर्वप्रथम चीन के पास बहुत अधिक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है, जिससे अधिशेष उत्पादन होता है। कुछ बाजारों में बेचने की क्षमता, चीन को अन्य बाजारों में समान सामग्री डंप करने के लिए मजबूर करती है। चीन का ध्यान हमेशा निर्यात आधारित विकास पर रहा है, जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त है। दूसरे, चीनी कंपनियों को अन्य रूपों में सब्सिडी और सरकारी सहायता मिलती है, जिससे वे अपने उत्पादों को कृत्रिम रूप से कम कीमतों पर बेच पाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकारी सब्सिडी बाजार की कीमतों को विकृत करती है और अनुचित प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। तीसरे, व्यापार तनाव भी वैकल्पिक बाजारों पर किसी तरह नियंत्रण करने के चीनी खेल का हिस्सा है। चीनी डंपिंग को लेकर आशंकाएं बेवजह नहीं हैं। अतीत में, ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जब चीन ने भारत समेत विदेशी बाजारों में डंपिंग की अनैतिक प्रथा अपनाई। अतीत में, हमारा एपीआई उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम उद्योग, कपड़ा और परिधान उद्योग, खिलौना उद्योग और कई अन्य उद्योग चीनी डंपिंग का शिकार रहे हैं। **:: चर्चित डेस्क**

आज का राशिफल

मेषः- नकारात्मक चिन्ताओं को त्याग कर अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। नौकरी-पेशे में अधिकारियों व सहकर्मियों के सहयोग से वातावरण सुखद होगा। राजनैतिक क्षेत्र के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा।

वृषभः- शासन-सत्ता के लोगों के साथ निकटता बढ़ेगी। नियोजित परिश्रम द्वारा कार्य सिद्धी के आसार बनेंगे। पुराने संबंधों से लाभ संभव। परिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा।

मिथुनः- कठिन एवं विषम परिस्थितियों के मध्य परिश्रम व लगन से प्रगति के ओर अग्रसर होंगे। समाजिक सक्रीयता से मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घरेलू दायित्वों के प्रति आपकी महत्ता बढ़ेगी।

कर्कः- कुछ भौतिक आकांक्षाएं अपनी सार्थकता हेतु मन को उद्वेलित करेंगी। निकटस्थ सम्बन्धों में भावनात्मक अपेक्षाएं कष्टकारी हो सकती है। तामसी व गैर कार्यो पर आकर्षित मन पर अंकुश लगावें।

सिंहः- कुछ नई इच्छाएं बलवती होंगी। प्रयासरत् क्षेत्रों में संघर्ष संभव परन्तु निराशावादी विचारों को मन में स्थान न दें। किसी बड़े आयोजन हेतु समुचित व्यवस्था के लिए मन प्रयत्नशील होगा।

कन्याः- नई सफलताओं से खुद की क्षमताओं का ऐहशास होगा। जीविका क्षेत्र में अवरोधों से मन में निराशा संभव भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यय की अपेक्षित है। सन्तत्ति एवं सन्तानोत्पत्ति के लिए प्रयास सार्थक होंगे।

तुलाः- किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लाएगी। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव। दुविधाओं को त्याग कर सही व स्वच्छ योजनाओं पर केन्द्रित हों।

वृश्चिकः- कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मन पर प्रभावी होंगी। घरेलू कार्यो में व्यस्तता बढ़ेगी। परिजनों के सहयोग से मन उत्साहित होगा। हंसमुख स्वभाव से आस-पास वातावरण में प्रसन्नता बिखेरेंगे।

धनुः- सम्बन्धों में व्यवहारकुशल बनें। समाजिक व मांगलिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी संभव। कुछ महत्वपूर्ण प्रयत्न की सार्थकता आप में नए उत्साह का संचार करेगा।

मकरः- विद्यार्थियों के लिए ग्रहों की अनुकूलता लाभप्रद होगी। कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं सार्थक होगी। नवीन आशाएं नवीन उत्साह लाएंगी। कार्य क्षेत्र में सम्बन्धों का भरपूर लाभ मिलेगा।

कुम्भः- अर्न्तमुखी स्वभाव को त्याग बहिरमुखी बनें। कुछ महत्वपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति के आसार हैं। परिजनों के सुख-दुख के प्रति मन चिन्तित होगा। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी।

मीनः- पुरानी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सुखद अनुभूति करेंगे। ग्रहों की अनुकूलता से कोई अवरोधित कार्य हल होने के आसार बनेंगे। समुचित परिश्रम करने में असमर्थ मन परेशान होगा।

राशि रत्न

बिलग्राम में सर्राफा व्यापारी ने की आत्महत्या

बिलग्राम/हरदोई, चसं। नगर के मंडई मोहल्ले में 29 वर्षीय सर्राफा व्यापारी मिथुन गुप्ता ने सोमवार देर रात पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि मिथुन, जो बीजीआरएम इंटर कॉलेज के सामने सर्राफा और कपड़े की दुकान चलाते थे, रात को दुकान बंद कर घर लौटे थे। खाना खाने के बाद वे अपने कमरे में गए और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज सुन परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खोला, जहां मिथुन का शव और पास में लाइसेंसी बंदूक मिली। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया और फोरेंसिक जांच शुरू की गई। मिथुन की पत्नी प्रिया और 14 दिन की नवजात बेटी परिवार में हैं। हाल ही में बच्ची के जन्म की खुशी मना रहे परिवार के लिए यह घटना सदमे का सबब बन गई। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के अनुसार, आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है और जांच जारी है। परिजनों का कहना है कि मिथुन ने कभी कोई मानसिक परेशानी जाहिर नहीं की थी। इस घटना ने नवजात बेटी और पत्नी के भविष्य पर गहरा आघात पहुंचाया है।

सफाई कार्य में लापरवाही पर की जाएगी सख्त कार्यवाही : नसरीन बानो

नगरपालिका बोर्ड की बैठक में 30 लाख का बजट पास

चर्चित राजनीति। संवाददाता

शाहाबाद/हरदोई। नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक नगरपालिका सभागार में पालिकाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बोर्ड बैठक में सड़क निर्माण, नाली निर्माण, प्रकाश, सफाई व्यवस्था व अन्य मूलभूत सुविधाओं तथा विकास कार्यों के लिए कई प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किए गए।

पालिका अध्यक्ष नसरीन बानो ने बोर्ड बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि अटल अमृत योजना के तहत पाइप लाइन पड़ने से नगर की सड़कों की खुदाई के कारण सड़के काफी खराब स्थित में पहुंच गई है जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस योजना का कार्य पूरा होने के बाद नगर के सभी मार्गों का बेहतर निर्माण करवाया जाएगा।बैठक में विभिन्न मोहल्लों में खराब पड़े नलों को बोर्ड फंड से रिबोर करवाने का प्रस्ताव भी पास हुआ।पालिका अध्यक्ष ने कहा कि वार्डो की साफ सफाई व्यवस्था का उचित ध्यान रखा जाये इसके लिए वार्ड के सुपरवाइजर सजग रहे और बरसात से पहले नगर के नालो और नालियों की सफाई व्यवस्था समुचित करवाई जाये।अगर सफाई से जुडी कोई शिकायत आती है तो सम्बंधित कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाही की जाएगी।इस दौरान बर्ष 2025-2026 की आय व व्यय का बजट पास किया गया।जिसमें पालिका की आय 77 करोड़ 82 लाख रुपये तथा व्यय 77 करोड़ 52 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया।इस प्रकार कुल 30 लाख का लाभ का बजट ध्वनि मत से पास हुआ।बोर्ड बैठक मे बिना आपत्ति वाले मानचित्रो को स्वीकृति दी गई।बोर्ड बैठक में बजट विवरण सुनाते हुए प्रभारी अधिशासी अधिकारी दीपक कुमार द्वारा सभी बिंदुओं का विस्तृत ब्यौरा दिया गया।इस बैठक मे लक्ष्मी त्रिपाठी,अजहर मसूद,अतुल मिश्रा, रिजवान अली उर्फ कल्लू,आदित्य गौतम, रतिराम, सुष्मिता,नैना कुशवाहा अहिवरन, प्रीति, महनूर जवी,पूनम गुप्ता, इमरान खा,इच्छाराम शर्मा आदि सभासद मौजूद रहे। लेखाकार असद खां,राजस्व निरीक्षक अनस खां,जे ई विजय कृष्ण यादव मौजूद रहे।

वक्फ सुधार जन जागरण के तहत जिला पंचायत सभागार में अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद का आयोजन सम्पन्न

चर्चित राजनीति। संवाददाता

हरदोई। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत जिला पंचायत सभागार में अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद का आयोजन हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी पवन सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यालय प्रभारी असरार अहमद मौजूद रहे। अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने की।

अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद को संबोधित करते हुए एमएलसी पवन सिंह ने कहा, मुस्लिम समुदाय को वक्फ बोर्ड द्वारा पूरी तरह लूटा गया है। गरीब पसमांदा मुस्लिम समाज के लिए बना वक्फ बोर्ड भारत का सबसे बड़ा घोटाला बन चुका है। बड़े-बड़े मॉल होटल व्यवसाय की इमारते वक्फ की जमीनों पर फल फूल रही हैं लेकिन गरीब मुसलमान को कुछ नहीं मिला। धार्मिक नेताओं एवं राजनेताओं के एक बड़े गुट ने वक्फ संपत्तियों को लूटकर आम मुसलमान को बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया है। 31 फीसदी मुसलमान आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है जबकि लाखों करोड़ की वक्फ सम्पतियों द्वारा उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया गया है। 80 परसेंट वक्फ संपत्तियां भ्रष्टाचार एवं अतिक्रमण की शिकार हो गई हैं। प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के असरार अहमद ने बताया ,कर्नाटक में 22000 एकड़ वक? भूमि 2 लाख करोड रुपए में बेची गई। वक्फ बोर्डों द्वारा आम गरीब मुसलमान की जमीन कब्जा की जा रही हैं लखनऊ में वक्फ बोर्ड ने पुनर्विकास के नाम पर सैकड़ो मुस्लिम परिवारों की दुकाने छीन ली ,बिना किसी मुआवजे बिना किसी अधिकार के।

जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने कहा, 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड वक्फ बाय यूजर के तहत मामूली जांच के उपरांत एकतरफा वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते थे, इससे मनमाने ढंग से कई संपत्तियों को वक्फ घोषित करने के कई प्रकरण सामने आए। मोदी सरकार ने वर्तमान वक्फ अधिनियम में वक्फ द्वारा मनमाने ढंग से अतिक्रमण करने तथा जवाबदेही एवं पारदर्शिता बढ़ाने के प्रावधान किए हैं। संवाद कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला महामंत्री एवं अभियान के जिला संयोजक अनुराग मिश्रा, सह संयोजक गोपामऊ अध्यक्ष वली अहमद, संजय सिंह गुड्डू, असद इराकी आदि मौजूद रहे।

कलयुगी पुत्र ने ईंट से कुचलकर की पिता की हत्या

चर्चित राजनीति। संवाददाता

हरदोई। बेनीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में शराब के लती एक कलयुगी पुत्र ने सोते समय अपने पिता की ईंट से कुचल कर हत्या कर दी।सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हरदोई भिजवाया है।पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

प्राप्त विवरण में 6 मई की रात को डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि महावीर पुत्र घनश्याम लोधी निवासी ग्राम गोखुरा पुरवा मजरा करीमनगर थाना बेनीगंज को उनके पुत्र राहुल ने सिर पर ईट से वार कर घायल कर दिया। सूचना पर पीआरवी 2735 व थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घायल महावीर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोथावां में भर्ती कराया गया जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।पुलिस द्वारा शव का नियमानुसार पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना बेनीगंज पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की।थाना बेनीगंज के प्रभारी निरीक्षक कृष्ण बली सिंह और पुलिस बल द्वारा आरोपी राहुल को नियमानुसार हिरासत में लिया गया है।

सेप्टी टैंक में मिला वृद्धा का शव, पड़ोसी युवक हिरासत में

हरदोई, चसं। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के नानक गंज झाला में एक घर के बाथरूम के बगल में बने सेप्टी टैंक में एक वृद्धा का शव पुलिस ने बरामद किया है।मृतका के परिजनों द्वारा पड़ोसी युवक पर हत्या करने का आरोप लगाया है।पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। प्राप्त विवरण में 5 मई को कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम नानकगंज झाला में 60 वर्षीय रामबेटी पत्नी बेचेलाल का शव घर में बने स्नान घर के पास सेप्टी टैंक में मिलने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर अंकित मिश्रा एवं स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं स्थानीय पुलिस द्वारा शव का नियमानुसार पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण कर पोस्टमार्टम भेजा गया। फील्ड युनिट द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतका के परिजनों से वार्ता की गयी एवं संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये।मृतका रामबेटी के पुत्र जगत राम की तहरीर के आधार पर कोतवाली देहात पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई।कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित आरोपी धनीराम को नियमानुसार हिरासत में लिया गया है। अभियुक्त शराब के नशे में है। अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है।आरोपी धनीराम व मृतका एक ही परिवार के है। आरोपी मृतका का भतीजा लगता है।पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया है।

भागवत कथा में कथा व्यास ने सुनाया कंस वध और गोपियों का विरह

चर्चित राजनीति। संवाददाता

हरदोई। ब्लॉक भरखनी के सहसोगा गांव में लखनौर ग्राम पंचायत के प्रधान अजय सिंह चौहान ने सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान कराया है।भागवत कथा के छठे दिन की कथा में कथा व्यास ने भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन करते हुए कंस वध, अधर्म पर धर्म की विजय,और भगवान का गोकुल से द्वारिका का प्रस्थान करना,उनके जाने पर गोपियों का बिरह और श्री राधा रानी का वियोग की करुणामई कथा का रसपान करवाया।

गोपियों का बिरह और करुण क्रंदन और श्री राधा रानी का विलाप सुनकर उपस्थित दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। गोपियों को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं, जो गोपियों को समझाते हैं, कि वो निराकार परमब्रह्म की उपासना करें।तब गोपियां उद्धव जी से कहती है, कि हमें तो श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता। गोपिया ऊधौ से कहती हैं,

उद्धव मन् ना भये दस बीस। एक हतो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस ऊधौ मन् ना भये दस बीस। हमारे पास दस बीस मन नहीं है, एक था, जो श्री कृष्ण के साथ चला गया, अब हम कौन सा हृदय लेकर उस पारब्रह्म निराकार ईश्वर की पूजा करें। और गोपियां रो रो के ऊधव से कहती हैं,

शिथिल भई सबहि माथो बिनु जथा देह बिन शीश उद्धव मन ना भये दस बीस। हे उद्धव जिस प्रकार शरीर के बिना सर का कोई महत्व नहीं रहता उसी प्रकार कृष्ण के बिना हम प्राण विहीन हैं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। गोपियों का करुण क्रंदन सुनकर उद्धव जी भी रो पड़ते हैं, और वहां से वापस द्वारिका आ जाते हैं। गोपियों का बिरह वर्णन कथा व्यास ने इस प्रकार सुनाया कि वहां पर उपस्थित सभी दर्शक रो पड़े,और मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रीय लोग लखनौर के प्रधान अजय सिंह चौहान सपरिवार भागवत कथा में उपस्थित रहे।

युवक ने किशोरी से किया दुष्कर्म

हरदोई, चसं। थाना पिहानी व विकासखंड हरियावां क्षेत्र के एक गांव निवासी 11वर्षीय किशोरी के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़ित किशोरी की शिकायत पर परिजनों ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि किशोरी जानवरों की घास लेने के लिए खेतों में गई थी। तभी पड़ोस में रहने वाला युवक पहुंचा और किशोरी को अकेला पाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया।किसी तरह आरोपी युवक के चंगुल से निकल कर घर पहुंचकर अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजन किशोरी के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी विद्यासागर पाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे दबोच लिया जाएगा। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीम में गठित की गई है।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई राजस्व कार्यों की बैठक

चर्चित राजनीति। संवाददाता

हरदोई। विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि पाँच वर्ष से अधिक पुराने सभी वादों का निस्तारण किया जाये।

धारा 24 के सभी वादों के निस्तारण में समय सीमा का ध्यान रखा जाये। पैमाइश के प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाये। धारा 34 के 5 वर्ष से अधिक पुराने वादों के निस्तारण की अच्छी प्रगति होने पर जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बचा हुआ एक मामला भी जल्द निस्तारित किया जाये। उन्होंने कहा कि वरासत के प्रकरणों को त्वरित गति से निस्तारित किया जाये। अंश निस्तारण से सम्बंधित वादों को लम्बे समय तक न खींचा जाये। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी व सभी सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

निजी स्कूलों में फीस वृद्धि की शिकायतों को लेकर अभिभावक संघ जिलाधिकारी से मिला, कार्यवाही का आश्वासन : निजी स्कूलों में फीस वृद्धि स्कूलों की फीस वृद्धि आदि शिकायतों को लेकर अभिभावक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज फिर जिलाधिकारी से मिला। फीस वृद्धि को लेकर कुछ स्कूलों की रसीदें साक्ष्य में दी। जिलाधिकारी ने शीघ्र कार्यवाही करने को कहा। गौरतलब हो, अभिभावक संघ ने जिलाधिकारी को गत 07 अप्रैल को निजी स्कूलों की कई समस्याओं और शिकायतों को लेकर एक 12 सूत्रीय ज्ञापन दिया था। जिस पर कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी ने गत 11 अप्रैल को कलक्ट्रेट सभागार में निजी स्कूलों, शिक्षा अधिकारियों व अभिभावक संघ की एक बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने निजी स्कूलों के प्रशासकों को समस्याओं और शिकायतों के निदान को लेकर कतिपय सुझाव भी दिए। जिलाधिकारी ने अभिभावक संघ को भी समस्याओं और शिकायतों पर विस्तारित प्रतिवेदन साक्ष्य सहित देने को कहा था।

अभिभावक संघ इस बीच दो बार जिला विद्यालय निरीक्षक से मिला और उन्हें विस्तारित प्रतिवेदन व स्कूल फीस की रसीदों को साक्ष्य के रूप में दिया और कार्यवाही की माँग की।निजी स्कूलों की समस्याओं और शिकायतों के निस्तारण की धीमी प्रगति देखते हुए आज मंगलवार को अभिभावक संघ की ओर से अध्यक्ष गोपाल द्विवेदी व संरक्षक राकेश पाण्डेय व शिव प्रकाश त्रिवेदी प्रतिनिधिमंडल के रूप में जिलाधिकारी से मिले और एक प्रतिवेदन के साथ पूर्व में दिए ज्ञापन व स्कूल फीस में वृद्धि के साक्ष्य के तौर पर रसीदें प्रस्तुत की। इन रसीदों के अनुसार निजी स्कूलों ने फीस वृद्धि में उत्तरप्रदेश स्ववित्तपोषित निजी स्कूल (शुल्क विनिमयन) 2018 का स्पष्ट उल्लंघन है। जिलाधिकारी ने शीघ्र कार्यवाही का भरोसा दिया।

ग्राम प्रधानों, अधिकारियों के संरक्षण के चलते सफाई कर्मी बेलगाम, ग्राम सभाओं की सफाई व्यवस्थाएं चौपट

कछौना/हरदोई, चसं। विकासखंड कछौना की 41 ग्राम सभाओं की सफाई व्यवस्था सफाई कर्मियों के नियमित रूप से रोस्टर के अनुसार सफाई न होने के कारण ग्राम सभा सहित सार्वजनिक भवनों, पंचायत घर, परिषदीय स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, आरोग्य केंद्रों में गंदगी अम्बार है। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं कागजों पर सीमित है। सामुदायिक शौचालय में ताला लटका रहता है। आरसीसी सेंटर शोपीस बने हैं। घर-घर कूड़ा उठाने व प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने का अभियान सीमित संसाधनों के कारण हवा-हवाई है। जिसके कारण गांव में जगह-जगह कू? के ढेर, नालियों में कचरा, स्कूलों के शौचालय में गंदगी के कारण नौनिहालों सहित मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। गंदगी के कारण संक्रामक बीमारी फैलने की प्रबल संभावना रहती है। गांव की बदरंग तस्वीर हो जाती है।

क्षेत्रीय विकास जन आंदोलन के संयोजक रामखेलावन कनौजिया ने कहा आखिरी सफाई कर्मी नियमित रूप से सफाई कार्य क्यों नहीं करते हैं? उनकी जवाब देही क्यों तय नहीं होती है? उनकी उपस्थिति को ग्राम प्रधानगण फर्जी तरीके से क्यों प्रमाणित करते हैं? ग्राम सभा में तैनाती के बावजूद सहकारी स्कूलों में रसोइयों के सहारे सफाई व्यवस्था क्यों है? ग्राम प्रधान व अधिकारियों के संरक्षण के चलते सफाई कर्मी बेलगाम है। सामुदायिक शौचालय में महिला समूहों को केयर टेकर के रूप में नियुक्त किया गया है, लेकिन ज्यादातर ग्राम प्रधानों ने अपनी भूमिका व गांव से काफी दूर सामुदायिक शौचालय को बनवाया है। जिसके कारण आम नागरिकों को लाभ नहीं मिल पाता है। कुछ सफाई कर्मी ग्राम सभा में तैनाती स्थल पर कार्य न करके ब्लॉक मुख्यालय, जिले पर, अधिकारियों के ड्राइवर व अर्दली के रूप में सेवा दे रहे हैं। क्षेत्रीय विकास जन आंदोलन के संयोजक ने बताया सफाई कर्मियों की हाजिरी रजिस्टर स्कूलों में रखी जाए अथवा बायोमेट्रिक उपस्थिति पंचायत घर में सुनिश्चित की जाए। क्षेत्रीय विकास जन आंदोलन के संयोजक रामखेलावन कनौजिया ने ग्राम सभा में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जिला प्रशासन से निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी है। सफाई कर्मियों के नाम व आवंटन गांव का नाम, मोबाइल नंबर, आवंटन गांव में सफाई कर्मियों का रोस्टर प्लान, माहवार पैरोल की छायाप्रति, अटैचमेंट आदि बिंदुओं पर सूचनाओं मांगी है। ग्राम प्रधानगणों का अधिकारियों के संरक्षण के चलते ग्राम सभाओं की व्यवस्थाएं चौपट हैं। गंदगी का अंबार रहता है। नालियां बजबजाती है। लोगों को जीना दुश्वार है।

संक्षिप्त समाचार

बाइक समेत दो जेबकतरों को हरपालपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, 34300 रूपये किए बरामद

हरपालपुर/ हरदोई, चसं। स्थानीय पुलिस ने दो जेबकतरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 34300 बरामद किए हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की है। प्रभारी निरीक्षक बालकृष्ण मिश्रा ने बताया कि की 21 अप्रैल को अरवल थाना क्षेत्र के चंद्रमपुर गांव स्थित अपनी बहन के यहां ई-रिक्शा से जा रहे कन्नौज जिले के कस्बा गुरसहायगंज निवासी रविंद्र कुमार दुबे की जेब काटकर अज्ञात जेबकतरों ने 28000 रुपए पार कर दिए थे। दूसरी घटना में अपने घर से बाइक से हरपालपुर कस्बे में स्थित अपनी बर्तन की दुकान पर जा रहे धर्मपुर मढैया गांव निवासी सेवानिवृत्त सैनिक राजेंद्र सिंह से लिफ्ट लेने के बहाने दो जेबकतरों ने 42000 रूपये पार कर दिए थे। पुलिस ने दोनों मामलों की रिपोर्ट दर्ज कर सर्विलांस की मदद से छापेमारी कर सवायजपुर कस्बा निवासी नीरज पुत्र महेश व फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ताकीपुर गांव निवासी सनी पुत्र सूरजपाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में दोनों घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 34300रूपये की नगदी व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसआई धीरेंद्र कुमार वर्मा, कांस्टेबल अभिषेक त्यागी, ओम प्रकाश मौर्य,अंकित यादव,सुनील कुमार व महिला कांस्टेबल संध्या कुमारी शामिल रही।

शाहाबाद पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

शाहाबाद /हरदोई, चसं। कोतवाली पुलिस ने दो शातिर चोरों को नगदी और घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ गिरफ्तार कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई सात घटनाओं का खुलासा किया है।पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है। प्राप्त विवरण में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम, चोरी, लूट व नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सोमवार को प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश राय,अतिरिक्त निरीक्षक शिव गोपाल, उपनिरीक्षक अनिल कुमार और पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर संतोष कंजड़ पुत्र रामेश्वर और राहुल कंजड़ पुत्र महेन्द्र निवासीगण ग्राम ओमपुरी कोतवाली देहात को जनपद में घटित विभिन्न चोरियों से संबंधित तेतालिस हजार रुपए की नगदी और घटना में प्रयुक्त बाइक सहित गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार संतोष पर डेढ़ दर्जन मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में पंजीकृत है।दूसरे गिरफ्तार आरोपी सचिन पर सात मुकदमे दर्ज हैं।गिरफ्तार चोरों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि 2 मई को उनके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिल कर थाना शाहाबाद क्षेत्रांतर्गत अल्हापुर तिराहा के निकट एक व्यक्ति की जेब काटकर नगदी चोरी की गयी थी।25 जुलाई 24 को थाना शाहाबाद क्षेत्रांतर्गत बैंक आफ बडौदा के निकट से एक व्यक्ति की जेब से नगदी चोरी की गयी थी। दिनांक 31 जुलाई 24 को थाना पचदेवरा क्षेत्रांतर्गत अनंगपुर चौराहा के निकट ई-रिक्शा में बैठे व्यक्ति की जेब काटकर नगदी चोरी की गयी थी। दिनांक 25 जुलाई 24 को थाना पाली क्षेत्रांतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के निकट एक व्यक्ति की साइ?किल से बैग चोरी किया गया।14 फरवरी को अभियुक्तों द्वारा थाना पाली क्षेत्रांतर्गत रुपापुर चौराहे के निकट टैम्पो में सवार एक व्यक्ति की जेब काटकर नगदी चोरी की गयी थी।4 जनवरी को थाना शाहाबाद क्षेत्रांतर्गत अल्हापुर तिराहा व नवीन गल्ला मंडी के बीच मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की जेब काटकर नगदी चोरी की गयी थी।4 दिसंबर 24 को थाना सवायजपुर क्षेत्रांतर्गत रोडवेज बस में बैठे एक व्यक्ति के बैग से नगदी व आभूषण चोरी की गयी थी।पुलिस ने गिरफ्तार चोरों को जेल भेज दिया है।

हरपालपुर पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

हरदोई, चसं। हरपालपुर थाना पुलिस ने क्षेत्र में हुई घटनाओं में दो शातिर चोरों को नगदी और घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्राप्त विवरण में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम, चोरी, लूट व नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मंगलवार को थाना हरपालपुर के उपनिरीक्षक धीरेंद्र कुमार वर्मा और पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर नीरज पुत्र महेश निवासी कस्बा व थाना सवायजपुर और सनी पुत्र सूरजपाल निवासी ग्राम तकीपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद को चोरी किये गये चौतीस हजार तीन सौ रुपए की नगदी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि 21 अप्रैल को उनके द्वारा थाना हरपालपुर क्षेत्रांतर्गत मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति की जेब काटकर नगदी चोरी की गयी थी।3 मई को थाना हरपालपुर क्षेत्रांतर्गत ई-रिक्शा में बैठे एक व्यक्ति की जेब काटकर नगदी चोरी की गयी थी।पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को किया बरामद

हरदोई, चसं। कछौना थाना क्षेत्र दो माह पूर्व बहला फुसलाकर ले जाई गई किशोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया है।पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। प्राप्त विवरण में 24 फरवरी को किशोरी के पिता द्वारा थाना कछौना पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात आरोपी उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इस संबंध में थाना कछौना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी थी।पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया। थाना कछौना के उपनिरीक्षक अनिल कुमार और पुलिस बल द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त तुफैल उर्फ मोनू पुत्र रसीद निवासी ग्राम मुतक्कीपुर थाना मडियाव जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया गया।पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

वक्फ संशोधन अधिनियम के संबंध में जनजागरूकता गोष्ठी का ब्लॉक सभागार में आयोजन

कछौना/हरदोई, चसं। वक्फ संसोधन अधिनियम 2025 की जागरूकता के विषय पर वक्फ सुधार जनजागरण अधिनियम अल्पसंख्यक सवांद सभा का आयोजन विकासखण्ड कछौना के सभागार में मंगलवार को हुआ। जिसमे जनप्रतिनिधिगणों ने आमजनमानस मुस्लिम समाज में वक्फ संसोधन अधिनियम पर चर्चा की। सदस्य विधान परिषद अशोक अग्रवाल ने कहा इस कानून से मुस्लिम समाज के जीवन में परिवर्तन होगा। वक्फ संपति पर एक विशेष वर्ग शामिल था, यह भूमि मुस्लिम समाज के मदरसा, स्कूल, अस्तपताल बनाकर जीवन में बदलाव लाया जायेगा। डबल इंजन की सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर कार्य करती है। बिना भेदभाव के योजनाओ का लाभ जाति धर्म से ऊपर उठकर पात्र व्यक्तियों को देने का कार्य कर रही है। वक्फ सम्पतियो पर कुछ लोगो का काकस था। इस काकस को तोड़ने का कार्य सरकार कर रही है। हमारा देश तभी तरक्की करेगा, जब सभी की भागीदारी होगी। इस अवसर पर मुख्य अथिति वारिष्ठ भाजपा नेता राजीव मिश्रा ने कहा वक्फ बोर्ड के नाम पर देश की रास्ट्रीय संपति पर कुछ लोग लाभ उठा रहे थे। हमारे देश के ?रीब मुसलमान वंचित थे। सरकार ने इस कानून में संसोधन कर मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करने के लिए एक कदम उठाया है। विपक्षी पार्टिया केवल गुमराह कर रही है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष कर्मवीर सिंह ने संसोधित करते हुए कहा मोदी जी 140 करोड़ आमजन मानस के विश्वास के प्रतीक है। वह विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे है। इसके लिये सबका साथ सबका विकास सबका विशवास पर कार्य कर रहे है। विपक्षी पार्टिया मोदी सरकार के प्रति मुसलमानों में डर पैदा कर राजनैतिक रोटी सेक रही है। उन्हें गुमराह कर रही है। इस वक्फ बिल को पढ़ें व चर्चा करे, तभी इसका पता चलेगा। इस कानून से मुस्लिम समाज के जीवन में परिवर्तन आयेगा। देश तरक्की की नई इबारत लिखेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षयता ग्राम प्रधान डॉ0 मुख्तार ने की। कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्रधान देवी शंकर शुक्ला ने किया।

संक्षिप्त समाचार

एएमयू में एनआरएससी ने इंटर-हॉल क्रिकेट ट्रॉफी जीती

अलीगढ़, चसं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में आयोजित इंटर-हॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब एनआरएससी टीम ने अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में एनआरएससी ने राजा महराज प्रताप सिंह एएमयू सिटी स्कूल हॉल को एकतरफा मुकाबले में हराकर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। यह मुकाबला विश्वविद्यालय के विलिंगडन पवेलियन में खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एनआरएससी ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 173 रन बनाए। मोहम्मद सिब्तैन ने शानदार अंदाज में 52 रन बनाकर शीर्ष स्कोर किया, जबकि अभय ने 42 रन की अहम पारी खेली। राजा महराज प्रताप सिंह स्कूल की ओर से कृष्णा सारस्वत सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए। कप्तान आरिफने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्कूल टीम दबाव में आकर 89 रनों पर सिमट गई। एनआरएससी की ओर से मोहम्मद ओसैद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके और प्लेयर ऑफद मैच का पुरस्कार जीता।चिराग शर्मा को टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज घोषित किया गया, जबकि मोहम्मद सिब्तैन और हनीफचौधरी को उनकी निरंतर प्रदर्शन के लिए संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफद सीरीज चुना गया। पुरस्कार वितरण समारोह में एएमयू के प्रो-वाइस चांसलर प्रो. मोहम्मद मोहसिन (मुख्य अतिथि), खेल समिति के सचिव प्रो. सैयद अमजद अली रिजवी और ईसी सदस्य डॉ. मोहम्मद मोइनुद्दीन शामिल हुए। पूर्व रणजी क्रिकेटर ओबैद कमाल और एएसए सचिव अब्दुल वहाब ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और विजेताओं को सम्मानित किया। टूर्नामेंट का आयोजन कोच डॉ. फैसल एम.आर. शेरवानी की देखरेख में किया गया।

प्रयागराज, एटा, बांदा, सीतापुर, झांसी, अयोध्या में मूर्तियों की स्थापना के लिए करोड़ 23 लाख 42 हजार स्वीकृत

लखनऊ, चसं। संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में पूर्व मुख्यमंत्री स्व कल्याण सिंह, स्व कमला बहुगुणा, महापुरूषों एवं भक्त प्रहलाद, नरसिंह भगवान, भगवान सूर्य नारायण, भगवान गणेश व महर्षि बाल्मीकि की मूर्तियां की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 01 करोड़ 23 लाख 42 हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इन मूर्तियों के निर्माण हेतु श्रद्धा शुक्ला निदेशक राज्य ललितकला अकादमी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रयागराज में स्व कमला बहुगुणा की 05 फिट की कांस्य की प्रतिमा स्थापित करने के लिए 06 लाख 60 हजार रूपये, एटा में पूर्व मुख्यमंत्री बाबू कल्याण सिंह की 12.5 फिट खड़ी मूर्ति के लिए 19 लाख 75 हजार, जनपद बांदा में अवंतीबाई होलकर की 12.5 फिट अश्वारोही कांस्य मूर्ति के लिए 27 लाख 05 हजार रूपये, सीतापुर में अवैद्यनाथ 12.5 फिट खड़ी ब्रांज मूर्ति के लिए 14812580 रूपये तथा झांसी में भक्त प्रहलाद की मूर्ति के लिए 04 लाख 95 हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है। झांसी में नरसिंह भगवान की मूर्ति के लिए 2118750 रूपये, अयोध्या में भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति हेतु 02 लाख 56 हजार रूपये, अयोध्या में ही भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने के लिए 12 लाख 50 हजार रूपये तथा अयोध्या में महर्षि बाल्मीकि की मूर्ति हेतु 1401000 रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

मारुति जॉब फेयर, अभ्यर्थी बोले, अच्छा पैकेज मिला, धूप से परेशान दिखे स्टूडेंट्स

लखनऊ, चसं। लखनऊ के आईटीआई अलीगंज में मंगलवार को मारुति कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव का दूसरा दिन है। सोमवार को हुई रिटेन परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों का मंगलवार सुबह से ही इंटरव्यू लिया जा रहा है। कुल 13 ट्रेड के आईटीआई पास अभ्यर्थियों की भर्ती होनी है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 32 हजार का मंथली पैकेज ऑफर किया जा रहा। कुल 500 पदों पर भर्ती के लिए इस रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अरविंद ने बताया बरेली से मारुति के कैंपस ड्राइव में शामिल होने के लिए आए हैं। सोमवार को रिटेन टेस्ट दिया, उसमें नाम आया फिर आज इंटरव्यू हुआ। बहुत ज्यादा देर इंटरव्यू नहीं चला। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सवाल थे और कुछ सवाल इस बात पर थे कि इससे पहले की नौकरी में किस वर्क प्रोफाइल पर काम किया। अरविंद ने कहा मारुति में इसलिए नौकरी करना चाहते हैं क्योंकि ये कंपनी पैकेज अच्छा दे रही है। 32 हजार का मंथली पैकेज है। इसके अलावा और भी कई फैसिलिटी देती है। ऐसे में यहां नौकरी करना चाहता हूं। आईटीआई अलीगंज के प्लेसमेंट ऑफिसर ड। खान ने बताया कि 2 दिन तक चलने वाले इस जॉब फेयर में सोमवार को लिखित परीक्षा हुई। इसमें करीब 750 अभ्यर्थी शामिल हुए। 400 के करीब अभ्यर्थियों ने रिटेन में क्वालीफाई किया, आज इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू चल रहा। पहले दिन रिटेन परीक्षा एग्जाम को लेकर तीन बैच बनाए गए हैं। हर बैच में करीब 200 से 250 के बीच अभ्यर्थी रहे। मंगलवार शाम तक फाइनल लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। आईटीआई अलीगंज के प्रिंसिपल डॉ.राजकुमार यादव ने बताया कि मारुति हरियाणा के मानेसर प्लांट के लिए हायरिंग कर रही है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 32 हजार से ज्यादा का सैलरी पैकेज ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई फैसिलिटीज मिलेंगी।

यूपी के मिर्जापुर जिले में अडाणी समूह लगाएगा पहला थर्मल पावर प्लांट, 1600 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन

लखनऊ, चसं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अडाणी समूह को 1600 मेगावाट की नई तापीय परियोजना लगाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसी के साथ अडाणी पावर लिमिटेड का यूपी में लगने जा रहा यह पहला थर्मल पावर प्लांट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रतिस्पर्धात्मक न्यूनतम बिडिंग के आधार पर अडाणी समूह को मिर्जापुर में 1600 मेगावाट का तापीय संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। नयी परियोजना 2030-31 तक अमल में आने के आसार है। सरकार ने 1600 मेगावाट क्षमता की इस तापीय परियोजना से कुल 1500 मेगावॉट ऊर्जा बिड प्रॉसेस के माध्यम से 25 वर्षों तक खरीदने का निर्णय लिया है। बिडिंग प्रक्रिया में सबसे कम टैरिफ दर (5.38 रुपए प्रति यूनिट) की पेशकश की गयी है। इससे यूपी पावर कॉर्पोरेशन (यूपीपीसीएल) को 25 वर्षों में लगभग 2958 करोड़ रुपए की बचत होगी। बता दें कि मिर्जापुर के दादरी खुर्द गांव में लगने जा रहे अडानी ग्रुप का यह प्लांट 1(डी) थर्मन पावर प्लांट और कैटगरी ए का है। कंपनी कुल 36519 हेक्टेयर भूमि का उपयोग इस प्लांट के लिए करेगी। इस प्लांट के लिए अडानी ग्रुप को 18300 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इस प्लांट तक कोयला लाने के लिए रेलवे लाइन का भी निर्माण किया जाएगा।

भारत के सेवा क्षेत्र में नए ऑर्डर प्रवाह से मामूली सुधार

नयी दिल्ली , एजेंसी। भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधि में अप्रैल में मामूली सुधार दर्ज किया गया। यह मुख्य रूप से नए ऑर्डर प्रवाह में तेजी से प्रेरित रहा। मंगलवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण में यह बात कही गई। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया सेवा कारोबारी गतिविधि सूचकांक अप्रैल में 58.7 रहा जो मार्च में 58.5 पर था। यह आंकड़ा इसके दीर्घकालिक औसत 54.2 से अधिक है। क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) की भाषा में 50 से ऊपर अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार से और 50 से कम का आशय संकुचन से होता है। एचएसबीसी के भारत के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, ''भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां पिछले महीने की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी हैं। मार्च में राहत मिलने के बाद नए निर्यात ऑर्डर में तेजी आई है, जो जुलाई 2024 के बाद सबसे तेज गति से बढ़ रहे हैं।श्श् उत्पादन में समग्र विस्तार नए व्यवसाय में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित रहा जो आठ महीनों में संयुक्त रूप से सबसे अच्छा था। कई कंपनियों ने अनुकूल मांग की स्थिति और सफल विपणन प्रयासों का उल्लेख किया। इसके अलावा, भारतीय कंपनियों को अपनी सेवाओं के लिए बेहतर अंतरराष्ट्रीय मांग से लाभ मिलना जारी रहा, जिसमें एशिया, यूरोप, पश्चिम एशिया और अमेरिका को विशेष रूप से ताकत के स्रोत के रूप में उद्धृत किया गया। कुल मिलाकर, नए निर्यात ऑर्डर जुलाई 2024 के बाद से सबसे तेज गति से बढ़े। नए ऑर्डर के प्रवाह में तीव्र वृद्धि के कारण भारतीय सेवा कंपनियों ने अप्रैल में लगातार 35 वें महीने अपने कार्यबल की संख्या में वृद्धि की। सर्वेक्षण में कहा गया कि कंपनियों ने ग्राहकों की बढ़ती मांग का लाभ उठाने के लिए पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारियों के साथ परिचालन क्षमता में वृद्धि की। मूल्य निर्धारण के मोर्चे पर, भारतीय सेवा कंपनियों ने अप्रैल के दौरान अपने औसत विक्रय मूल्यों में वृद्धि की क्योंकि वे ग्राहकों पर उच्च लागत का बोझ डालना चाहते थे।

रोमांचक मुकाबले में गुजरात ने मुम्बई को हराया

चर्चित राजनीति। एजेंसी

मुम्बई। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 56वें मुकाबले में मंगलवार को मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से हुआ। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में गुजरात ने मुंबई को 3 विकेट से हराया। शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 155 रन बनाए। विल जैक्स ने सबसे ज्यादा 53 रन की पारी खेली। उनके अलावा सूर्यकुमार यादव ने 35 रन बनाए। दीपक चाहर 8 और कर्ण शर्मा बिना कोई रन बनाए नाबाद रहे। गुजरात की ओर से साई किशोर को 2 विकेट मिले। बारिश के कारण मैच 19 ओवर का हुआ। 18वें ओवर तक गुजरात ने 132 रन बना लिए थे। ऐसे में 19वें ओवर में उन्हें 15 रन चाहिए थे। ओवर की 5वीं गेंद पर गेराल्ड कोएत्ज़ी कैच आउट हुए। अब टीम को आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था। अरशद खानने सिंगल लेकर अपनी टीम को जीत दिला दी। गुजरात की ओर से शुभमन गिल ने 43 रन की पारी खेली।

वहीं जोस बटलर ने 30 और शेफरोन रदरफोर्ड ने 28 रन बनाए। गुजरात टाइटंस ने सांस थाम देने वाले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को आखिरी गेंद पर 3 विकेट से मात दी। वानखेड़े स्टेडियम पर वर्षाबाधित मुकाबले में गुजरात ने मुंबई को मात देकर प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल किया। टूर्नामेंट के 56वें मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करके 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 155 रन बनाए। गुजरात को बारिश के कारण रुके मुकाबले में 19 ओवर में 147 रन का संशोधित लक्ष्य

मिला। जीटी ने आखिरी गेंद पर सात विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। गुजरात टाइटंस ने मौजूदा सीजन में मुंबई इंडियंस को लगातार दूसरी बार पटखनी दी। दोनों टीमों के बीच पिछली भिड़ंत 29 मार्च को हुई थी, जहां गुजरात ने 36 रन से बाजी जीती थी। गुजरात टाइटंस इस जीत के साथ प्लेऑफ के बेहद करीब पहुंच गई है। 156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शानदार फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन (5) को ट्रेंट बोल्ट ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर रिकलटन के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर (30) ने दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी की। यह जोड़ी आक्रामक अंदाज अपनाती कि पहले ही अश्विनी कुमार ने बटलर को रिकलटन के हाथों कैच आउट कराया। फिर रदरफोर्ड ने आते ही चौके-छक्के जमाए।

बारिश ने मुकाबला बनाया रोमांचक : शुभमन गिल और शेरफेन रदरफोर्ड ने 14वें ओवर तक गुजरात को 100 रन के पार पहुंचा दिया था। तब अंपायर ने दूसरा स्ट्रैटेजिक टाइम आउट लिया और बारिश के कारण कुछ देर के लिए खेल रुका। जब दोबारा खेल शुरू हुआ तो बुमराह ने मुंबई की वापसी कराई। बुमराह ने 15वें ओवर की पांचवीं गेंद पर शुभमन गिल (43) को क्लीन बोल्ड कर दिया। अगले ओवर में बोल्ट ने शेरफेन रदरफोर्ड (28) को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। फिर बुमराह ने शाहरुख खान (6) को बोल्ड करके मुकाबले में जान भर दी। इसके बाद अश्विनी कुमार ने राशिद खान (2) को एलबीडब्ल्यू आउट करके गुजरात को बैकफुट पर धकेल दिया।

गुजरात ने 18 ओवर में 6 विकेट खोकर 132 रन बना लिए थे। उसे दो ओवर में 24 रन की दरकार थी। तभी बारिश के कारण फिर मैच रुक गया। अंपायर्स ने कुछ देर बाद मैदान का निरीक्षण किया और मैच शुरू करने का फैसला लिया। गुजरात को 19 ओवर में 147 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। यानी गुजरात को आखिरी ओवर में 15 रन की दरकार थी। दीपक चाहर ने आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभाली। आखिरी गेंद पर गुजरात ने जीत दर्ज की। इससे पहले शुरुआती ओवरों में कैच टपकाने और विल जैक्स की शानदार अर्धतकीय पारी के बाद गुजरात टाइटंस के स्पिनरों राशिद खान और आर साई किशोर ने शानदार वापसी करते हुए मुंबई इंडियंस को उसके घर वानखेड़े स्टेडियम में आठ विकेट पर 155 रन पर रोक दिया। दोनों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए मुंबई के मध्यक्रम को दवाब में ला दिया। गुजरात की टीम ने पावरप्ले में तीन आसान कैच छोड़े, जिसका लाभ उठाते हुए मुंबई को विल जैक्स (53) और सूर्याकुमार यादव (35) ने शुरुआती झटकों के बावजूद अच्छी शुरुआत दी। लेकिन बीच के ओवरों ने राशिद और साई किशोर ने बाजी को पलट दिया। राशिद ने जहां खतरनाक दिख रहे विल जैक्स को आउट किया तो किशोर ने सूर्या कुमार व कप्तान हार्दिक पांड्या के अहम विकेट चटकाए। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अहम इस मुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने रिकलटन को आउट कर मुंबई को पहला झटका दिया। इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर विल जैक्स को जीवनदान मिला, जब साई सुदर्शन ने उनका कैच टपका दिया।

जैक्स ने उठाया फायदा : पहले ही ओवर में मिले जीवनदान का लाभ उठाते हुए जैक्स ने दूसरे छोर से मुंबई के गेंदबाजों के विरुद्ध शाट लगाने जारी रखे। उन्होंने सिराज के ओवर में लगातार दो गेंद पर एक छक्का व चौका जड़ा। वहीं सूर्या ने पर्पल कैप धारक प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर में तीन चौके जड़ते हुए रनों की गति बढ़ाई। पावरप्ले समाप्त होने तक दोनों ने 56 रन बना लिए थे।

हालांकि इस दौरान जैक्स और सूर्या को एक-एक बार जीवनदान मिला। इसका लाभ उठाते हुए विल जैक्स ने केवल 35 गेंदों की पारी में पांच चौके व तीन छक्के लगाए। उन्होंने सूर्या के साथ तीसरे विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी की। लेकिन जैसे ही ये दोनों बल्लेबाज आउट हुए, गुजरात ने खेल पर पूरी पकड़ बना ली। राशिद ने इससे पहले दो बार डीआरएस भी लिया, लेकिन दोनों बार निर्णय उनके पक्ष में नहीं गया। एक बार गेंद का इंपैक्ट आफ स्टंप से बाहर रहा तो दूसरी बार गेंद स्टंप को मिस करती हुई पाई गई।

अंत में बॉश की आतिशबाजी : 123 रन के स्कोर पर सात विकेट गंवा चुकी मुंबई के लिए कार्बिन बॉश (27) ने अंत में कुछ शानदार शाट खेले और 22 गेंदों में दो छक्के व एक चौका लगाते हुए टीम को 150 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। बॉश, सूर्या और जैक्स के अलावा मुंबई को कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका।

मुम्बई ने गुजरात के खिलाफ उतारे 13 प्लेयर्स : आमतौर पर क्रिकेट में टीम 11-11 प्लेयर के साथ मैदान पर उतरती हैं। हालांकि, दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है। इसमें टीम 11 की

■ **प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची**

जगह 12 प्लेयर के साथ खेल सकती हैं। हालांकि, मैदान पर अधिकतम 11 खिलाड़ी ही रह सकते हैं। 1 प्लेयर को बाहर बैठाकर उनके जगह दूसरे प्लेयर को बतौर इम्पैक्ट प्लेयर मौका दिया जा सकता है। हालांकि, गुजरात टाइटंस के खिलाफ मंगलवार को मुबई इंडियंस ने 13

> **शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 155 रन बनाए। विल जैक्स ने सबसे ज्यादा 53 रन की पारी खेली। उनके अलावा सूर्यकुमार यादव ने 35 रन बनाए। दीपक चाहर 8 और कर्ण शर्मा बिना कोई रन बनाए नाबाद रहे।**

प्लेयर्स का इस्तेमाल किया। 18वें सीजन के इस 56वें मैच में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीततकर गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 155 रन बनाए। 20वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा ने किया। ओवर तीसरी गेंद कॉर्बिन बॉश के हेलमेट पर जाकर लगी। कृष्णा की शॉट गेंद पर बॉश ने पुल शॉट लगाने का प्रयास किया और वह पूरी तरह चूक गए। चूंकि गेंद हेलमेट पर लगी थी ऐसे में कन्कशन जांच के लिए फिजियो आए। जब मुंबई गेंदबाजी करने के लिए उतरी तो तीसरे अंपायर की इजाजत से कार्बिन बॉश के कन्कशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर अश्वनी कुमार को मौका दिया गया। कन्कशन सब्स्टीट्यूट नियम की बात करें तो जब खिलाड़ी के सिर या गर्दन की चोट लगती है तो उसके जैसे ही किसी दूसरे प्लेयर को मौका दिया जा सकता है। क्रिकेट की भाषा में इसे लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कहा जाता है। अगर बल्लेबाज चोटिल होता है तो बैटर और अगर गेंदबाज चोटिल होता है तो गेंदबाज को ही मौका मिलता है।

इम्पैक्ट प्लेयर रूल में सभी टीम मैच से पहले अपनी प्लेइंग इलेवन के अलावा पांच सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों का नाम देती हैं। दोनों कप्तान मैच के किसी नेचुरल ब्रेक के दौरान प्लेइंग इलेवन में किसी एक खिलाड़ी की जगह लेने के लिए इन पांच सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों में से किसी एक को टीम में शामिल कर सकता है। हालांकि, सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों जिसकी जगह लेगा उसे मैदान से बाहर जाना होगा। मैदान से बाहर जाने के बाद यह प्लेयर वापस नहीं आ सकता है। अगर किसी टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में चार विदेशी खिलाड़ियों को चुना है, तो वह एक भारतीय प्लेयर को ही इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में टीम में शामिल कर सकती हैं। अगर टीम ने अंतिम 11 में तीन या उससे कम विदेशी खिलाड़ियों को चुना है, तो वह इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में विदेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल कर सकती है। आईपीएल में प्लेइंग 11 में ज्यादा से ज्यादा 4 विदेशी प्लेयर ही खेल सकते हैं।

पावरप्ले में गुजरात ने टपका दिए 3 कैच, शुभमन गिल गुस्से से हुए लाल-पीले : इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 56वें मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। गुजरात को शुरुआत तो अच्छी मिली, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में जीटी ने फील्डिंग से निराश किया। पावरप्ले समाप्त होने तक मुंबई ने 2 विकेट खोकर 56 रन बनाए। हालांकि, पहले 6 ओवर में गुजरात के फील्डर्स ने 3 कैच टपका दिए। गुजरात की ओर से पहला ओवर मोहम्मद सिराज ने किया। ओवर की दूसरी गेंद पर ही उन्होंने रयान रिकेल्टन का विकेट चटकाया। ऐसे में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने विल जैक्स आए। जैक्स का खाता तक नहीं खुला था और चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार ड्राइव लगाई। गेंद हवा में थी और कवर पर खड़े साई सुदर्शन ने इस आसान से कैच को ड्रॉप कर दिया। सिराज पहले ही ओवर में 2 विकेट चटका सकते थे हालांकि, ऐसा नहीं हो पाया। अब देखना होगा यह कैच कितना भारी पड़ता है। गुजरात टाइटंस की ओर से 5वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा ने किया। ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्यकुमार यादव को जीवनदान मिला। इस बार साई किशोर ने मिड विकेट पर उनका कैच ड्रॉप कर दिया। सूर्यकुमार यादव ने गेंद को थोड़ा ऊपर की ओर फ्लिक किया। उन्होंने गेंद को रिवर्स कप करने की कोशिश की। साइडलाइन के पास खड़े आशीष नेहरा निराश नजर आए।

धोखेबाज और घोटालेबाजों की टीम के कप्तान! आखिर ऐसा किसने और क्यों कहा : आईपीएल 2025 का रोमांच फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए सात टीमों के बीच जोरदार जंग चल रही है। चेन्नई सुपरकिंग्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की जगह लगभग पक्की हो चुकी है। पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइटराइडर्स और लखनऊ सुपरजायंट्स के बीच चौथे स्थान के लिए जंग जारी है। आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में कौन-सी टीमें जगह बना पाएंगी, फैंस का ध्यान इस पर है, लेकिन इस बीच आइसलैंड क्रिकेट ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट से सभी का ध्यान खींचा है। आइसलैंड क्रिकेट अपने चुटीले सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जाना जाता है और एक बार फिर वो अपने इरादे में कामयाब हुआ। आइसलैंड क्रिकेट ने आईपीएल 2025 में फ्लॉप चल रहे खिलाड़ियों की टीम बनाई है, जिसका कप्तान ऋषभ पंत को बनाया है।

आइसलैंड क्रिकेट ने तंजभरे पोस्ट में लिखा, रेजाविक में बारिश के दिन, हम आपको अपनी आईपीएल 2025 के धोखेबाजों और घोटालेबाजों टीम देते हैं।

इंटर स्कूल गर्ल्स एवं बॉयज बास्केटबाल चैम्पियनशिप का भव्य शुभारम्भ, सरोजनीनगर में जारी है खेलों का महाकुम्भ

चर्चित राजनीति। संवाददाता

लखनऊ। विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह द्वारा शुरू की गयी सरोजनीनगर स्पोर्ट्स लीग खेलों प्रतिभाओं को संसाधन, अवसर और प्लेटफॉर्म प्रदान करने का अभूतपूर्व माध्यम बन गयी है। मंगलवार को वृन्दावन योजना स्थित एसकेडी अकैडमी ग्राउंड में लीग के सातवें चरण के अंतर्गत इंटर स्कूल गर्ल्स, बॉयज बास्केटबाल चैम्पियनशिप का शुभारम्भ किया गया।

इस प्रतियोगिता के अंतर्गत 49 टीमें (26 बॉयज और 23 गर्ल्स) हिस्सा ले रही हैं। लीग का पहला मुकाबला सेठ एआर जयपुरिया स्कूल अंसल और दि मिलेनियम स्कूल की टीमों के बीच खेला गया। गर्ल्स एवं बॉयज दोनों टूर्नामेंट में सेठ एआर जयपुरिया स्कूल की टीमों ने जीत दर्ज की। लीग के शुभारम्भ समारोह में बोलते हुए सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि बास्केटबाल एक अद्भुत खेल है। दुनिया के 45 करोड़ लोग बास्केटबाल खेलते हैं, बास्केटबाल से हमें जो सीख मिलती है वो किसी और खेल से नहीं मिलती है।

जब आप बॉल दूसरे खिलाड़ी को पास करते हैं तो आपको विश्वास के बारे में सीखने को मिलता है, यह खेल स्वयं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। विधायक ने बताया सरोजनी नगर के युवाओं के लिए सरोजनीनगर स्पोर्ट्स लीग अनवरत जारी रहेगी। गौरतलब है कि लीग की शुरुआत 4 दिसंबर 2022 को अंडर -19 गर्ल्स बास्केटबाल टूर्नामेंट के आयोजन के साथ की गयी, जिसमें विभिन्न विद्यालयों की करीब 200 छात्राओं ने हिस्सा लिया। दूसरे चरण में इंटर

■ **सरोजनीनगर स्पोर्ट्स लीग बास्केटबाल चैम्पियनशिप का भव्य शुभारम्भ, सेठ एआर जयपुरिया की टीम ने जीत से किया आगाज**

■ **शिक्षा के साथ खेल को मिला रहा मंच सरोजनीनगर में शुरू हुआ बास्केटबाल चैम्पियनशिप**

क्लब और इंटर स्कूल क्रिकेट चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया जिसमें करीब 3,500 खिलाडियों ने हिस्सा लिया, तीसरे चरण में फुटबॉल टूर्नामेंट, चौथे चरण में वॉलीबॉल चैंपियनशिप, पांचवे चरण में इंटर मंडल क्रिकेट चैम्पियनशिप और छठे चरण में पुनः इंटर क्लब और इंटर स्कूल क्रिकेट चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया जिसमें 166 टीमों के 2400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। शुभारम्भ समारोह के दौरान एसकेडी अकैडमी के निदेशक मनीष सिंह, पूर्व आईआरएस अधिकारी रामेश्वर सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद मौर्या, अमर पाल राठौर, शंकरी सिंह, रमा शंकर त्रिपाठी, पार्षद के.एन. सिंह, शैलेन्द्र सिंह, सुमन सिंह राठौर, राजीव सिंह बंगाली, शिव प्रकाश मिश्रा, बूथ अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सक्सेना एवं धर्मेन्द्र कुमार, राम सिंह, माधवी देवी, राधिका परिहार, अंजू पाण्डेय, अर्चना बोहरा, नीतू सिंह, ओम प्रकाश यादव, रोहित रस्तोगी, यदुशल्य यादव सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे।

हिंदुस्तान जिंक का जिंक बैटरी तकनीक में अनुसंधान : भविष्य के ऊर्जा भंडारण में बनेगा गेम-चेंजर

चर्चित राजनीति। एजेंसी

उदयपुर। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल), अगली पीढ़ी की जिंक-आधारित बैटरी तकनीकों के अनुसंधान में सक्रिय रूप से निवेश कर रही है, जो कंपनी को ऊर्जा भंडारण समाधानों के तेजी से बढ़ते बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की क्षमता रखती है। कंपनी का यह रणनीतिक कदम न केवल तकनीकी नवाचार पर केंद्रित है, बल्कि लिथियम की आपूर्ति संबंधी चुनौतियों और बढ़ती लागत के मुकाबले एक अधिक टिकाऊ और लागत-प्रभावी विकल्प तलाशने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। एचजेडएल ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों- आईआईटी मद्रास और जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (जेएनसीएएसआर), बेंगलुरु के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान साझेदारी स्थापित की है। जेएनसीएएसआर के साथ मिलकर, एचजेडएल जिंक-आयन बैटरी के विकास को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें उन्नत इलेक्ट्रोलाइट्स और नए जिंक एनोड फॉर्मूलेशन पर काम शामिल है। प्रारंभिक निष्कर्ष इलेक्ट्रोड/इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस इंजीनियरिंग में उत्साहजनक प्रगति दर्शाते हैं।

सेंसेक्स 157 अंक गिरकर 80,641 पर बंद, निफ्टी 24,379 के स्तर पर

मुंबई, एजेंसी। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन आज यानी मंगलवार (6 मई) को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 157 अंक गिरकर 80,641 के स्तर पर और निफ्टी में भी 81 अंक की गिरावट रही, ये 24,379 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में गिरावट रही। अडानी पोर्ट्स, जोमैटो, सनफार्मा, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस 2 प्रतिशत तक की गिरावट रही। वहीं, महिंद्रा, एयरटेल और नेस्ले के शेयर में 3 प्रतिशत तक की तेजी रही। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार, 5 मई को शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 295 अंक ऊपर 80,797 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 114 अंक की तेजी रही, ये 24,461 के स्तर पर बंद हुआ।

सुंदरम होम फाइनेंस का जनवरी-मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ 26 फीसदी बढ़कर 71.57 करोड़ रुपए

चेन्नई, एजेंसी। सुंदरम होम फाइनेंस का जनवरी-मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ 26 प्रतिशत बढ़कर 71.57 करोड़ रुपये रहा। सुंदरम होम फाइनेंस की ओर से मंगलवार को जारी बयान के अनुसार, कंपनी का पिछले वर्ष की इसी तिमाही में शुद्ध लाभ 56.80 करोड़ रुपए रहा था। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी का समूचे वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध लाभ चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 244.66 करोड़ रुपए रहा।वित्तीय प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कंपनी के प्रबंध निदेशक डी. लक्ष्मीनारायणन ने कहा, ''छोटे शहरों में गहरी पैठ बनाने की हमारी विकास रणनीति के अनुरूप, हमने पिछले वर्ष विस्तार के लिए मझोले तथा छोटे शहरों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा, ''अपने परिचालन के 25वें वर्ष में, हम छोटे शहरों में अपनी पहुंच और देश भर में अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार करने से करीब 30 प्रतिशत की मजबूत संवितरण वृद्धि दर्ज करने में सक्षम हुए हैं। इस बीच, सुंदरम होम फाइनेंस ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अपनी वृद्धि में तेजी लाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाने की योजना की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि जुटाई जाने वाली प्रस्तावित धनराशि एनएचबी से पुनर्वित्त, बैंक ऋण, 'डिबेंचर और सावधि जमा के मिश्रण के माध्यम से होगी।

डिशटीवी वॉचो का नया धमाका : फ्लिक्स देगा हर कहानी को अपनी पहचान

नई दिल्ली, एजेंसी। कंटेंट वितरण के क्षेत्र में अग्रणी डिशटीवी इंडिया लिमिटेड ने डिजिटल मनोरंजन के मैदान में एक बड़ा कदम उठाया है। डायरेक्ट-टू-होम सेवा में अपनी मजबूत पकड़ के बाद, कंपनी ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म वॉचो पर फ्लिक्स नामक एक नया और महत्वाकांक्षी सेगमेंट लॉन्च किया है। यह पहल न केवल ओटीटी बाजार में विविधता लाएगी, बल्कि कंटेंट निर्माताओं और दर्शकों के बीच एक सीधा और सशक्त मंच भी स्थापित करेगी। फ्लिक्स की नींव अप्रैल 2025 में आयोजित कंटेंट इंडिया समिट 2025 में रखी गई थी और वेव्स 2025 में इसका आधिकारिक अनावरण किया गया। इस लॉन्च के साथ, डिशटीवी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह अब केवल कंटेंट एग्रीगेटर बनकर नहीं रहेगी, बल्कि एक संपूर्ण डिजिटल मनोरंजन केंद्र के रूप में विकसित होगी। फ्लिक्स की सबसे खास बात यह है कि यह कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के साथ-साथ अपने कंटेंट पर पूर्ण नियंत्रण और उससे कमाई करने का अवसर भी देगा। यह हर पेशेवर क्रिएटर को अपना खुद का ओटीटी ऐप होने जैसा अनुभव प्रदान करेगा।

भारतीय सिनेमा में पुरुषों का दबदबा बहुत ज्यादा : सामंथा

भारतीय सिनेमा की कई अभिनेत्रियां ऐसी हैं, जो एक्टिंग के अलावा फिल्म निर्माता के तौर पर भी काम कर रही हैं। इस लिस्ट में सामंथा रुथ प्रभु का नाम भी शामिल है। वह अपने प्रोडक्शन हाउस त्रालाला मूविंग पिक्चर्स के बैनर तले बन रही फिल्म शुभम को लेकर काफी चर्चा में हैं। समाचार एजेंसी से बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि भारतीय सिनेमा में महिलाओं की आवाज और कहानियों को मंच देने की जरूरत है। जब सामंथा से पूछा गया कि क्या वे एक प्रोड्यूसर के रूप में ऐसी कहानियां बनाना चाहती हैं जो महिलाओं के दृष्टिकोण को गहराई से समझें, तो उन्होंने जवाब दिया, एक महिला होने के नाते मेरी पहचान मेरे काम के हर पहलू में दिखेगी, खासकर फिल्मों को चुनते या बनाते समय। यह मेरे लिए गर्व की बात है। मैं ऐसी कहानियों की ओर आकर्षित होती हूं जो महिलाओं को सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि एक गहराई से भरा इंसान दिखाएं। सामंथा ने कहा, मुझे लगता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को महिलाओं के नजरिए की ज्यादा जरूरत है।

फिल्मों में महिलाओं की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण को ज्यादा जगह मिलनी चाहिए। अभी भी इंडस्ट्री में पुरुषों का दबदबा बहुत ज्यादा है। मैं यह बात नकारात्मक रूप में नहीं कह रही हूं, बल्कि बस एक सच्चाई को सामने रख रही हूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ज्यादा महिला फिल्म निर्माताओं और कहानीकारों को आगे आने की जरूरत है। एक्ट्रेस ने कहा, यह याद रखना जरूरी है कि महिलाएं दुनिया की आधी आबादी हैं, इसलिए हमें और महिला प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और रचनात्मक लोग चाहिए, जो अपनी आवाज और अनुभव सामने ला सकें। सामंथा ने कहा कि वह ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहती हैं जो आधुनिक महिलाओं से जुड़ी हों, जो आज की महिलाओं के संघर्ष, स्वतंत्रता और जज्बातों को सच्चाई और गहराई से दिखाएं। सामंथा की फिल्म शुभम एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, जो एक छोटे से गांव की कहानी दिखाती है।

मेकर्स फिल्म का ट्रेलर जारी कर चुके हैं। ट्रेलर की शुरुआत तीन पतियों से होती है, जो पत्नियों को काबू करने की बात करते हैं। इसके बाद नए नवेले शादीशुदा जोड़े का सीन दिखाया जाता है, जहां दूल्हा पहले तो शांत और सौम्य लगता है, लेकिन अचानक दुल्हन पर अकड़ दिखाने लगता है। दुल्हन चुपचाप उसकी बातें सुनती है। कहानी में ट्विस्ट आता है, जब दुल्हन एक टीवी सीरियल में पूरी तरह से डूब जाती है। इस सीरियल के पीछे पूरे गांव की औरतों में अजीब सी ताकत आती है। रात के 9 बजते ही अगर कोई उन्हें सीरियल देखने से मना करता या सीरियल के बारे में कुछ गलत कहता, तो उन्हें उनका डरावना अंदाज देखने को मिलता। इससे गांव के सभी पुरुषों में डर का माहौल है। शुभम में हर्षित रेड्डी, गविरेड्डी श्रीनिवास, चारण पेरी, श्रिया कोंथम, श्रवणी लक्ष्मी, शालिनी कोंडेपुडी, वाम्शीधर गौड़ समेत कई कलाकार अहम किरदार में हैं। बता दें कि अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने फिल्म शुभम से फिल्म निर्माण में भी कदम रख चुकी हैं। सामंथा की यह फिल्म 9 मई को रिलीज होगी। अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु से जब पूछा गया कि अभिनय की तुलना में फिल्म निर्माण का अनुभव कैसे अलग रहा, इस पर उन्होंने कहा कि जब आप एक निर्माता होते हैं, तो फिल्म निर्माण के हर पहलू के बारे में सीखने का मौका मिलता है। अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु ने बताया कि एक अभिनेत्री के रूप में मैंने जितना कुछ सीखा था, इस फिल्म का निर्माण करते हुए मैंने उससे ज्यादा सीखा। जब आप एक निर्माता होते हैं तो फिल्म निर्माण के हर पहलू के बारे में करीब से सीखने का मौका मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनना मेरे लिए काफी संतोषजनक रहा। क्या उन्हें यह कदम जोखिम भरा नहीं लगा? इस पर अभिनेत्री सामंथा ने जवाब दिया कि 'इंडस्ट्री में 15 साल बिताने के बाद, जुनून और उद्देश्य ने डर को पीछे छोड दिया है। इस उद्योग में जोखिम अपरिहार्य है। इसके बिना आप सार्थक बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।' वहीं 28 अप्रैल 2025 को एक्ट्रेस सामंथा रूथ ने अपना जन्मदिन मनाया। फैंस ने भी सामंथा का जन्मदिन अलग-अलग ढंग से सेलिब्रेट किया। इसी बीच एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें सामंथा के एक फैन द्वारा बनाया गया एक्ट्रेस का मंदिर चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक्ट्रेस सामंथा का मंदिर दिख रहा है। इसी मंदिर में फैन ने एक्ट्रेस का 38वां जन्मदिन मनाया।

वीडियो में दिख रहा है कि मंदिर के बाहर लिखा है, 'सामंथा का मंदिर'। अंदर जाने पर सामंथा की दो प्रतिमाएं दिखती हैं, इसमें से एक सुनहरे रंग की है। फैन ने सिर्फ एक्ट्रेस का मंदिर ही नहीं बनवाया है, इसके अलावा अनाथ बच्चों को पार्टी दी। अनाथ बच्चों के साथ सामंथा के बर्थ डे का केक भी काटा। जिस फैन ने यह मंदिर बनवाया है, उसका नाम तेनाली संदीप है। मीडिया से भी इस फैन ने बातचीत की। तेनाली कहता है, 'मैं आंध्र प्रदेश से हूं। मैं सामंथा का बहुत बड़ा फैन हूं। पिछले तीन सालों से उनका जन्मदिन मना रहा हूं। मैंने कुछ साल पहले ही यह मंदिर भी बनवाया था। हर साल मैं यह तय करता हूं कि सामंथा के जन्मदिन पर बच्चों को खाना खिलाऊं और केक काटूं। सामंथा ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है।' नागा चैतन्य से तलाक के बाद से ही समांथा रुथ प्रभु काफी ज्यादा चर्चा में रही हैं। तलाक से लेकर अपनी बीमारी और कई कारणों से चर्चा में रही है। जहां एक तरफ तलाक के बाद नागा चैतन्य ने शोभिता धुलिपाला के साथ अपना फिर से घर बसा लिया है वहीं समांथा रुथ प्रभु आज भी सिंगल है। काफी समय से फिल्म निर्माता राज निदिमोरू के साथ अभिनेत्री सामंथा का नाम जोड़ा जा रहा है। अभी हाल ही में सामंथा को एक बार फिर से राज निदिमोरू के साथ देखा गया। अभिनेत्री सामंथा ने शनिवार को आशीर्वाद लेने के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर का दौरा किया। उनके साथ फिल्म निर्माता राज निदिमोरू भी थे। उनके दौरे के वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं, जिसमें दोनों पारंपरिक परिधानों में मंदिर परिसर में दिखाई दे रहे हैं। सामंथा अक्सर दिव्य आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में जाती हैं। 19 अप्रैल को, कुशी अभिनेता को गुलाबी सलवार सूट और राज को नीली शर्ट और सफेद पंचा में दिखाते हुए कुछ वीडियो पपराज़ी द्वारा साझा किए गए थे। एक क्लिप में, दोनों को एक साथ मंदिर में प्रवेश करते देखा जा सकता है, जबकि सामंथा किसी का इंतजार करते हुए रुकी हुई हैं। एक अलग वीडियो में सामंथा को कई अन्य लोगों के साथ मंदिर में प्रवेश करते हुए दिखाया गया।

हालाँकि न तो सामंथा और न ही राज निदिमोरू ने अपनी डेटिंग अफवाहों के बारे में कोई आधिकारिक बयान दिया है, लेकिन उनके प्रशंसक लंबे समय से अटकलें लगा रहे हैं। अभिनेता पहले ही निर्देशक के साथ दो प्रोजेक्ट - सिटाडेल : हनी बनी (2024), और द फैमिली मैन 2 (2021) पर काम कर चुके हैं। उनकी अगली नेटफ्लिक्स सीरीज, जिसका शीर्षक 'रक्त ब्रह्मांड : द ब्लडी किंगडम' है, भी निर्देशक के साथ है। सामंथा को आखिरी बार सिटाडेल : हनी बनी में देखा गया था, जिसमें उनके साथ वरुण धवन भी थे। इससे पहले अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु ने हाल ही में पिकलबॉल के साथ खेल की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। **:: नेशनल डेस्क**

सामंथा ने कहा, मुझे लगता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को महिलाओं के नजरिए की ज्यादा जरूरत है। फिल्मों में महिलाओं की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण को ज्यादा जगह मिलनी चाहिए। अभी भी इंडस्ट्री में पुरुषों का दबदबा बहुत ज्यादा है। मैं यह बात नकारात्मक रूप में नहीं कह रही हूं, बल्कि बस एक सच्चाई को सामने रख रही हूं।

कियारा आडवाणी ने कॉउचर में बेबी बंप किया फ्लॉन्ट

कियारा आडवाणी ने न्यूयॉर्क शहर के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित मेट गाला में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई और अपने लुक से प्रशंसकों का दिल जीत लिया। उन्होंने मेट गाला के ब्लू कार्पेट के लिए एक खूबसूरत लुक चुना। 2025 मेट गाला के लिए, थीम सुपरफाइन~टेलरिंग ब्लैक स्टाइल, कॉउचरियर गौरव गुप्ता ने कियारा आडवाणी द्वारा पहना गया एक कस्टम कॉउचर क्रिएशन ब्रेवहार्ट्स का अनावरण किया। मातृत्व की यात्रा से पहले डिज़ाइन किया गया, मूर्तिकला लुक एक व्यक्तिगत मील का पत्थर और पहचान और वंश पर एक गहरा बयान दोनों है। मातृत्व और गाला की थीम को समर्पित अपने लुक के बारे में बात करते हुए कियारा ने कहा, एक कलाकार और एक माँ के रूप में अपने जीवन के इस मोड़ पर मेट गाला में पदार्पण करना अविश्वसनीय रूप से विशेष है। जब मेरी स्टाइलिस्ट, अनाइता ने मेरा लुक डिज़ाइन करने के लिए गौरव से संपर्क किया, तो उन्होंने ब्रेवहार्ट्स बनाया, जो एक ऐसा विज़न है जो उस परिवर्तनकारी चरण का सम्मान करता है जिसमें मैं कदम रख रही हूँ और इसे इस साल के ड्रेस कोड टेलर्ड फॉर यू से खूबसूरती से जोड़ता है। एंड्रे लियोन टैली की विरासत से प्रेरित होकर, हमने इस बात पर विचार किया कि इरादे, व्यक्तित्व और ताकत के साथ दिखने का क्या मतलब है। यह उसी के लिए एक मौन श्रद्धांजलि है - यह एक अनुस्मारक है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह अगली पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा भले ही पत्नी कियारा आडवाणी के साथ मेट गाला 2025 के रेड कार्पेट पर नहीं चले, लेकिन वे हर कदम पर उनका साथ देते हुए उनके साथ थे। उन्हें कियारा को लॉबी तक ले जाते हुए देखा गया, जो अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, और युगल को हाथों में हाथ डाले चलते हुए देखा गया। कॉउटियर गौरव गुप्ता कहते हैं, ब्रेवहार्ट्स भावनात्मक, शारीरिक और पीढ़ीगत बदलाव के बारे में है। कियारा के लिए यह पीस बनाते हुए, हम उसकी मातृत्व का सम्मान करना चाहते थे और ब्लैक स्टाइल की बोल्ड भव्यता को श्रद्धांजलि देना चाहते थे। यह लुक महाद्वीपों और इतिहासों को जोड़ता है, जो ब्लैक डैंडीज्म के कट्टरपंथी परिष्कार के साथ एक गहरी प्रतीकात्मकता को मिलाता है। कियारा आडवाणी ने कहा, एक कलाकार और माँ बनने वाली महिला के रूप में, अपने जीवन के इस मोड़ पर मेट गाला में पदार्पण करना अविश्वसनीय रूप से विशेष अनुभव है। जब मेरी स्टाइलिस्ट, अनाइता श्रॉफ अदजानिया ने मेरा लुक डिज़ाइन करने के लिए गौरव से संपर्क किया, तो उन्होंने ब्रेवहार्ट्स बनाया, जो एक ऐसा विज़न है जो मेरे द्वारा शुरू किए जा रहे परिवर्तनकारी चरण का सम्मान करता है, इसे इस साल के ड्रेस कोड टेलर्ड फॉर यू से खूबसूरती से जोड़ता है। आंद्रे लियोन टैली की विरासत से प्रेरित होकर, हमने इस बात पर विचार किया कि इरादे, व्यक्तित्व और ताकत के साथ सामने आने का क्या मतलब है। यह उसी के लिए एक मौन श्रद्धांजलि है - यह एक अनुस्मारक है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह अगली पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यह गाउन सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट अनाइता के सहयोग से बनाया गया था, जिन्होंने इस विज़न को जीवंत करने के लिए गौरव और कियारा के बीच रचनात्मक आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की। **:: एजेंसी**

मेरी मम्मी ज्यादा टिप नहीं देतीं : पलक तिवारी

संजय दत्त की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द भूतनी 1 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में सनी सिंह, पलक तिवारी, मौनी रॉय और आसिफ खान , संजय दत्त के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आ रहे हैं और इस फिल्म का निर्देशन किया है सिद्धांत सचदेव ने। द भूतनी में संजय और मौनी पहली बार एक साथ नजर आए है और इसकी कहानी कॉलेज में एक आत्मा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हर वैलेंटाइन डे पर जागती है। पलक ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से ज्यादा मेरा हमारे डायरेक्टर सिद्धांत सचदेव से मिलना बहुत जरूरी था। ये फिल्म डेढ़ साल पहले शूट हुई थी लेकिन रिलीज अब हुई वीएफएक्स के कारण। वैसे तो ये उनका भी फर्स्ट प्रोजेक्ट है डायरेक्शन डेब्यू किया है उन्होंने इस फिल्म से लेकिन वो बहुत काम कर चुके हैं। एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने कई फिल्में की हैं तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन एक बात ये भी है कि एक डायरेक्टर होना सिर्फलोगों को शूट करना नहीं होता, डायरेक्टर के काम में बहुत गहराइयां होती हैं। एक्टर को समझना डायरेक्टर को जरूरी है फिर ये भी जरूरी है कि एक्टर उस किरदार को समझे। हमारे लिए ये शायद इसलिए भी ज्यादा आसान हो गया क्यूंकि सिद्धांत सचदेव ने ये फिल्म लिखी भी है। तो वो अपने किरदारों को जानते थे। पता नहीं उन्होंने मुझे देख कर समझ लिया लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे अच्छा करने के लिए प्रेरित किया है वैसे मुझे आज तक किसी ने पुश नहीं किया। **:: एजेंसी**

हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या को रखा जाता है वट सावित्री व्रत

सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत खासतौर पर विवाहित महिलाएं करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियमपूर्वक करने से पति की आयु लंबी होती है और दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत पौराणिक कथा सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम और दृढ़ संकल्प की याद दिलाता है, जिसमें सावित्री ने अपने पति को यमराज से भी वापस लाने का साहस दिखाया था। पंचांग के अनुसार, वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। साल 2025 में यह तिथि 26 मई दिन सोमवार को है। अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 को दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से, अमावस्या तिथि का समापन 27 मई 2025 को रात 8 बजकर 31 मिनट पर। उदयातिथि (सूर्योदय की तिथि) के अनुसार व्रत 26 मई को ही रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त (सुबह जल्दी) में उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा करें। सूर्य देव को जल चढ़ाएं (अर्घ्य दें)। व्रती महिलाएं (जो व्रत रख रही हैं) श्रृंगार करें। वट वृक्ष (बड़ के पेड़) के नीचे जाएं और वहाँ पहले सफाई करें। पूजा की जगह पर दीपक, अगरबत्ती जलाएं। **:: एजेंसी**

चेहरे पर आते बालों की ग्रोथ होगी कम, ट्राई करें ये असरदार टिप्स

चेहरे पर अनचाहे बालों का आना महिलाओं के लिए चिंता और शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। यह न सिर्फ सौंदर्य को प्रभावित करता है बल्कि आत्मविश्वास भी कम कर सकता है। खासतौर पर होंठों के ऊपर, ठुड्डी, गाल और माथे पर जब बाल ज्यादा दिखते हैं तो उन्हें बार-बार हटाना मुश्किल हो जाता है।

हालांकि बाजार में इससे छुटकारा पाने के लिए कई उत्पाद और ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप प्राकृतिक और सुरक्षित उपायों की तलाश में हैं, तो कुछ घरेलू नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि चेहरे पर फेशियल हेयर क्यों आते हैं।

इसके कई कारण हो सकते हैं। महिलाओं के शरीर में सामान्य रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन ज्यादा होते हैं, लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन (जो कि पुरुष हार्मोन होता है) का स्तर बढ़ने लगता है, तो वह शरीर पर पुरुषों जैसे लक्षण उत्पन्न करने लगता है। इससे आवाज भारी होना, पीरियड्स में अनियमितता और चेहरे पर बाल आना शामिल हो सकता है। यह स्थिति हिर्सूटिज्म कहलाती है, जिसमें महिला के चेहरे, सीने, पीठ और पेट जैसे हिस्सों पर मोटे और काले बाल आने लगते हैं। यह हार्मोनल बदलाव थायरॉइड की गड़बड़ी, स्ट्रेस, या कुछ दवाइयों के कारण भी हो सकता है।

पीसीआएस एक आम स्त्री रोग है जो आजकल बहुत सी महिलाओं में देखने को मिल रहा है। इस स्थिति में ओवरीज में छोटे-छोटे सिस्ट बन जाते हैं और शरीर में एंड्रोजन (पुरुष हार्मोन) का स्तर बढ़ जाता है। यही हार्मोन फेशियल हेयर ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं। पीसीओएस की वजह से महिलाओं को अनियमित पीरियड्स, मुंहासे, वजन बढ़ना, और बाल झड़ने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर इसका सही समय पर इलाज न किया जाए, तो यह भविष्य में बांझपन का कारण भी बन सकता है। इस कारण से चेहरे पर बार बार बाल हटवाने के बावजूद उनका उगना जारी रहता है। कई बार चेहरे पर अनचाहे बालों का आना किसी बीमारी या हार्मोनल बदलाव के कारण नहीं बल्कि परिवारिक प्रवृत्ति की वजह से होता है। अगर आपकी मां, बहन या नानी-दादी को चेहरे पर ज्यादा बाल आते थे, तो यह संभावना है कि आपको भी यही समस्या हो सकती है। **:: एजेंसी**

प्रथम पृष्ठ का शेष समाचार

बाबा साहेब के

और ओपन एयर जिम तथा सड़कों के निर्माण के लिए प्रयास करने हेतु आश्वस्त किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व केन्द्रीय मंत्री कौशल किशोर, अनुसूचित जाति - जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विश्वनाथ, डॉ. अजय गुप्ता, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि शिशिर यादव, वीरेंद्र रावत, नीलम श्रीवास्तव, विमला देवी, शंकरी सिंह, पूर्व ब्लाक प्रमुख कुंवर राम विलास व अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे।

आईओसी की टिप्पणी

किया गया ओआईसी का बयान पहलगाम आतंकवादी हमले और इसके सीमा पार संबंधों के तथ्यों को स्वीकार करने से इनकार करने में बेतुका है। उन्होंने कहा, यह पाकिस्तान द्वारा एक और प्रयास है, जो एक ऐसा देश है जो लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद में लिप्त है, ताकि वह ओआईसी समूह को गुमराह करके स्वार्थी बयान जारी कर सके।

योगी कैबिनेट ने

वर्ष के बाद ही हो सकेगा। विनियामक प्राधिकरण के पास ऑपरेटर को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद कुछ परिस्थितियों में प्राधिकरण को निलंबित या रद्द करने की शक्ति भी होगी। खन्ना ने बताया कि विनियामक प्राधिकरण के किसी भी आदेश के विरुद्ध शिकायत के मामले में बस टर्मिनल ऑपरेटर संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है जो नीति के तहत अपीलीय प्राधिकरण के रूप में काम करेगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे।

टूरिस्ट बस पार्क की होगी स्थापना : योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूर्स्ट बस पार्क स्थापना एवं विनियमन नीति-2025 को भी मंजूर कर लिया है। इससे प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नीति के अंतर्गत प्रदेश भर में बस अड्डों,पार्कों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगा। उनके द्वारा स्टेड कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट पार्क नियामक प्राधिकारी का गठन किया जाएगा। नीति के अंतर्गत स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना के लिए कम से कम 2 एकड़ भूमि होने तथा आवेदक की एनुअल नेटवर्थ कम से कम 50 लाख व टर्नओवर 2 करोड़ रुपए प्राविधानित है। आवेदन इंडीविजुअल व कंसोर्टियम के रूप में हो सकेंगे। किसी एक आवेदक को प्रदेश में 10 से अधिक, एक जिले में 2 से अधिक और एक ही मार्ग पर 1 से अधिक बस अड्डा व टूरिस्ट बस पार्क स्थापित करने की अनुमति नहीं मिलेगी। निजी निवेश से स्थापना पर संचालन के लिए पहली बार 10 वर्षों के लिए अनुमति दी जाएगी जिसका आगे 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण हो सकता है। स्वामित्व का हस्तांतरण 1 वर्ष के पहले नहीं किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण, निजी वाहनों की संख्या बढ़ने तथा पार्किंग की मांग को पूरा करने के लिए सभी 17 नगर निगमों में पीपीपी माडल आधारित व्यवस्था संचालित करने के लिए उ.प्र. नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण एवं प्रचालन) नियमावली 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रथम चरण में नियमावली के तहत प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी। सभी पार्किंग स्थलों में तकनीकी आधारित स्मार्ट व्यवस्था की सुविधा मिलेगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मंगलवार को लोकभवन के मीडिया सेंटर में प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरों में पार्किंग स्थलों की कमी के कारण लोग अपने वाहनों को सड़क के किनारे, फुटपाथों व खाली स्थलों पर अनियोजित ढंग से पार्क कर देते हैं। जिससे शहरों में टैअफिक की समस्या, एक्सीडेंट की संभावना तथा शहरों में अक्सर जाम लगने व वाहनों में तोड़ फोड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। पार्किंग की व्यवस्था होने से लोगों को इन सभी समस्याओं से निजात मिलेगी। साथ ही निगमों को भी अपने राजस्व में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सभी पार्किंग स्थलों में आईटी आधारित मल्टीलेबल की व्यवस्था की जायेगी। सार्वजनिक परिवहन के संसाधनों को और बढ़ाया जायेगा। अच्छी व्यवस्थायें लोगों को प्रदान की जायेगी। पार्किंग स्थलों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग की व्यवस्था की जायेगी, साथ ही गाड़ियों की धुलाई, सफाई और टायरों में हवा भरने आदि की भी व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी पार्किंग स्थलों को पीपीपी के माध्यम से निगरानी एवं व्यवस्थापन के लिए प्रबंधकीय समिति बनाई जायेगी। जो पार्किंग जगहों का सीमांकन कर चिन्हित करेगी और निजी संस्थान इन स्थलों को विकसित करेंगे। दरों को तय करने के लिए बिडिंग भी की जायेगी और निजी संस्थानों से निगरानी एवं व्यवस्थापन के लिए पांच वर्ष का अनुबंध किया जायेगा। इससे लोगों को सुगम पार्किंग की सुविधा मिलेगी और एक समान पार्किंग शुल्क होने से लोगों का शोषण भी नहीं हो पायेगा तथा पार्किंग शुल्क से होने वाली आय से शहरों का नियोजित विकास भी हो सकेगा।

एक ही जिले

ख के अधिकतम 20 प्रतिशत अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। समूह ग व घ के कार्मिकों का अधिकतम 10 प्रतिशत तबादला होगा। उन्होंने बताया कि विभागाध्यक्ष, मंडलीय कार्यालयों में की गई तैनाती की अवधि को स्थानांतरण के लिए उक्त निर्धारित अवधि में नहीं गिना जाएगा। मंडलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी तथा इसमें सबसे ज्यादा समय से कार्यरत पुराने अधिकारियों के तबादले प्राथमिकता के आधार किए जाएंगे। तबादला नीति के अनुसार स्थानांतरण किये जाने के लिए अवधि के निर्धारण के लिए कट-आफ-तिथि 31 मार्च, 2025 मानी जाएगी। समूह ग के कर्मचारियों का जिला परिवर्तन न होने की स्थिति में पटल परिवर्तन अवश्य किया जाएगा। यह अधिकतम 10 प्रतिशत किया जाएगा। समूह ग व घ के 10 प्रतिशत से अधिक तबादले करने के लिए विभागीय मंत्री से अनुमोदन लेना होगा। समूह ख एवं समूह ग के अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण यथासंभव मेरिट आधार पर आनलाइन किए जाएंगे। समूह क के अधिकारियों का उनके गृह जनपद में तबादला नहीं होगा। पूर्णतया दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाएगी जहां उनकी देखभाल व चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो। प्रदेश के आकांक्षी जिले चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती व बहराइच एवं 100 आकांक्षी विकासखंडों में प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में समस्त पदों पर शत-प्रतिशत तैनाती की जाएगी। आकांक्षी जिलों व विकासखंडों में दो वर्ष से तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। स्थानांतरण सत्र यानी 15 जून के बाद समूह क के साथ ही साथ समूह ख के संबंध में विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही तबादले हो सकेंगे। तबादला आदेश में कर्मियों के अवमुक्त करने की तिथि या फिर एक सप्ताह के अंदर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बगैर कार्यमुक्त किए जाएंगे।

अदाणी पावर लिमिटेड

किया गया है। उसके द्वारा प्रस्तुत दर सबसे कम 5.383 रुपये रही। शर्मा ने बताया कि राज्य को अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2033-34 तक अतिरिक्त 10,795 मेगावाट ताप बिजली की जरूरत होगी। उन्होंने बताया कि निविदा प्रक्रिया में अदाणी पावर लिमिटेड सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी।

ग्लोबल सेवा का

डेवलपमेंट, साइबर सुरक्षा, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आते हैं। इंजीनियरिंग डिजाइन का बहुत सारा एलीमेंट है जो बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है और हम काफी सस्ते दामों में और उच्च गुणवत्ता के साथ इस काम को कर सकते हैं। इसी प्रकार से बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे काम आउटसोर्स करने के लिए मल्टीनेशन कंपनियां भारत आ रही हैं। इसी तरह, ऑटोमोटिव सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण सेक्टर की भी बहुत सारी कंपनियां यहां आई हैं। उनके सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का बहुत सारा काम इन जीसीसी में होगा। उन्होंने बताया कि आज भारत में लगभग 1700 जीसीसी हैं और इनके तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट ने 10 हजार सीटर डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया है।

भारत ने जारी

के लिए आवश्यक जानकारी दी जाती है। NOTAM का अर्थ होता है कि नोटिस टू एयरमैन। ये एक ऐसा नोटिस है जो हवाई यात्रियों को हवाई अड्डों, हवाई क्षेत्रों और हवाई मार्ग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्शाता है। तत्काल उड़ान के लिए इससे जानना आवश्यक होता है।

मुख्यमन्त्री योगी से

कराकर उसकी मरम्मत एवं साज-सज्जा कराई जाए ताकि द्वक्तोटो जर्नलिस्ट उक्त कक्षा का संक्षिप्त सदुपयोग कर सकें।इसके राज्य संपति विभाग के रिक्त करीब तीन दर्जन से अधिक आवासों को सम्मानित पत्रकारों को आवंटित करने की बात की गयी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री से मिलने वालों में वरिष्ठ पत्रकार गण बृजनन्दन राजू ने मुख्यमंत्री को स्वलिखित जनता सर्वोपरि और श्वर्णिम भारतश्की ओर पुस्तक भेंट की। प्रतिनिधि मण्डल में भारत सिंह के नेतृत्व में सर्वेश सिंह, बृजनन्दन राजू, पदमाकर पाण्डेय, अरूणव सिन्हा, अनूप चतुर्वेदी, अशोक मिश्रा, सुरेश सिंह, डा. सत्येन्द्र त्रिपाठी, आशीष मौर्य और अनूप मिश्र मुख्यमंत्री से मिले।

मॉक ड्रिल में

का निर्देश दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि देश के 259 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इससे पहले साल 1971 में ये ड्रिल आयोजित हुई थी। इस दौरान पूरी तरह से ब्लैक आउट किया जाता है और सायरन बजाते हैं। ब्लैकआउट के समय देश के सभी ऑफिस, घरों और दफ्तरों की लाइटें बंद कर जाती और इसी के साथ तेज आवाज में सायरन बजाया जाता है। इस आवाज को सुनकर लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपना होता है। इस मॉक ड्रिल का मकसद लोगों को संकट के समय के लिए तैयार करना है।

मॉक ड्रिल को

सूचना शहर के केंद्रों तक भेजा जाता है जहां जमीनी कार्रवाई शुरू होती है- वायुसेना सूचना को एक बड़े नक्शे पर अंकित करती है और रक्षात्मक जवाबी कार्रवाई की योजना बनाती है। पहला हवाई हमला संदेश - येलो- यह प्रारंभिक एवं गोपनीय संदेश है। यह दुश्मन के विमान की गतिविधि का पूर्वानुमान है। यह संदेश प्राप्त होने पर, नागरिक सुरक्षा सेवाओं को बिना किसी बाधा के आवागमन के लिए तैयार रहना चाहिए। लोग न घबराएं इसलिए इस चेतावनी को गोपनीय रखा जाता है। दूसरा अलर्ट हवाई हमला मैसेज-रेड-रेड का संकेत होता है कि दुश्मन के विमान कुछ शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही मिनटों में हमला हो सकता है। यह संदेश मैसेज सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों को भेजकर कार्रवाई करने को कहा जाता है। हवाई हमलों के दौरान आम लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना अहम होता है। इसमें आम लोगों और छात्रों की ट्रेनिंग के साथ-साथ सिविल डिफेंस की अहम भूमिका होती है। इस चेतावनी के बाद सायरन के माध्यम से सार्वजनिक चेतावनी जारी किए जाने की जाती है। तीसरा अलर्ट एयर रेड मैसेज - ग्रीन- इस अलर्ट का मतलब है कि हमलावर विमान शहरों से चले गए हैं या अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। चौथा अलर्ट है एयर रेड मैसेज-व्हाइट-यह अलर्ट एयर रेड मैसेज-व्हाइट तब भेजा जाता है जब एयर रेड मैसेज-येलो में चेतावनी दी गई प्रारंभिक धमकी का समय बीत जाता है। इस प्रकार का अलर्ट भी गोपनीय होता है।

भारत के हक

कानून में संशोधन किए जो गरीब मुसलमानों पसमांदा मुसलमानों के काम आएगा। दशकों तक हमारे नदियों के पानी को तनाव का विषय बना कर रखा। हमारी सरकार ने नदियों को जोड़ने का काम किया। पाकिस्तान से सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के बाद जारी तनाव के बीच पीएम मोदी ने कहा, आजकल मीडिया में पानी को लेकर काफी चर्चा चल रही है। पहले भारत के हक का पानी बाहर जा रहा था, आज भारत का पानी भारत के हक में ही बहेगा, भारत के काम आएगा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजय शंकर शर्मा द्वारा ग्रुप 5 प्रकाशन 55-बी, वजीर हसन रोड, लखनऊ से मुद्रित एवं डी-206-सी, विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ से प्रकाशित। सम्पादक- विजय शंकर शर्मा
(M.)- 9628478339, 9335322739 Ph: 0522- 4075237 Fax: 0522- 2306048 Email- charchitrajnit@gmail.com

योगी के जनता दर्शन में पहुंचे अन्य राज्यों के भी फरियादी

समाधान मिलने पर खिले चेहरे, मुख्यमन्त्री योगी को धन्यवाद देने भी पहुंचे

चर्चित राजनीति। ब्यूरो

लखनऊ। हैलो, मैं मुख्यमंत्री कार्यालय से बोल रहा हूं। आपके प्रदेश के एक नागरिक अपनी समस्या लेकर यहां आए हैं। यह आपसे मिलेंगे। कृपया इनकी समस्या का समाधान कराने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के अधिकारियों के पास प्रायः ऐसे फोन यहां से किए जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'जनता दर्शन' में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के पीड़ित भी निरंतर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन में हर पीड़ित के पास स्वयं पहुंचते हैं। उनकी समस्या सुनते हैं और निराकरण के लिए संबंधित राज्य से संपर्क स्थापित करने का आदेश अपने कार्यालय को देते हैं। अक्टूबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच यूपी के बाहर के 65 फरियादी जनता दर्शन व प्रवास के दौरान योगी आदित्यनाथ से मिले। इन सभी की शिकायत उनके गृहराज्य के आलाधिकारियों तक पहुंचाई गई। जनता दर्शन नजीर बन गया है। अन्य राज्यों के नागरिक भी मानते हैं योगी हैं तो यकीन है। समाधान पाकर खिले चेहरे सीएम योगी का धन्यवाद करने भी आते हैं।

उत्तर प्रदेश के पीड़ितों की समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय-समय पर जनता दर्शन करते हैं। वे पीड़ितों की समस्या को सुनते हैं और निराकरण कराते हैं। प्रार्थना पत्रों पर सीएम योगी की कार्रवाई नजीर बनती है। योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर समय समय पर स्वयं जनता दर्शन करते हैं। गोरखपुर प्रवास के दौरान प्रतिदिन जनता से मुखातिब होते हैं। उनकी दिनचर्या ही जनता से मिलने से प्रारंभ होती है। पिछले साढ़े छह महीने में बिहार, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम समेत कई राज्यों के 65 फरियादी जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री ने इनकी समस्याएं सुनीं और समाधान के लिए संबंधित राज्यों तक इसे प्रेषित कराया। योगी आदित्यनाथ फरवरी के प्रथम सप्ताह में उत्तराखंड दौरे पर गए थे। वहां पौड़ी गढ़वाल के विथ्याणी गांव के पूर्व सैनिक महेंद्र सिंह नेगी ने सीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा।

ठांगर ग्राम पंचायत में एएनएम सेंटर के उच्चीकरण संबंधी पत्र भी सीएम को सौंपा गया। उत्तराखंड की ही रुचि ने चिकित्सा संबंधी आर्थिक सहायता की गुहार लगाते हुए सीएम योगी को पत्र सौंपा। यमकेश्वर विकास खंड के एक मंदिर समिति के अध्यक्ष रूपचंद्र लखेड़ा ने सीएम योगी को सड़क निर्माण कराने के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा। सीएम ने सभी प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड

● फरियादियों को है योगी पर पूरा भरोसा

प्रशासन को पत्र प्रेषित कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का आग्रह किया। सीएम योगी के पास फीस माफी, चिकित्सा, पुलिस, पढ़ाई में मदद, मंदिर निर्माण, पैतृक विवाद संबंधी कई फरियाद पहुंची। मध्य प्रदेश के सीधी के राजगढ़ कोठार की प्रीतू साहू ने गंभीर बीमारी के इलाज के लिए गुहार लगाई।

बिहार के पश्चिमी चंपारण के माधोपुर प्रखंड की प्रियम प्रीति ने राहत कोष से सहायता राशि दिलाने का अनुरोध किया। ओडिशा, बिहार से मंदिर जीर्णोद्धार, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों से भी आए लोगों की शिकायतों को सीएम योगी ने सुना। छात्रा निष्ठा साहनी ने राजस्थान में फीस माफी के लिए भी गुहार लगाई।

योगी सरकार का संभव अभियान से बच्चों के पोषण स्तर में हुआ सुधार, बाल कुपोषण और भुखमरी दूर करने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य से भुखमरी, बाल कुपोषण को दूर करने और सतत खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में प्रतिबद्ध है। सतत विकास के इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीएम योगी के मार्गदर्शन में वर्ष 2021 में संभव अभियान की शुरुआत की गई थी जिसके 4 चरणों पूरे हो चुके हैं, यूपी ने 2024 में मातृ-शिशु पोषण के स्तर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के गंभीर तीव्र कुपोषित सैम बच्चों में से 65 प्रतिशत सामान्य स्थिति में आ चुके हैं।

16 प्रतिशत बच्चे सैम स्थिति से मध्यम तीव्र कुपोषित मैम बच्चों की स्थिति में आ चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार संभव अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आकांक्षात्मक जिलों में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, जिसे आने वाले समय में पूरे प्रदेश में चलाने की तैयारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश से कुपोषण और भुखमरी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ वर्ष 2021 में संभव अभियान की शुरूआत की थी। जिसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य-2 को प्राप्त करना और प्रदेश में सतत खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना था।

प्रदेश के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने संभव अभियान के चार चरणों की सफलता की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश ने संभव अभियान के तहत आपेक्षित सफलता प्राप्त की है। एक ओर इन चार वर्षों में तकनीकि नवाचार, प्रशिक्षण और सटीक निगरानी कर 1.7 करोड़ बच्चों की जांच की गई, जिसमें 1.8 लाख तीव्र कुपोषित बच्चों सैम के मामले दर्ज हुए थे, जिसमें 65 प्रतिशत सैम मामले साल के अंत तक सामान्य स्थिति में आ चुके हैं। जबकि 16 प्रतिशत मामले सैम स्थिति से मध्यम तीव्र कुपोषित मैम में आ चुके हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भवती महिलाओं की मेजरिंग इफिशियंसी 6 प्रतिशत से बढ़कर 51 प्रतिशत हो चुकी है। प्रदेश के 8 आकाक्षांत्मक जिलों में भी संभव अभियान ने सकारात्मक असर दिखाया है। संभव अभियान के सफल संचालन का असर है कि आकाक्षांत्मक जिलों के बच्चों में स्टंटिग, अंडरवेट और वेस्टिंग के मामलों में सुधार आया है लेकिन इन जिलों में अभी बच्चों में कुपोषण की स्थिति को देखते हुए, सीएम के निर्देश के अनुसार में इन जिलों में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।

3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को टेक होम राशन के माध्यम से पौष्टिक स्वल्पाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसमें प्रतिदिन लक्षित बच्चों को 400 कैलोरी एवं 15-20 ग्राम प्रोटीन दिया जा रहा है। समय-समय पर आंगनबाड़ी कार्यकत्री बच्चों के पोषण स्तर की जानकारी एकत्रित करती हैं।

सीएम योगी ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को आगामी वर्षों में पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिये हैं। जिसको लेकर प्रदेश का बाल सेवा विकास एवं पुष्टाहार विभाग कार्ययोजना तैयार कर रहा है, जल्द ही ये अभियान प्रदेश स्तर पर चलाया जाएगा।

देश-विदेश डायरी

तेज रफ्तार ने छीनी 12 जिंदगियां, बस पलटी और मच गया कोहराम, लाशों के बीच मची चीखपुकार

सुमात्रा, एजेंसी। इंडोनेशिया से एक दुखद खबर सामने आई है। आज पश्चिमी सुमात्रा प्रांत के पदांग पंजांग शहर में एक भीषण बस हादसा हुआ। यात्रियों से खचाखच भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई जिससे उसमें सवार 12 लोगों की जान चली गई जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस दर्दनाक हादसे में कुछ लोगों ने तो मौके पर ही अपनी जान गंवा दी जबकि कुछ अन्य ने अस्पताल ले जाते समय या अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। मृतकों में महिलाओं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं जिससे मातम का माहौल है। बस पलटने के इस भयानक हादसे में 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत दो अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक इनमें से कुछ लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यात्रियों से भरी यह बस काफी तेज गति से जा रही थी। इसी दौरान अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए। एक मोड़ पर जब ड्राइवर ने बस को मोड़ने की कोशिश की तो ब्रेक नहीं लगने के कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पलटने के बाद बस एक घर की बाउंड्री वॉल (फेंसिंग) से जा टकराई जिससे यह भीषण हादसा हुआ। स्थानीय पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा के महत्व को उजागर करती है।

बांग्लादेश में फिर हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास पर संकट, 4 नए गिरफ्तारी वारंट जारी

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश की अदालत ने मंगलवार को हिरासत में लिए गए हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास को चार और मामलों में मंगलवार को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसके एक दिन पहले अदालत ने हत्या के एक मामले में उनके खिलाफइसी तरह की कार्रवाई की थी। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस की खबर के अनुसार, चटगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसएम अलाउद्दीन महमूद ने 'वर्चुअल सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। इस्कॉन के पूर्व पदाधिकारी दास को पिछले साल 25 नवंबर को राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान को लेकर देशद्रोह के एक मामले में ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। चटगांव की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें अगले दिन जेल भेज दिया था। उनकी गिरफ्तारी को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और उनके अनुयायियों ने ढाका और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। सहायक लोक अभियोजक मोहम्मद रेहानुल वाजेद चौधरी के अनुसार, जिन चार मामलों में अदालत ने मंगलवार को कार्रवाई की उनमें कोतवाली पुलिस थाने में पुलिस के काम में बाधा डालना और वकीलों तथा न्याय चाहने वालों पर हमला शामिल है। समाचार पोर्टल बीडीन्यूज24 ने चौधरी के हवाले से कहा, ''अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें (दास को) गिरफ्तार दिखाने की याचिका स्वीकार कर ली। खबर में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि दास को उनकी 'सुरक्षा और समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुनवाई के लिए 'वर्चुअल माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया था। बीएसएस ने बताया कि 'वर्चुअल सुनवाई के मद्देनजर मंगलवार सुबह से ही चटगांव अदालत परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। चटगांव जेल के सामने भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अदालत ने सोमवार को सहायक सरकारी अभियोजक सैफुल इस्लाम अलिफकी हत्या के सिलसिले में दास की गिरफ्तारी का आदेश दिया जिसकी हिंदू नेता की गिरफ्तारी के बाद भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। उच्च न्यायालय की एक पीठ ने 30 अप्रैल को दास को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। लेकिन इस फैसले को अपीलीय डिवीजन के चौंबर न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेजाउल हक के समक्ष चुनौती दी गई जिन्होंने जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी।

पाकिस्तान सेना ने खाली किया बलूचिस्तान

नयी दिल्ली, एजेंसी। पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ तनाव के बीच बलूचिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की कोर की दो अहम इन्फेंट्री डिवीजन 33वीं और 41वीं बलूचिस्तान से हटाकर भारत की सीमाओं की ओर भेजी जा रही हैं। यह दोनों डिवीजन पाकिस्तान आर्मी की बलूचिस्तान में सुरक्षा और सैन्य ऑपरेशनों की रीढ़ मानी जाती थीं। सूत्रों के अनुसार, भारत से जंग के हालात के बीच पाकिस्तानी सेना ने इन दोनों डिवीजन को बलूचिस्तान से हटाकर पंजाब और सिंध की ओर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है, जिससे उन्हें भारत के साथ संभावित सीमा तनावों या युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके।

वित्तमंत्री ने की वीसी के जरिए कोषागारों की समीक्षा

लखनऊ, चसं। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रदेश के कोषागारों को निर्देश दिया है कि कोषागारो से पेंशन आहरित करने वाले ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने बैंक से किसी प्रकार का लोन लिया है उनकी पेंशन उनके खाते में भेजने से पहले प्रत्येक माह उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाए। लापरवाही न की जाए ऋणधारक पेंशनर्स से कुशलक्षेम जानने के उपरांत ही पेंशन का भुक्तान करें। वित्तमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कोषागारों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कोषागारों को निर्देश दिया है कि पेंशनर्स की शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करें।

मिट्टी की सेहत सुधारने को मंत्री सहित पूरा कृषि विभाग खेतों में उतरा

लखनऊ, चसं। प्रदेश के किसानों को खरीफसीजन की फसलों हेतु उनके खेतों से मृदा नमूनें एकत्रित कराकर प्रयोगशालाओं पर परीक्षण कराकर निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सोईल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी कार्यक्रम के खरीफमें क्रियान्वयन के लिये 5 मई को वृहद स्तर पर प्रदेश में मृदा नमूना संकलन अभियान संचालित किया गया है। प्रदेश के 826 विकासखण्डों से 20-20 ग्राम पंचायतों का चयन मृदा नमूना संकलन हेतु किया गया है, जिनमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से100 रेण्डम मृदा नमूनें संकलन हेतु क्षेत्रीय प्रसार कार्मिकों, प्रयोगशाला पर कार्यरत कार्मिकों, प्रशिक्षित कृषि सखियों को तैनात किया गया है।

'भारत-पाक युद्ध का बजा सायरन, जमीन पर लेट गए लोग'

लखनऊ, चसं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर लखनऊ में युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए सिविल डिफेंस द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास लखनऊ के पुलिस लाइंस में किया गया, जिसमें सायरन बजते ही लोग तुरंत फर्श पर लेट गए और दोनों हाथों से कान ढक लिए। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आम नागरिकों को यह सिखाना था कि युद्ध या आतंकी हमले की स्थिति में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। ड्रिल के दौरान गोलीबारी, विस्फोट और आग लगने जैसी घटनाओं के बीच सुरक्षित रहने की रणनीति पर प्रशिक्षकों ने जानकारी दी। ड्रिल में हिस्सा लेने वाले सिविलियंस को यह भी सिखाया गया कि घायल लोगों को प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाए और उन्हें सुरक्षित तरीके से अस्पताल तक कैसे पहुँचाया जाए। आग लगने पर उसे बुझाने की विधि और घायलों को विस्फोटों के बीच से सुरक्षित निकालने के उपाय भी सिखाए गए। गौरतलब है कि देश में इस प्रकार की मॉक ड्रिल पिछली बार 1971 में भारत-पाक युद्ध के समय हुई थी। यूपी डीजीपी ने जानकारी दी है कि कल यानि 7 मार्च को 19 जिलों के साथ-साथ पूरे उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल की जाएगी।

हर बूथ से भारत निर्माण की प्रेरणा : कार्यकर्ताओं को संगठन और विकास की संयुक्त जिम्मेदारी

चर्चित राजनीति। संवाददाता

लखनऊ। सरोजनीनगर के लोकप्रिय विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को खुशहालगंज मंडल के भाजपा पदाधिकारियों संग एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें न केवल स्थानीय विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई, बल्कि देश और प्रदेश में भाजपा द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुँचाने का भी आह्वान किया गया। मवई चौराहा स्थित मधुर मिलन गेस्ट हाउस में आयोजित 'खुशहालगंज मंडल पदाधिकारी सम्मेलन' में भाजपा के सभी मोर्चों के प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

बैठक में डॉ. सिंह ने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रहित और जनसेवा की भावना से प्रेरित होकर बूथ स्तर से आगे बढ़कर संगठन और विकास दोनों की धार को मजबूत करने का संदेश दिया।

फ्लैगशिप योजनाओं ने दिलाई सरोजनीनगर को राष्ट्रीय ख्याति : इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉ. राजेश्वर सिंह ने विधानसभा क्षेत्र में सीएसआर योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि अबतक स्थापित 152 तारा शक्ति केंद्र (सिलाई सेंटर) जिनके माध्यम से 3,000 से अधिक महिलाओं के जीवन में सार्थक बदलाव आया, प्रतिदिन 4,000 जरुरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने वाली ताराशक्ति निःशुल्क रसोई, अब तक स्थापित 13 रण बहादुर सिंह डिजिटल शिक्षा एवं सशक्तिकरण केंद्र जो हजारों युवाओं को ट्रेंडिंग डिजिटल कोर्सो का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार - स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। विधायक ने बताया इन फ्लैगशिप योजनाओं ने सरोजनी नगर को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाई है।

11 मई को होगा ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्रोजेक्ट व डिफेंस नोड का उद्घाटन : विधायक डॉ. सिंह ने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि 11 मई को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जी और मुख्यमंत्री जी भटगाँव में ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्रोजेक्ट व डिफेंस नोड का उद्घाटन करेंगे, ये प्रोजेक्ट सरोजनीनगर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। क्षेत्र के विकास कार्यो का उल्लेख करते हुए विधायक ने बताया कि ?492.34 करोड़ की लागत से विभिन्न नहरों की 11 क्षतिग्रस्त पटरियों का सुदृढ़ीकरण कराया गया, 183.95 करोड़ की लागत से शिवरी, लोनहा तथा तेज किशन खेड़ा में ग्रामीण हाट बाजार बनाये गये। किसानों को सुलभ हुए स्थानीय बाजार। 45 करोड़ की लागत से शिवरी स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट की क्षमता में वृद्धि से प्रतिदिन 5500 मैट्रिक टन कूड़े का निस्तारण कराया जा रहा है, ?117 करोड़ की लागत से 61 ग्राम पंचायतों में हर घर को नल से जल दिये जाने के लिए 45 परियोजनायें स्वीकृत कराई गयी। लतीफनगर में वर्षो से बंद पडे गर्ल्स डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए ?13.52 करोड़ की धनराशि दिलायी गयी। चकौली में स्थापित किया जाएगा फॉरेन लैंग्वेज विश्वविद्यालय। 40 एकड़ में नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में अत्याधुनिक AI सिटी बनेगी। 192 करो की लागत से अमौसी में वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज विकसित होगी। सुल्तानपुर रोड के समीप 360 एकड़ में अत्याधुनिक आईटी सिटी बनेगी,

● मंडल पदाधिकारी सम्मेलन : सशक्त समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए डॉ. राजेश्वर सिंह का वैचारिक मार्गदर्शन
● डॉ. राजेश्वर सिंह की विजनरी पहल : ताराशक्ति केन्द्रों ने बदला हजारों महिलाओं का जीवन, ताराशक्ति रसोई से 4000 को प्रतिदिन भोजन
● सरोजनीनगर में पूरे हुए ग्रामीण सड़कों के 1459 कार्य, सुगम आवागमन, व्यापार और शिक्षा के बढ़ रहे अवसर

75 हजार से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। डॉ. सिंह ने सरोजनी नगर में हुए विकास कार्यों से अवगत कराते हुए बताया कि पिछले करीब 3 वर्ष में ?4973 करोड़ की लागत से 1459 ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण के कार्य पूर्ण हुए, जिनसे ग्रामीण क्षेत्र में सुगम आवागमन, व्यापार और शिक्षा के अवसर बढ़ रहे हैं। आगरा एक्सप्रेस-वे से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए ?500 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई, लिंक एक्सप्रेस-वे बनेगा। विधायक ने बताया कलियाखेडा एवं प्यारेपुर में 6500 करोड़ की लागत से अनन्तनगर (मोहन रोड योजना) आवासीय परियोजना विकसित की जा रही है, जहाँ 20 हजार परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी। सरोजनी नगर में सोलर क्षमता की वृद्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए डॉ. सिंह ने कहा 45 मेगावाट सोलर उत्पादन हो रहा ह, सोलर ट्रीज़ और 1200 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगवाई गई।

विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत : विधायक ने कहा भारत जब सोने की चिड़िया कहा जाता था तब आक्रमणकारी आयें, आज ही भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारत 4.187 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था है। आज भारत में एफडीआई बढ़ रहा, गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है।

भारत की बढती आर्थिक ताकत के बीच विधायक ने राष्ट्रीय एकजुटता को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा सीएम योगी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सभी को एकजुट रहना है। डॉ. सिंह ने जनसांख्यिकी परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केरल में हिन्दू आबादी 14 फीसदी से अधिक कम हुई, यूपी में हिन्दुओं की आबादी 5 प्रतिशत घटी है। एक साथ चुनाव होने से लाखों करोड़ रुपयों की बचत होती है लेकिन विपक्षी दल जातिगत, तुष्टिकरण की राजनीति के चलते एक देश एक चुनाव का विरोध करते हैं। पहलगाम पर हुए हमले को अत्यंत दुखद बताते हुए विधायक ने कहा उरी और पुलवामा का जबाब दिया गया पहलगाम का भी करारा जबाब दिया जाएगा।

कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई विकास कार्यों की विवरणिका : मंडल पदाधिकारी सम्मेलन के दौरान सरोजनी नगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह की ओर से उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों के विकास कार्यों, युवाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण से सम्बंधित और अन्य विषयों से सम्बंधित विवरणिकायें (पैम्फलेट) भी उपलब्ध कराई गई। कार्यकर्ताओं को पैम्फलेट वितरित किये जाने का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए विधायक डॉ. सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं का दृष्टिकोण केवल अपने बूथ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उनके न केवल विधानसभा क्षेत्र बल्कि जिले और प्रदेश के विकास कार्यों से भी अवगत रहना चाहिए तभी वे जनता तक सही बात रख पायेंगे और विपक्ष के दुष्प्रचार को निष्प्रभावी बना सकेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष विजय मौर्या ने बताया विपक्ष सरकार को लेकर भ्रम पैदा करता है, सरकार की योजनओं के बारे में झूठ फैलाता है, ऐसे में विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह द्वारा योजनाओ की विवरणिका उपलब्ध कराने का कार्य अनुकरणीय और सराहनीय है। सम्मेलन के दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष आशीष द्विवेदी, पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी भारत मौर्या, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुनेन्द्र सिंह श्यामू, पूर्व जिला महामंत्री राजेन्द्र सिंह राजू, संजय सिंह, मुकेश सिंह, बाल कृष्ण द्विवेदी, गंगा राम भारती, रमा शंकर त्रिपाठी, शंकरी सिंह, राजेश सिंह चौहान, शिव बक्श सिंह, मनीष द्विवेदी, रागिनी कटारिया, दिनेश गुप्ता धर्मवीर यादव, धर्मेन्द्र सिंह, रश्मि गुप्ता, दल बहादुर सिंह, सुभाष मौर्या, महेंद्र सिंह तथा मंडल के सभी बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल मोर्चों के पदाधिकारी व अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे।